सी० आइ० ए०

पर्दे के पीछे

दलजीत सेन ग्रदल

प्रकाशक :
विजेन्द्र जैन
महासचिव, अखिल भारतीय विद्यार्थी कांग्रेस,
बी० ८६, रमेश नगर, नई दिल्ली-१५

मूल्य : पाँच रुपये
प्रथम संस्करण : पाँच हजार

मुद्रक :
पायनियर प्रिंटर्स,
२६१, फैज रोड, नई दिल्ली-५

प्रस्तावना

सी० आई० ए० का परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं। गुप्त रूप से काम करने वाली यह संस्था बहुत बदनाम हो चुकी है। यदि यह कहा जाये कि सी० आई० ए० ने एक प्रजातांत्रिक सरकार का तख्ता उल्ट दिया या एक पिट्ठू सरकार को गद्दी पर बिठा दिया तो यह आश्चर्य की बात नही होगी। चाहे एशिया हो या अफ्रीका या लतीनी अमरीका इस संस्था की घिनौना रूप अन्तर्राष्ट्रीय रंग मंच पर भी दिखाई देगा, कभी जनतन्त्र का खून करने मे, कभी प्रगतिशील नीतियों का विरोध करने में या फिर षडयन्त्रकारी गतिविधियों द्वारा आजादी का हनन करने में ताकि लोगों के समाजवाद की ओर बढ़ते हुए साहसिक कदम डगमगा उठें, देश का आर्थिक और सामाजिक विकास रुक जाए, और लोगों की इच्छाएं और आकांक्षाएं दबी की दबी रह जाए, इस दिशा में अमरीकी गुप्तचर संस्था सदैव अग्रणी रही है।

सी० आई० ए० उन क्षेत्रों में विद्यमान है जहा उपनिवेशवाद की जड़ें खोखली हो चुकी हैं और जहां प्रजातांत्रिक प्रणाली के आधार पर राजनैतिक ढांचे को सुदृढ़ बनाने का प्रयास जारी है। प्रजातन्त्र की आड लेकर यह संस्था पैसे और हथियारों का प्रलोभन देकर, जहां २ सम्भव हों सके, सैनिक अड्डे कायम करना

चाहती है ताकि विश्व में युद्ध के बादल मंडराते रहें और छोटे २ राष्ट्रों को विवश कर दिया जाए कि वे सैनिक गुटबन्दी का शिकार बने रहे।

सी० आई० ए० का मुख्य उद्देश्य है कि एकाधिकार बढे, पूजीवादी शक्तिया देश की आर्थिक नीति पर अपना प्रभुत्व जमा सकें और लगड़ा साम्राज्यवाद खड़ा रह सके। सी० आई० ए० एक विशुद्ध राजनैतिक सस्था ही नही बल्कि एक व्यापारिक सस्थान भी है। यह संस्था बड़े पैमाने पर षडयन्त्रकारी और विघटन सम्बन्धी कार्यो को बढ़ावा देती है। यह अलग बात है कि इस सस्था को हर स्थान पर मुह की खानी पड़ी है।

अमरीकी सरकार के विदेशी विभाग पर सी० आई० ए० का प्रभाव इतना अधिक बढ़ चुका है कि अमरीकी दूतावासो में सी० आई० ए० के अधिकारी प्रमुख स्थानो पर तैनात हैं। ये अधिकारी अवाछनीय कार्यो को बढावा देने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। ये अधिकारी किसी न किसी प्रकार विद्यार्थियों, युवकों और *नागरिकों से सम्बन्ध बढ़ाकर उन्हें विघटनकारी कार्यो के लिए तैयार करके* अपने ही देश के विरुद्ध कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं।

इण्डोनेशिया में भूतपूर्व राष्ट्रपति डाकटर सुकर्ण, ईरान के भूतपूर्व प्रधान मन्त्री डाकटर मुसद्दिक, घाना के भूतपूर्व राष्ट्रपति एनक्रूमा और कम्बोडिया के नारडोम सिहानुक के विरुद्ध षडयन्त्रों के पीछे सी० आई० ए० का हाथ था, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता। बन्दूकों और टैंकों के बलबूते पर अधिक देर तक साम्राज्यवादी शक्तियां नही टिक सकती भले ही सी० आई० ए० कोई रूप धारण करके सामने आए। उसकी मित्रता प्रतिक्रियावादियो से हो या साम्प्रदायिक तत्वो से, उसकी गोद में एकाधिकार पलता हो या तस्करी करने वाला व्यापारी, ये सब आजादी के दुश्मन हैं।

अतः आज़ादी के दीवानो को सजग और जागरुक रह कर अपने राष्ट्रीय गौरव, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा के लिए सतत् कार्यशील रहना चाहिये ताकि विध्वंसकारी और प्लायनवादी प्रवृत्तिया हमेशा के लिए कुचल दी जाएं। सी० आई० ए० का विरोध करने का मतलब है मानवीय मूल्यों का प्रतिपादन करना।

जहां लिकन ने अमरीका की स्वतन्त्रता और एकता को अपने जीवन का लक्ष्य माना वहा उन्होंने भारत की आजादी के लिए और विश्व के अन्य देशों को गुलामी

की जंजीरों से मुक्त कराने का भी प्रयास किया। भारतीय जनता को लिंकन की आज़ादी-प्रिय भावना से बहुत प्रेरणा मिली। यह सही है कि भारतीय स्वतन्त्रता सग्राम के सफल होने तक अमरीकी जनता हमारी आजादी की लड़ाई का समर्थन करती रही और भारत के कई प्रसिद्ध क्रांतिकारी अमरीका मे रहकर भारत की हर प्रकार से सहायता करते रहे और उन्हे अमरीकी जनता का सहयोग भी मिलता रहा। स्वामी विवेका नन्द को अमरीका में अध्यात्मवाद की चर्चा करने के साथ-साथ यह भी अवसर प्राप्त हुआ था कि वह अमरीकी लोगों मे भारत की आज़ादी के प्रति रुचि भी पैदा करते रहे थे। कौन नहीं जानता कि भारतीय क्रान्तिकारी जापानी जहाज़ 'कामा-गाटा-मारो' को जब अमेरिका से भारत लाए थे तो उस जहाज़ में लगभग ४०,००० रायफलें और लाखों रुपये का गोला बारुद मौजूद था। यह था उस समय की जनता और सरकार का आजादी के साथ प्रेम। क्या ही अच्छा होता कि हमारे दोनो देशो के बीच आज़ादी और मित्रता के आधार पर सम्बन्ध बने रहते और दोनो देश मिलकर साम्राज्यवाद का विरोध करते परन्तु अमरीकी सरकार रास्ते से भटक गई और सी० आई० ए० जैसी संस्थाओ ने अमरीका के पुराने इतिहास को मिट्टी मे मिला दिया और कुछ पूंजीपतियो के स्वार्थ की रक्षा के लिए छोटे छोटे राष्ट्रों का गला दबा दिया। आज अवस्था यह है कि अमरीका तथा लतीनी अमरीका मे अमीरी और गरीबी का भेद ज़मीन व आसमान की तरह बढ़ा है और इसके साथ-साथ काले और गोरे का अमानुषिक भेद भी बढा है। इस भेद भाव को बढाने में तथा इन्सान की इन्सान के खिलाफ़ नफ़रत को बढावा देने मे सी० आई० ए० शर्मनाक षडयन्त्र रचती रही है।

भारत मे सी० आई० ए० एक ओर तो दक्षिण पथी फासिस्टों की सहायता करती है जिन्होने गांधी जी की हत्या की, और दूसरी ओर उग्र वाम पंथी फासिस्टों की सहायता करती है जो गांधी जी के चित्रों की एवं देश की संस्कृति की होली जलाते हैं। एक ओर तो एक से बड़े-बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में साम्प्रदायिक दंगे कराए जाते हैं तो दूसरी ओर दूसरे से इन्ही औद्योगिक क्षेत्रों मे ताला बन्दी और हडताल कराई जाती है। देश की आर्थिक व्यवस्था को क्षीण बनाने के लिए ३०० करोड रुपये वार्षिक तस्करी सोने से भारतीय धरती पर आर्थिक हमला किया जाता है। इस प्रकार के 'सुनहरी हमलों' ने एशिया और अफ्रीका के कई छोटे-छोटे राष्ट्रो की आज़ादी का गला घोंटा है। अब एशिया और अफ्रीका की जनता सजग और जागरूक हो चुकी है इसलिए वह इस हमले का मुंहतोड़ जवाब दे सकती है। अतः

उनका मुकाबला करने की शक्ति बढे, यह किताब इस दिशा में सहायक हो, ऐसी मैं कामना करता हूं।

श्री दलजीत सेन अदल, जो एक अनुभवी कार्यकर्त्ता हैं, ने राष्ट्रीय भावनाओं से ओत प्रोत होकर विद्यार्थियों एव युवकों को चुनौती देते हुए कहा है कि 'सी० आई० ए० एक ऐसा घिनौना हथियार है जो स्वतन्त्रता-प्रिय देशो के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है' जिन लोगों को अपने देश से प्रेम है और जिनकी रगों में *स्वाभिमानी रक्त बहता है, और जो चान्दी के चन्द ठीकरो पर अपना ईमान नही* बेच सकते, उन सब लोगो को एक जुट हो कर सी० आई० ए० का विरोध करने के लिए यह पुस्तक आह्वान देती है।

नई दिल्ली। — शशि भूषण
२४ अक्तूबर, १९७० — ससद सदस्य

दो शब्द

न तो मैं अमरीका का विरोधी हूं न अमरीकन लोगों का। मैं अब्राहीम लिंकन को आज़ादी का देवता मानता हूं। इसलिए जब देखता हूं कि निकट भविष्य में दुनिया के नक्शे पर अमरीका का नाम आते ही जन-साधारण यह सोचने पर विवश हो जाएगा कि अमरीका आज़ादी का सरक्षक नही अपितु आजादी का शत्रु है तो मुझे आभास होने लगता है कि इस महान देश के माथे पर लगा हुआ कलुषित दाग कभी मिट न सकेगा।

अमरीका को इस प्रकार बदनाम करने की जिम्मेदारी सी० आई० ए० पर है जिसकी गतिविधियां किसी से छिपी हुई नही हैं। यह सही है कि अमरीकन सरकार की नीति का सब से तीव्र विरोध अमरीका में ही हुआ है, भले ही इस विरोध के उपलक्ष मे कई नवयुवकों को अपनी जिन्दगी से हाथ धोने पड़े हों।

भारतीय जनता स्वभाव से ही किसी भी देश के आन्तरिक मामलों में बाहरी हस्तक्षेप के हमेशा खिलाफ़ रही है इसलिए वे लोग जो शायद यह समझते हों कि सी० आई० ए० जैसी संस्थाओं के माध्यम से वे भारतीय जनता के विचारों मे

परिवर्तन ला सकते हैं, बिल्कुल धोखे में हैं। विदेशी टुकड़ों पर मनुष्य तो शायद पल जाए, राष्ट्र नहीं पल सकते। उसकी अपनी मर्यादा होती है और मानवीय मूल्यों में अटल आस्था भी। कोई भी देश इससे वंचित नहीं रखा जा सकता।

मुझे इस बात की खुशी है कि सी० आई० ए० के काले कारनामों का विरोध अमरीका में बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है और आम जनता को इस बात का पता लग गया है कि सी० आई० ए० षडयन्त्रकारियों का टोला है और यदि इस संस्था का अस्तित्व न मिटाया गया तो उस महान देश की मान मर्यादा मिट्टी में मिल जाएगी।

इसलिए आवश्यक है कि सी० आई० ए० का पर्दा फाश किया जाए और यह पुस्तक भी इसी दिशा में एक प्रयास है।

दलजीत सेन अदल

बी० ८६, रमेश नगर
नई दिल्ली–१५
२४ अक्तूबर, १९७०

अनुक्रमणिका

अनुक्रमणिका

विश्व के अन्य विद्यार्थियो की भाति अमेरिका के विद्यार्थी भी बहुत नटखट निकले। एक बहुत बडा राज़ जो कई वर्षों से छिपा हुआ था खोलने मे कोई कसर न छोड़ी। समूचा अमेरिका स्तब्ध रह गया, लोगो ने दातों तले उगली दबा ली। नेशनल स्टूडेंट्स एसोसियेशन के पदाधिकारियो ने खुले आम इस बात को स्वीकार कर लिया कि उनकी संस्था सी० आई० ए० के इशारे पर कई वर्षों से अन्य देशो के विद्यार्थियों और युवकों से तालमेल बढ़ाने का काम करती रही है। मित्रता के पर्दे के पीछे जासूसी का जाल किस प्रकार तेज़ी से फैलता रहा है यह घटना दुःखदायी भी है और रोमांचकारी भी।

मज़े की बात तो यह है कि 'घर के भेदी ने लंका ढाह दी।' अमेरिकन गुप्तचर संस्था 'सी० आई० ए०' का राज़ अमेरिका की प्रमुख विद्यार्थी संस्था ने ही खोल दिया। सी० आई० ए० के अधिकारियों को मुंह छुपाना दूभर हो गया, काटो तो खून नही, लगे इधर उधर की हांकने और दिल ही दिल मे सोचने लगे कि 'खुदा बचाए इन अल्हड़ जवानो से, सी० आई ए० की कई वर्षों की कमाई मिट्टी में मिला दी।'

पुरानी घटनाए एक-एक करके सामने आने लगी। हर चित्र धूमिल था, उस पर दाग़ थे। १९४७ में सी० आई० ए० का जन्म हुआ, उस समय साम्राज्यवाद की जड़ें खोखली हो चुकी थी। लड़खड़ाते हुए साम्राज्यवाद की कोख से सी० आई० ए० का जन्म उसी प्रकार था जैसे 'शैतान का साहिबे औलाद' होना वर्षों की मन्नत मानने के बाद। द्वितीय महायुद्ध मे हिटलर की पराजय से एक नये युग का प्रादुर्भाव हुआ। गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए बहादुर लोगों ने निश्चय कर लिया कि वे हर कुर्बानी देंगे क्योंकि 'आज़ादी तो बलिदान मागती है।' आज़ादी के दीवानों के इस दृढ़ निश्चय को देखकर साम्राज्यवादी सटपटाने लगे और उनके राज्य की दीवारें

गिरने लगीं। एक-एक करके देश आजाद होते गये। विदेशी राज्य के स्थान पर स्वशासन नई आशाओं और आकांक्षाओं का सन्देश लेकर आगे बढ़ने लगा। बड़े-बड़े पूँजीपतियों के दिल दहल गये और उनकी मण्डियां प्रायः ठप्प होने लगीं। हिन्दुस्तान से ब्रिटिश साम्राज्य का साया उठ गया, मिस्र ने नई करवट ली, अफ्रीकी एशियाई देशों में चेतना की एक नई लहर उठ खड़ी हुई।

बस क्या था एक ही थैली के चट्टे-बट्टे मिल गये। कुछ धर्म के नाम पर, कुछ उग्रराष्ट्रवादिता के नाम पर। उनके नाम अलग-अलग थे परन्तु काम एक था। उन्हीं का रूप बना अन्तर्राष्ट्रीय रंगमंच पर 'सी० आई० ए०' अर्थात् केन्द्रीय अमरीकी गुप्तचर संस्था।

अफ्रीका और एशिया की धरती सजग और जागरूक हो जाए तो इसका सीधा परिणाम यह होगा कि शोषण की दीवारें गिर जाएगी, भूखी और नग्न जनता गुलामी की लोहे की जंजीरों को अपने खून की गर्मी से पिघला देगी। जब साम्राज्यवादियों ने इस चुनौती को साकार होते देखा तो उनके हाथ-पाव फूलने लगे। उन्हे इस बात का आभास होने लगा कि 'लोग राष्ट्र शक्ति के स्रोत हैं, क्षीणता के द्योतक नहीं' और वे अपने परिपक्व विचारों से राष्ट्र को नया जीवन प्रदान कर सकते हैं। परन्तु साम्राज्यवादियों ने जनता की ओर उसी प्रकार रुख किया जिस प्रकार 'जब गीदड़ की मौत आ जाये तो वह सरपट शहर की ओर दौड़ने लगता है।'

सी० आई० ए० ने यही उचित समझा कि वह गोपनीय ढंग से उन लोगों का गठन करे जो डालर के बदले अपना ईमान बेचने के आदी हो चुके थे। आजाद देशों मे 'जय चन्दो और मीर जाफरों' को इकट्ठा करने का काम सी० आई० ए० के हवाले किया गया। इतनी बड़ी जिम्मेदारी अमेरिका ने अपने कंधे पर क्यों ली? क्या उसे इस बात का ज्ञान नहीं था कि जिस बच्चे को उसने जन्म दिया है वह बचपन से डकैत, प्रपची और खूनी है। लेकिन 'बदनाम न होंगे तो क्या नाम न होगा' की होड़ लगाये हुए अमेरिका का गुप्तचर विभाग विध्वंसकारी कार्यों में संलग्न रहा।

इतिहास के पन्ने उलट कर देखिए, किसी भी देश को गुलाम बनाने के लिए बाहर से फौजें नहीं आईं बल्कि चन्द मुट्ठी भर लोग व्यापारी बन कर आये, तस्करी के काम मे निपुण थे इसलिए उसी देश के कुछ लोगों को अपना पिट्ठू और दलाल बनाकर अपना उल्लू सीधा करते रहे, और अन्तिम क्षणों तक 'जन सेवा' का दम भरते रहे। जब 'गीदड़ चिल्लाना शुरु कर दे तो समझ लेना चाहिए कि मुर्गियों की

खैर नहीं।' भला कहां साम्राज्यवाद और कहां जन-कल्याण, कहां तस्करी और कहां देश भक्ति, कहां गंगू तेली और कहां राजा भोज।

फिर भी प्रयास जारी रहा, आजादी को छीनने का, गुलामी की जंजीरों में जकड़ने का, लोगों की मान मर्यादा पर कुठाराघात करने का, आर्थिक दबाव डालकर, राजनैतिक कुचक्र चलाकर, ताकि एशिया और अफ्रीका की धरती सिहर न उठे। शुरू-शुरू में सास्कृतिक संस्थाओ को गांठा गया जहा धर्म और संस्कृति के नाम पर जनता को फुसलाना सरल था वहाँ प्रतिक्रियावादी और रूढिवादी संस्थाओं की सहायता की जाने लगी। सी० आई० ए० अपने असली रूप मे सामने आ गया उसके अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह में पूँजीवादी, प्रतिक्रियावादी, एकाधिपत्य वाले, शोषण करने, वाले सब मौजूद थे।

नई-नई संस्थायें बनाई गई राष्ट्रीय स्तर पर भी और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। इन संस्थाओ का बाह्य रूप देखकर कोई नही कह सकता कि यह सस्था देश के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। इसका नाम भोला, परन्तु हाथ में भाला। केवल गौर से देखने पर ही पता लगेगा कि संस्था के काम और नाम में कोई सामंजस्य नही है। यदि आपने यह जानने का प्रयास किया कि इस संस्था को धन कहा से मिलता है? तो आपको यह जानकर निराशा होगी कि जहां भामा शाह ने राणा प्रताप की धन से सहायता उस समय की जब वह पेट पर पत्थर बाध कर शत्रु का मुकाबला कर रहा था, वहां आधुनिक 'प्रताप' की सहायता अमरीकी 'भामा शाह' उस समय करता है जब अन्य लोग पेट पर पत्थर बांधे हुए है और उनका शोषण करना जरूरी हो।

कैसी विडम्बना है? अब्राहीम लिंकन और जेफरसन आजादी की सुरक्षा के लिए लड़े परन्तु उसी की ही सन्तान में कुछ लोग दूसरो की आजादी का दमन करने पर उतारू हैं।

विद्यार्थी वर्ग स्वभाव से ही क्रियाशील और उतावला रहा है, उनकी इस प्रवृत्ति को बदलना असम्भव है। यही कारण है कि किसी प्रकार का पलोभन उनके स्वाभिमान को छीन नही सकता। शुरू-शुरू में उनके जिम्मे जो काम लगाया जाता है उसमें साहस झलकता है। उस नवयुवक की इस साहसिक प्रवृत्ति का दुरुपयोग करने के लिए सी० आई० ए० हर प्रकार के हथकण्डे प्रयोग मे लाता है। लेकिन जब विद्यार्थी को इस बात का आभास हो जाता है कि किस प्रकार उसे

मालाकार बनाया जा रहा है तो वह क्षण भर भी इसे सहन नहीं कर सकता, विद्रोह की ज्वाला भड़क उठती है और वह उस मायाजाल को तोड़ने के लिए अधीर हो जाता है। ठीक ऐसी ही परिस्थिति में अमेरिका की नेशनल स्टुडेंट्स एसोसियेशन ने सी० आई० ए० का भाण्डा चौराहे पर फोड़ने का अदम्य उत्साह किया। परिणाम स्वरूप हर कोने से आवाज उठी, अमेरिका के अन्दर भी और बाहर भी 'जी में आता है तोड़ दूँ शीशा फरेब का'।

गुप्तचरों का टोला :

विदेशों से जो विद्यार्थी अध्ययन करने के लिए अमेरिका जाते है उन पर सी० आई० ए० की कड़ी नजर रहती है। किसी न किसी बहाने उनसे सम्पर्क बढ़ाकर इस प्रकार साठ-गांठ की जाती है कि इस दोस्ती के बदले में उस विद्यार्थी से यह आशा की जाती है कि वह अपना दिल दिमाग सी० आई० ए० के पास गिरवी रख दे। गूढ़ सम्पर्क होने के तुरन्त बाद उसे गुप्तचरों के टोले में भर्ती कर लिया जाता है। उस विद्यार्थी को इस बात का आश्वासन दिया जाता है कि जो काम उसके जिम्मे सौंपा गया है वह अहितकर नही है।

इस प्रकार भर्ती करने के बाद उसका पुनः 'नामकरण' किया जाता है क्योंकि इस नए नाम पर ही उसे रिपोर्ट लिखने के लिए कहा जाता है। इस तरह नए नामकरण के पश्चात कोई 'ईगल' बन जाता है तो कोई 'पैन्थर' और इस नए कार्य के उपलक्ष में १० डालर से लेकर २० डालर तक जेब खर्च प्रति सप्ताह बांध दिया जाता है। इस जेब खर्च के बदले में उसे एक रसीद पर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। रसीद लिखने का मतलब है अपनी मौत के वारंट पर हस्ताक्षर करना। रसीद का डर दिखाकर उसे बाध्य किया जाता है कि वह सी० आई० ए० की इच्छानुसार कार्य करे। उसके इंकार करने पर उसे धमकी दी जाती है कि यदि हस्ताक्षर वाली रसीद उसके देश की सरकार को भेज दी गई तो उसे भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति से एक हुंडी पर भी हस्ताक्षर करा लिए जाते हैं और पिछले दिनो यह आरोप लगाया गया कि इन्हीं लोगों से लिखित रूप में प्रण भी लिए गए हैं कि वे हर राज को गुप्त रखेंगे। इस प्रकार उसके चारों ओर जासूसी का जाल बुन दिया जाता है। परन्तु जब उसे इस बात का आभास होता है कि डालर के बदले उसे अपने ही देश से द्रोह करने के लिए तैयार किया जा रहा है तो उसकी आत्मा उसे विद्रोह करने के लिए प्रेरित करती है।

ठीक ऐसा ही हुआ जब नेशनल स्टुडेन्ट्स एसोसियेशन के पदाधिकारियों ने व्हाईट हाउस की विशेष समिति के अध्यक्ष नीकोलास काजनविच से चर्चा करते हुए कहा कि विदेशों में शैक्षणिक, श्रमिक एवं अन्य संस्थाओं को सी० आई० ए० से पर्याप्त धन राशि मिलती रही है इसलिए नहीं कि शिक्षा का स्तर ऊंचा हो या श्रम की महत्ता बढ़े परन्तु इसलिए कि हर देश में सी० आई० ए० के कुचक्रों का जाल बिछा दिया जाए।

अमरीकी सेनेट की परराष्ट्र समिति के अध्यक्ष विलियम फुलब्राइट ने कांग्रेस के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए सी० आई० ए० पर आरोप लगाया कि यह संस्था अमेरिका की परराष्ट्र नीति पर निरन्तर दबाव डालती रही है। आपने इस बात की भी चर्चा की कि :

"शीत युद्ध से भयभीत होकर हमने सी० आई० ए० को इतनी छूट दे रखी है कि वह हमारी परराष्ट्र नीति का संचालन करती रहे।"

आगे चलकर आपने चेतावनी दी कि :

"यदि शीघ्र ही कोई कदम न उठाया गया तो निकट भविष्य में इस संस्था के कुचक्रों का प्रभाव हमारे देश की गृह नीति पर भी पड़ेगा और उस समय स्थिति पर काबू पाना कठिन हो जाएगा।"

इसके साथ ही कांग्रेस को सुझाव देते हुए विलियम फुल ब्राईट ने जोरदार शब्दों में कहा कि :

"तुरन्त ही सी० आई० ए० की गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाए" यहां यह बात उल्लेखनीय है कि फुलब्राइट द्वारा लगाए गए किसी भी आरोप का आज तक खण्डन नहीं हुआ, उनकी हर बात अक्षरशः सत्य निकली। इसका ज्वलन्त उदाहरण है भूतपूर्व राष्ट्रपति केनेडी की हत्या सम्बन्धी जाच में सी० आई० ए० का दबाव ताकि असलियत को छुपाया जा सके और केनेडी के हत्यारों को दण्ड न मिल सके। अमेरिकन विदेशी सेवा विभाग के अधिकारी स्मिथ सैमसन ने इस बात की पुष्टि की है कि : इण्डोनेशिया के भूतपूर्व राष्ट्रपति डाक्टर सुकर्ण का तख्ता उलटने में सी० आई० ए० का हाथ था और सुकर्ण के विरुद्ध किये जाने वाले प्रदर्शनों की रूप रेखा तैयार करने वाले सी० आई० ए० के प्रमुख अधिकारी थे। वह व्यक्ति जो कई वर्षों तक अपने देश की स्वतन्त्रता के लिए लड़ता रहा और बहुत समय तक

राष्ट्रपति पद पर आसीन रहा उसे पदच्युत करने के लिए अमेरिका ने धन-धान्य से पूरी सहायता की।

इसी प्रकार बर्मा में कम्युनिस्ट-विरोधी चीनी गुरिल्लों की मदद खुफ़िया तौर पर सी० आई० ए० ने की। बर्मा सरकार ने जब इस षडयंत्र के लिए अमेरिका की भर्त्सना की तो बर्मा स्थित अमरीकी राजदूत ने आश्वासन दिया कि अमरीकी सरकार चीनी गुरिल्लों की सहायता नहीं कर रही है। यह आश्वासन केवल आश्वासन ही रहा क्योंकि सी० आई० ए० की गतिविधियों में कोई परिवर्तन न आया।

दक्षिण वियतनाम और दक्षिण कोरिया में भी इस प्रकार की कार्यवाहियां जारी हैं। दक्षिण वियतनाम और कोरिया, दक्षिण अमरीकी जासूसों का अड्डा बन चुका है। लेकिन इसके बावजूद वियतनाम और कोरिया की बहादुर जनता के अदम्य उत्साह के आगे अमेरिकन बम्बारो को मुंह की खानी पड़ रही है। सैंकड़ो अमरीकी हवाई जहाज़ गिराये जा चुके हैं। बांसों में बारूद भरकर जिस मुस्तैदी के साथ वियतनाम की जनता हमलावरों पर टूट पड़ती है उससे यह ज़ाहिर है कि तोपो और बन्दूकों के दहानों पर भी आज़ादी के तराने गाने वाले सेनानी पूरी शक्ति के साथ अमरीकी सैनिकों को नाकों चने चबा सकते हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ में जब नीम-सरकारी संस्थाओं को आर्थिक सहायता देने का प्रश्न उठा, तो यह विवरण प्राप्त हुआ कि सहायता प्राप्त करने वाली ३६५ संस्थाओं में से ३०० संस्थाओं को अमेरिका से सहायता प्राप्त होती है। यह सहायता भिन्न-भिन्न संस्थानों के माध्यम से दी जाती है और अधिकतर संस्थान तो ऐसे हैं जिनके पास जमा हुई धन राशि का कोई ब्यौरा नहीं। न धन के आने का पता और न जाने का। जिस संस्थान के अधिकारी यह भी नहीं जानते कि पैसा कहां से आया और कहां चला गया या तो वे जान-बूझ कर बावले बने बैठे हैं या वे स्वयं ही सी० आई० ए० की मशीनरी के पुर्ज़े हैं। अमरीका में जितने भी संस्थान बनाये जाते हैं या तो वे नीजि होते हैं और या फिर उन्हें 'गुप्त दान' देने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि गत कुछ वर्षों से कई ऐसे संस्थान बनाये गये हैं जिनका काम सी० आई० ए० के गुप्त कार्यों को बढ़ावा देने के लिए 'दानियों' का लबादा पहन कर ऐसी संस्थाओं की सहायता करना है जो विध्वंसकारी और विघटनवादी कार्यों से संलग्न हों। ज़ाहिर है कि नए संस्थान पर आसानी से शक नहीं किया जा सकता और यदि ऐसी नौबत आ भी जाए तो एक के

बदले अनेक संस्थानों की सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं। एक बार तो प्रत्येक व्यक्ति सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अमेरिका की इस 'उदारवादिता' की कोई सीमा भी है जहाँ तक धन के दलालों को सीमित रखा जा सकता हो।

सी० आई० ए० की नींव मुख्यतः इसीलिए रखी गई थी कि इस संस्था के माध्यम से 'साम्यवादी गतिविधियों' को अमेरिका में रोका जा सके। लेकिन यह तो केवल उसका बाह्य रूप था। अन्दर ही अन्दर गुप्तचर विभाग अपना जाल फैलाता रहा और इसने अपनी लपेट में अन्य देशों के कई व्यक्तियों को भी ले लिया। जब इसने अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप धारण किया तो सी० आई० ए० के ऐजेन्ट कई देशों में फैल चुके थे। सब से प्रथम, सी० आई० ए० की गतिविधियों के केन्द्र बने वे देश जिन्होंने थोड़ा समय हुआ आजादी प्राप्त की थी। पूंजीवादियों को हमेशा इस बात का डर रहा है कि आजादी मिलने के बाद शोषण के सब मार्ग बन्द हो सकते हैं। जब विदेशी कारोबार पर रोक लगेगी तो मण्डियों में पूंजीवादी व्यवस्था कायम न रह सकेगी। इसलिए वे शक्तियां जो शोषण पर ही पलती हैं आजादी के सूर्य का उदीयमान देखकर शोकातुर क्यों न हों ? परिणामस्वरूप इस आजादी पर प्रहार करने के लिए साम्राज्यवादी दलाल दल-बल के साथ आर्थिक दरवाजे से घुसने को प्रयास करते हैं और जब उन्हें इस बात का ज्ञान हो जाता है कि अमुक सरकार शोषण के विरुद्ध है तो उसका तख्ता उलटने के लिए षड्यन्त्र रचा जाता है। इसमें सहायता देती है स्थानीय पूंजीवादी व्यवस्था और उसकी रक्षा करने वाली संस्थाएं।

प्रजातन्त्र दोधारी तलवार है। इसका सही प्रयोग तो तभी होता है जब इसका विकास करते समय जनता की आकांक्षाओं का ध्यान रखा जाए। लेकिन इसका दुरुपयोग तब होता है जब कोई व्यक्ति यह समझने लगता है कि देश-द्रोह करना उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसी अवस्था में वह हर प्रगतिशील नीति का विरोध करता है और यह सब कुछ दूसरे के इशारे पर होता है। ऐसी संस्थाओं का जन्म होते देर नहीं लगती लेकिन इनका पतन भी उसी प्रकार शीघ्र ही होता है। सी० आई० ए० की यह टेक्नीक रही है कि जहाँ किसी संस्था में प्रवेश पाना कठिन हो वहाँ उसके मुकाबले में नई संस्था खड़ी कर दी जाये और इस संस्था के माध्यम से जन-जीवन में घुसपैठ की जाये। इस प्रकार के घुसपैठिये आपको कुछ साहित्यिक और सांस्कृतिक नाम रखने वाली संस्थाओं में भी मिलेंगे। इनका सम्बन्ध न तो साहित्य से होता है न संस्कृति से। लम्बे-लम्बे बाल रखकर साहित्यक बनने का दावा करेंगे, लम्बे-लम्बे

चोगे पहन कर योगा बनने का बहाना करेंगे, रोयेंगे तो संस्कृति के नाम पर, उनका हर आंसू मगरमच्छ का होगा, पर उनके शरीर के हर रोएं-रोएं से गद्दारी की भावना टपकेगी, उनका हर वाक्य जहर में डूबा हुआ होगा। उनकी हर अदा में मस्ती नही शरारत होगी, उनका हर काम विध्वंसकारी होगा। धर्म और संस्कृति के ठेकेदार बनकर साम्प्रदायिकता को हवा देंगे झूठ बोलेंगे तो गोबल्ज़ को मात कर देंगे। और अफ़रातफरी मचाने मे हिटलर को भी परास्त कर देंगे।

लेकिन तब तक, जब तक चेतना का प्रहरी सोता है और उसके सजग और जागरुक होते ही दुम दबाकर भाग जाएगे। आम चुनावों में सी० आई० ए० को विशेष दिलचस्पी रही है। जब फ्रास में चुनाव के समय प्रगतिशील सस्थाओ के जीतने की पूरी सम्भावना थी, तो सी० आई० ए० ने ऐड़ी से चोटी का जोर लगाकर इस सफलता को पराजय मे बदलने का भरसक प्रयास किया। १९४८ में जब ईटली साम्यवादी सफलता की ओर अग्रसर हो रहा था तो सी० आई० ए० ने क्रिश्चियन डेमोक्रेटस को पूरे तौर पर सहायता की। चोर-चोर मौसेरे भाई इकट्ठे हो गये। उनका उद्देश्य जनता की दु:ख तकलीफ को दूर करना नही बल्कि चुनाव के माध्यम से ऐसी सरकार की स्थापना करना था जो साम्राज्यवादी ताकतों का दुमछल्ला बन सके। उन सब प्रगतिशील व्यक्तियो का विरोध किया गया जो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के कट्टर विरोधी थे। कैरो के विख्यात समाचार पत्र दैनिक "अल-अहराम" के अनुसार भारत में आम चुनाव के समय १९६२ मे और १९६७ मे सी० आई० ए० ने भूतपूर्व रक्षा मत्री कृष्णा मेनन को हराने के लिए लाखो रुपये खर्च किए।

जिस स्थान पर चुनाव के माध्यम से सी० आई० ए० की पिठ्ठू सरकार कायम नहीं हो सकती उन स्थानों पर ऐसा ढग अपनाया जाता है कि प्रगतिशील सरकार का तख्ता उल्ट दिया जाये। गोटे माला के भूतपूर्व राष्ट्रपति आरबेन्स के खिलाफ ऐसा ही षडयन्त्र रचकर उसे गद्दी से हटाया गया। गायना के भूतपूर्व प्रधान मत्री छेदी जगन के विरुद्ध भी ऐसा ही षडयन्त्र रचा गया और पीपुल्ज प्रोग्रेसिव पार्टी को हराने का भरसक प्रयास किया गया। बहादुर लुमुम्बा की मौत भी इन्ही के हाथों हुई। उगते हुए देशो के महान् नेताओ के खिलाफ सी० आई० ए० की गतिविधिया न केवल शर्मनाक हैं परन्तु दु:खदायी भी।

१९६० में सी० आई० ए० ने सिंगापुर के मनोनीत और विख्यात राजनीतिज्ञ को ३५ लाख डालर देकर खरीदना चाहा, परन्तु उनका यह प्रयास सफल न हो सका।

सी० आई० ए० की गतिविधियों का संचालन करने का केन्द्रीय कार्यालय वाशिंगटन में स्थित है जिसमें लगभग १०,००० व्यक्ति कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त आंशिक समय में कार्य करने वालों की संख्या भी कई हजार है। अन्य देशों मे सी० आई० ए० का काम करने वालों की संख्या लगभग दो हज र है। मुख्यतः अमरीकी दूतावास के सूचना केन्द्र हर देश में इन कार्यवाहियों के केन्द्र हैं। हर देश में कार्यभार जिस व्यक्ति के जिम्मे सौंपा जाता है उसे हर प्रकार की सुविधाएं प्राप्त रहती हैं। आश्चर्य तो यह है कि सी० आई० ए० का अधिकारी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रखता है उसे डिप्लोमेट्स को मिलने वाली सब सुविधाए प्राप्त हैं। यह व्यक्ति दूतावास का अधिकारी भी होता है और सी० आई० ए० का भी। ऐसी परिस्थिति मे सांस्कृतिक आदान-प्रदान तो केवल ढोंग है, इसकी आड़ में शिकार खेला जाता है जिससे लोगों के दिल दिमाग पर काबू पाया जा सके। कुछ लोग तो शराब और डालर के नशे में भले ही मस्त हो जाएं परन्तु आम जनता को इस बात का आभास है कि झुग्गी में रहने वाले इन्सान की भी मर्यादा हुआ करती है, भूखा इन्सान भी स्वाभिमानी हो सकता है, और फटे, पुराने कपड़े पहनने वाला राजाओं की चादर नोचने की जुर्रत कर सकता है। इसीलिए सी० आई० ए० के डालर किसी गरीब व्यक्ति की विद्रोही भावना को शान्त नही कर सकते, उसका ईमान नही खरीद सकते। इतिहास साक्षी है कि जब भी किसी व्यक्ति के स्वाभिमान को दौलत से लड़ाया गया तो उसने दौलत के ढेर को ठुकरा दिया। क्रांति की ज्वाला भड़की और बड़े-बड़े साम्राज्य घुटने टेकने पर मजबूर हो गए।

फिर भी यदि कोई अमरीकी उदारवादिता का ढंढोरा पीटने की सौगंध खाए हुए हो तो उसे भूलना नही चाहिये कि भूखे और नगे लोग पेट पर पत्थर बांधकर भी अपने स्वाभिमान की रक्षा कर सकते हैं।

यहाँ यह जान लेना जरूरी है कि आम तौर पर प्रत्येक देश की यह कोशिश होती है कि वह अपने दूतावास के माध्यम से इस बात की जानकारी रखे कि अमुक नीति के बारे में उस देश की क्या प्रतिक्रिया है। जिसके फलस्वरूप उसे अपनी नीति निर्धारित करने में सावधानी बरतने की आसानी रहती है। परन्तु यदि यही दूतावास प्रतिक्रिया जानने के अतिरिक्त उस देश पर हावी होने का कुप्रयास करे तो यह राजनीति या कूटनीति नही बल्कि उस देश के खिलाफ षडयन्त्र है। कोई भी स्वाभिमानी देश अपने ही देश मे ऐसे नागों को दूध नहीं पिला सकता।

इसलिए इन सफेद नागो से बचने की आवश्यकता है और खास तौर पर उस समय जब कि यही नाग छद्मवेश धारण करके स्थान-स्थान पर घूम रहे हों।

पीस कोर

कहा जाता है कि पीस कोर की स्थापना अफ्रीका, एशिया और लतीनी अमेरिका के विकासशील देशों की आर्थिक और तकनीकी सहायता देने के उद्देश्य को लेकर हुई थी। १९६० में पीस कोर का उद्घाटन करते हुए अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति राबर्ट केनेडी ने कहा था :

"कम विकसित देशों को न केवल अमेरिका से आर्थिक सहायता एवं मशीनों की आवश्यकता है बल्कि इन देशों को इस बात का आश्वासन मिलना चाहिए कि अमेरिका के विचार और उसके तौर-तरीके सही हैं।"
राबर्ट केनेडी ने आगे चलकर कहा :

"आर्थिक विकास के लिए अमरीकी कार्यकर्त्ताओं का इन कम-विकसित देशों मे भेजा जाना आवश्यक है।" (हेरल्ड ट्रिब्यून)

अमेरिका के एक अन्य समाचार पत्र "सेचरडे रिव्यू" में अपने उद्गार व्यक्त करते हुए जार्ज सोकोलस्की ने एक लेख में पीस कोर के वास्तविक उद्देश्यों की चर्चा करते हुए लिखा है कि "क्या पीस कोर अपना कार्य कर सकती है ?" के शीर्षक के अन्तर्गत सुझाव देते हुए सोकोलस्की ने कहा है :

"निष्काम स्वयं सेवकों की कार्य कुशलता से ही हम उस ध्येय को प्राप्त कर सकते हैं जिससे जन-जीवन प्रफुल्लित हो सके और जन-साधारण अमेरिका की ओर उसी प्रकार देखे जिस प्रकार मुसलमान 'मक्का' की ओर इस आशा से देखते हैं कि यही वह स्थान है जहां शान्ति और सन्तोष प्राप्त हो सकता है।"

कहने को तो पीस कोर निष्काम सेवा करने वाले कार्यकर्त्ताओं की टोली है परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है। पीस कोर की गतिविधियों से तंग आकर ही कई देशों में पीस कोर की कार्यवाहियों पर रोक लगा दी गई है। कुछ ही दिन हुए प्रधान मंत्री श्रीमती भण्डार नायके ने पद ग्रहण करने के कुछ दिन बाद पीस कोर के २३ स्वय सेवकों को श्री लंका से निकल जाने का आदेश दिया। श्री लंका में इन स्वय सेवकों का यह अन्तिम टोला था जिसे निष्कासित कर दिया गया है। इस टोले के खिलाफ कई संगीन आरोप थे और हर व्यक्ति की जबान पर इस बात का चर्चा था कि पीस कोर के स्वयसेवकों के माध्यम से ही श्री लंका की आर्थिक व्यवस्था को बिगाड़ने की योजना बनाई जाती रही है ताकि आर्थिक बन्धनों मे फंसा हुआ यह देश साम्राज्यवादी चंगुल से निकल न सके।

पीस कोर की यह नीति रही है कि किसी भी देश की नीति उसकी अपनी राजधानी में निर्धारित न होकर वाशिंगटन स्थित व्हाईट हाऊस में हो। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाये तो यूँ समझिये कि उस देश की आजादी हमेशा-हमेशा के लिए गिरवी रखी जा रही है। यही कारण है कि पीस कोर के माध्यम से प्रतिक्रिया-वादी विचारों का प्रतिपादन किया जाता है।

अमेरिकन राष्ट्रपति के चुनाव अभियान के समय केनेडी ने १९५९ में सान् अन्टोनियो के स्थान पर मतदाताओं को सम्बोधित करते हुए पीसकोर की पहली बार चर्चा करते हुए कहा था कि पीस कोर जैसी सस्था को कायम करना ज़रूरी है। परिणामस्वरूप जब केनेडी ने राष्ट्रपति पद ग्रहण किया तो थोडे समय बाद उन्होंने अमेरिकन कांग्रेस को अपने एक संदेश द्वारा पीसकोर बनाने का सुझाव दिया था। इसी सुझाव पर विचार विनिमय के बाद पीस कोर की स्थापना का सुझाव स्वीकार कर लिया गया। सुझाव के पक्ष मे सेनेट के ५९ सदस्यों ने वोट दिए और विपक्ष में ३२। हाऊस आफ़ रिप्रेजेंटेटिवज में २८८ और ९७ के अनुपात से यह सुझाव स्वीकार कर लिया गया।

बस क्या था पीस कोर की नींव रख दी गई और उसके सर्व प्रथम निदेशक बने केनेडी के बहनोई सार्जेन्ट शिविर। इसके इलावा ३३ सदस्यों पर निर्धारित एक समिति का गठन भी किया गया जिसमें प्रमुख थे लिंडसन जानसन जो बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति बने और सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीश विलियम डगलस।

कहने को तो पीस कोर एक स्वतन्त्र संगठन है परन्तु इसका संचालन व निर्देशन अमेरिकन गृह विभाग व सी० आई० ए० ही करता है। वाशिंगटन स्थित कार्यालय में पीस कोर के ७५५ अधिकारी कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त एशिया, अफ्रीका और लतीनो अमेरिका में कार्य भार विभिन्न समितियों एवं उपसमितियों के हवाले किया गया है। इस संस्था को हर प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हैं ताकि पीस कोर का काम सुचारु रूप से चल सके। पीस कोर का काम भी अमरीकी दूतावास के माध्यम से किया जाता है और इसका प्रमुख अधिकारी भी सी० आई० ए० के प्रमुख अधिकारी की तरह दूतावास का भी अधिकारी होता है और उसे वह सब सुविधाएं प्राप्त हैं जो किसी भी अन्य डिप्लोमेट को प्राप्त होती हैं।

वाशिंगटन में पीस कोर कार्यालय एक विशालकाय भवन में स्थित है जहाँ अफ्रीका, एशिया और लतीनी अमेरिका के बड़े-बड़े मानचित्र दीवारों पर लटके रहते हैं। प्रत्येक विभाग अलग है और उसका प्रमुख अधिकारी भी अलग। सब आवश्यक कागजात उसी के पास रहते हैं और वही अपने विभाग का संचालन एवं निर्देशन करता है। पीस कोर में कार्य करने वाले सभी व्यक्ति वैतनिक हैं। शुरू-शुरू में आंशिक रूप से जिनको भत्ता दिया जाता है उसमें अधिकांश विद्यार्थी होते हैं। थोड़े समय बाद उन्हें पूरे तौर पर भर्ती कर लिया जाता है। उसका कारण यह है कि पीस कोर सी० आई० ए० का तरुण मोर्चा है। ऐसे कार्मों के लिए विद्यार्थियों और युवकों को विशेष तौर पर तरजीह दी जाती है, कारण यह कि विद्यार्थी और युवक किसी भी साहसिक कार्य करने से नहीं घबराते। शुरू-शुरू में तो इन युवकों को इस बात का ज्ञान नहीं होता कि उन्हें क्यों बटोरा जा रहा है लेकिन जब उन्हें इस बात का पता लगता है कि उन्हें अपने ही देश में उलट फेर करने के लिए तैयार किया जा रहा है तो उसमें विद्रोह की आग तेज हो जाती है, फिर वह पीस कोर का नहीं क्रांतिकारी आन्दोलन का अग्रदूत बन जाता है।

आश्चर्य तो यह है कि पीस कोर के कार्य-क्रम को विस्तृत रूप देने वालों के लिए गोरी चमड़ी वालों को ही भर्ती नहीं किया जाता बल्कि अफ्रीका जैसे देशों में कार्य करने के लिए काले रंग वालों को भी भर्ती किया जाता है ताकि गुप्त कार्य करने में कोई बाधा न पड़ सके। इस प्रकार की योजना बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि अमेरिका की रंग-भेद नीति पर पर्दा पड़ा रहे। क्योंकि सब जानते हैं कि अमेरिका में जहाँ-जहाँ रंग-भेद का प्रश्न उठा, काले लोगों पर खूंखार कुत्ते छोड़े गए। अमेरिका में अब भी कई शिक्षा संस्थाओं में केवल गोरे रंग

के विद्यार्थी ही प्रवेश पा सकते हैं काले रंग वाले बच्चे पास भी नहीं फटक सकते। इन सब तथ्यों की मौजूदगी में पीस कोर एक मजाक बन गया है।

जहाँ सी० म्राई० ए० रंग-भेद नीति को कायम रखने के लिए दक्षिणी रोडेशिया भ्रौर दक्षिणी भ्रफीका जैसे देशों को हर प्रकार का प्रोत्साहन देता है वहां कहीं भी पीस कोर के कार्यकर्त्ताभ्रों ने रग-भेद नीति के विरोध में भ्रपनी जुबान नहीं खोली।

पीस कोर के निदेशक ने भ्रफ्रीकी, एशियाई भ्रौर लतीनी भ्रमेरिका के देशों का दौरा करने के बाद भ्रपने उद्‌गार व्यक्त करते हुए कहा :

"भ्रफ्रीका, एशिया भ्रौर लतीनी भ्रमेरिका में ऐसे पर्याप्त भ्रवसर प्राप्त हैं कि इन देशो में वही घटना दुहराई जा सकती है जो फिलीपाईनज में ५ हजार भ्रमरीकी भ्रध्यापकों के माध्यम से १६१० में घटित हुई थी (भ्रर्थात् इन देशों में गुलामी के बीज पुनः बोये जा सकते हैं।)"

१६५५ के भ्रमेरिकन बजट में म्यूचुभ्रल सक्यूरिटी पैक्ट के भ्रन्तर्गत १५०० लाख डालर की बृहत्त योजना स्वीकार की गई। इसके भ्रतिरिक्त ६००० लाख डालर की राशि प्रशिक्षण कार्य के लिए निर्धारित की गई। सन् १६६४ तक कुल मिला कर दस हजार पीस कोर स्वयं सेवक विश्व के विभिन्न भागों में काम पर जुटे हुए थे भ्रौर भ्रकेले भारत में इनकी संख्या १४०० है। भ्रमेरिका ने कुछ देशो के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए समभौता कर रखा है भ्रौर उसी के भ्रन्तर्गत पीस कोर के स्वयं सेवक उन देशों में तैनात किए जाते हैं। इनमें से कुछ स्वयं सेवक थोडा बहुत जनसेवा का कार्य तो भ्रवश्य करते है लेकिन उनकी संख्या नही के बराबर है। भ्रधिकतर स्वयं सेवक जासूसी का काम करते हैं भ्रौर जैसे कैसे वे सब जानकारी प्राप्त करते हैं जिनसे उनके मालिक प्रसन्न रहें भ्रौर जासूसी का काम चलता रहे। भोले भाले लोगो को गोरी चमडी वाली नारियों के मोहपाश में उलभाने का भरसक प्रयास किया जाता है भ्रौर कही-कही तो पीले वस्त्र धारण किए हुए भ्रमेरिकन साधु लोगों को चक्र में फंसाने का विफल प्रयास भी करते हैं। उनके शरीर पर शिखर दुपहरी में बदन से चिपका हुम्रा वस्त्र उनके भोलेपन की निशानी तो जरूर है परन्तु उनकी कूटनीति का परिचायक भी। गले मे मोटे-मोटे रुद्राक्षो की माला पहनकर भ्रमेरिकन देवियां लोगों को वशीभूत करने के लिए सड़क के चक्कर काटती दिखाई देंगी। ऐसा लगता है कि वशीकरण ही उनका मूल मत्र हो। उनके लिए न कुछ उचित है न भ्रनुचित। जैसे तैसे काम चलता रहे यही उनका उद्देश्य

होता है। ये लोग साम्राज्यवाद के दलाल बन कर जगह-जगह घूमते हुए दिखाई देंगे। इनका बाह्य रूप कुछ और है और आन्तरिक रूप कुछ और। बगल में छुरी है तो मुँह में राम राम। रंग भले ही सफेद हो लेकिन मन कलुषित। अन्दाज और सलीका आशकाना जरूर है लेकिन काम घिनौना। खुदा बचाए इन लोगों से जो बड़े-बड़े शहरों में रोमियो-जूलियट बने घूमते हैं। यदि आप किसी ऐसे छद्मवेषी व्यक्ति को देख लें तो समझ लीजिए कि पुरानी शराब नई बोतलों में हाजिर है। साम्राज्यवादियों के इस नए हथकण्डे से जन-साधारण सजग है और यही कारण है कि जहाँ एक बार यह हथकण्डा अपना लिया गया वहाँ आंच पर काठ की हांडी दुबारा नहीं चढ़ सकी।

अमेरिका की आजादी का इतिहास साक्षी है कि अमेरिकन लोगों ने बर्तानवी साम्राज्यवाद से छुटकारा पाने के लिए किस प्रकार संघर्ष किया। यातनाएं भी सहन कीं परन्तु तब तक चैन से न बैठे जब तक कि ब्रिटिश साम्राज्य का बिस्तर गोल न कर दिया। परन्तु आश्चर्य की बात है कि उसी देश के माथे पर एक कलुषित दाग इस बात का भी लगा रहे कि बीसवीं शताब्दी में जब जन साधारण आजादी के लिए अधीर हो तो अमेरिकन फौजें आजादी की इस भावना को दबाने के लिए बम, गोले और बन्दूकें लेकर असहाय जनता पर टूट पड़े। आखिर कब तक गुलामी के ये कीड़े पलते रहेंगे। कब तक जनता की भावनाओं की अवहेलना करने का दुसाहस जारी रहेगा। कब तक संगीन की नोकों से निहत्थे लोगों के सीने छलनी होते रहेंगे। हीरोशीमा और नागा साकी पर बम बरसाने के बाद अमेरिका अपना सिर गर्व से कैसे ऊंचा कर सकता है? हजारों लोग जो परमाणु बम का कोप भाजन बने उनकी भटकती हुई आत्माएं किस प्रकार अमेरिका निवासियों को चैन से बैठने देंगी। सम्भवत: बदले की भावना पुनः जागृत हो चुकी है और यही कारण है कि अमेरिका के नौजवानों ने अपनी सरकार की जंगबाज नीती का तीव्र विरोध करने के लिए विशाल प्रदर्शनों का सहारा लिया है। कम्बोडिया में सी० आई० ए० के षड़यन्त्र के विरोध में अमेरिका में जितने प्रदर्शन हुए वे इस बात का प्रमाण हैं कि आधुनिक पीढ़ी अमेरिकन सरकार की नीतियों से परेशान है। कोई कालेज या विश्वविद्यालय ऐसा नहीं जहाँ विद्यार्थियों की आवाज़ अमेरिकन सरकार की बर्बरता के खिलाफ न उठी हो। भले ही इस महान् कार्य में नन्हे मुन्हें अमेरिकन युवकों को गोली का निशाना बनना पड़ा हो। लेकिन नवयुवकों का अदम्य उत्साह प्रशंसनीय था और उसके सामने हजारों लाखों सिर श्रद्धा से झुक गए।

दक्षिण वियतनाम में आजादी के दीवानों की लड़ाई विश्व के इतिहास में अपना अनोखा स्थान बनाए हुए है। यह ठीक है कि अमेरिकन साम्राज्यवाद कभी भी ब्रिटिश साम्राज्यवाद का अंश नहीं रहा है और इसका विशेष कारण यह था क्योंकि ब्रिटेन नहीं चाहता था कि उनकी साम्राज्यवादी मण्डियों में कोई अन्य साम्राज्यवादी प्रवेश पा सके। दो साम्राज्यवादी शक्तियां एक मन्तव्य रखते हुए भी आपस मे ईर्ष्या और द्वेष रखती थीं। लेकिन जब भारत स्वतन्त्र हुआ तो ब्रिटिश मिशनरी तो सही रास्ते पर आने लगे परन्तु अमेरिकन मिशनरियों ने अपना असली रूप दिखाना शुरू किया। ये लोग अमरीकी उदारवादिता के गुण गाने लगे और इन्होंने सतत् इस बात का प्रयास किया कि लोग अमरीकी संस्कृति और सभ्यता के पुजारी बन जाए। शायद उन्हें कुछ सफलता भी मिल जाती परन्तु अमेरिका में साम्राज्यवादियो की जड़े इतनी मजबूत हो चुकी थीं कि इन्होंने दूसरे देशों की आजादी पर पैदरपे हमले करने शुरू कर दिए। लोगों को सही ढंग से अमेरिकन उदारवादिता के दिग्दर्शन होने शुरू हो गए। रही सही कसर सी० आई० ए० और उसकी सहायक एंजसियों ने पूरी कर दी। अमेरिकन दलालों का यही काम रहा है कि वे भारत को एक भिखारी के रूप मे पेश करते रहें और अमेरिका का उदारवादी देश के रूप में। परन्तु वे भूल जाते हैं कि भारतीय जनता अमेरिका सी भीख नही बल्कि स्पष्टवादिता की माग करती है। वह स्वाभिमान के दायरे मे चट्टान की तरह मजबूत हैं।

गत वर्षो में पीस कोर की गतिविधियो के विरोध में पेरू, कोलम्बिया, क्यूबा और अर्जनटाईना में कई विशाल प्रदर्शन हुए हैं जहां यह माग की गई है कि पीस कोर की गतिविधियो पर शीघ्र प्रतिबन्ध लगाया जाए। कई देशों से पीस कोर के स्वयं सेवक निष्कासित किए जा चुके हैं। अन्य स्थानों मे भी यही माग की जा रही है। पिछले दिनों कोलम्बिया विश्वविद्यालय के छात्रो ने डोमिनिकन गृह-युद्ध में पीस कोर के हस्तक्षेप की तीव्र भर्त्सना की। अफ्रीका के कई देशों मे भी प्रचण्ड प्रदर्शन हुए। उन सबका उद्देश्य एक था कि पीस कोर का बोरिया बिस्तर गोल कर दिया जाए।

पुरानी रुढ़िवादी परम्पराओ को तोड कर अफ्रीका प्रगति के पथ पर अग्रसर है। परन्तु फिर भी पीस कोर वाले पुरानी लकीर को ही पीटते जा रहे है और निरन्तर इस कोशिश में रहते हैं कि प्रगति के पथ पर अफ्रीकी देशों के बढते हुए चरण रुक जाएं। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सी० आई० ए० वाले काले रग वाले लोगों को अपने जासूसी के जाल में फंसाने की कोशिश करते रहते है।

वाले मजदूरों की यूनियन को भी फांसने की कोशिश की परन्तु उन्हें सफलता न मिल सकी। इस सम्बन्ध में अखिल भारतीय बन्दरगाह कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष ने भारत सरकार से अनुरोध किया था कि इस तथ्य की जांच की जाए कि सी० आई० ए० द्वारा मजदूर संगठनों को कितनी धनराशि दी गई है।

इसी प्रकार पाकिस्तान के भूतपूर्व वित्त मंत्री मोहम्मद शोआव पर ब्रिटेन के एक समाचार पत्र में आरोप लगाया गया कि इसी मंत्री महोदय की सेवाए सी० आई० ए० ने पाकिस्तान सरकार का तख्ता उल्टने के लिए प्राप्त की थी। यह समाचार सितम्बर १९५५ में दैनिक समाचार पत्र 'डेली टेलीग्राफ' मे प्रकाशित हुआ था जिसमें यह भी आरोप लगाया गया था कि शोआव के माध्यम से अमरीकी सरकार ने अय्यूब सरकार को धमकी दी थी कि यदि भूतपूर्व राष्ट्रपति अय्यूब खां ने सोवियत रूस के प्रति कड़ा रुख न अपनाया तो पाकिस्तान को दी जाने वाली आर्थिक सहायता बन्द कर दी जाएगी।

५ जून १९६७ को भारतीय ससद में चर्चा करने हुए कुछ ससद सदस्यो ने सी० आई० ए० पर आरोप लगाया कि वह भारतीय समाचार पत्रों को आर्थिक सहायता दे रही है ताकि इन समाचार पत्रों मे छपने वाले लेखो को नए ढग से प्रस्तुत किया जा सके। निश्चय ही यदि कुछ समाचार पत्र किसी अमुक नीति का समर्थन करना शुरू कर दें तो वातावरण मे काफ़ी परिवर्तन आ सकता है। यही कारण है कि कई बार तो यह भी देखने में आया है कि हिन्दुस्तानी ज़बान में छपने वाले कुछ समाचार पत्रों के सम्पादकीय लेख मिलते-जुलते थे। हो सकता है कि इन लेखों को लिखने वाला सी० आई० ए० का ही प्रमुख अधिकारी हो। इसके अतिरिक्त सी० आई० ए० की यह भी कोशिश रहती है कि पत्रकारों से भी सीधा सम्पर्क बढ़ा कर उन्हें इस कार्य में भागीदार बनाया जा सके। जिन पत्रकारो की लेखनी में बल है उन्हे प्रलोभन दिया जाता है कि वे यदि एक पुस्तक का अनुवाद कर पायें तो उन्हें प्रति पृष्ठ २० या २५ रुपये मिल सकते हैं। इस प्रकार बड़ी-बड़ी धनराशि देने का प्रलोभन देकर उन्हें फुसलाने का भी प्रयास किया जाता रहा है। अलग बात है कि हमारे देश के पत्रकार स्वाभिमानी हैं और वे खरीदे नही जा सकते। कुछ वर्ष हुए ऐसे ही स्वाभिमानी पत्रकारो ने अपनी संस्था से अनुरोध किया था कि अमरीकी दूतावास के सूचना विभाग द्वारा पत्रकारों से तालमेल बढ़ाने के इस रवैया के खिलाफ आवाज़ उठाई जाए।

भारतीय संसद में एक पत्रिका 'ब्लेस्ट' की चर्चा करते हुए मांग की गई थी कि भारत सरकार इस विषय की पूर्ण जाच पड़ताल करे कि सी० आई० ए० के माध्यम से किन-किन समाचार पत्रों की धन से सहायता की गई है। वास्तव मे सी० आई० ए० का काम जितनी तेजी से बढ़ा है उतनी ही तेजी से उनका पतन भी हुआ है। कारण यह कि हर चीज की सीमा होती है और यदि कोई उस सीमा को लांघने की कोशिश करे तो परिस्थितियां उसके प्रतिकूल हो जाती हैं। न चालाकी साथ देती है, न मक्कारी। एक-एक करके प्रत्येक राज सामने आ जाता है, चाहे उसको छुपाने का कितना भी प्रयास क्यों न किया गया हो।

आइये ! अब देखें कि युवक आन्दोलन इन गतिविधियों को किस प्रकार देखता है। किस प्रकार विश्व युवक आन्दोलन धन के दलालों का विरोध करता है। कौन सी शक्तियां प्रगतिशील विचारों का समर्थन करती हैं और कौन सी संस्थाए रूढिवादी, प्रतिक्रियावादी और फासिस्ट मनोवृत्ति का शिकार हैं। जन-विरोधी भावनाओं का प्रतिपादन करने वाला जनता का हितैषी नहीं, तो किसका हितैषी है ? क्या कारण है कि आज का नवयुवक सजग और जागरूक हो चुका है ? किसने उसकी सोई हुई चेतना शक्ति को जगा दिया है और वह क्यों आधुनिक संसार का इतिहास पुन: लिखने के लिए अधीर है ? उसे प्रश्न नही, प्रश्नो का उत्तर चाहिए क्योंकि उसमें कार्य करने की क्षमता है। नवयुवक कठिनाईयो से लोहा ले सकता है। यही कारण है कि ससार मे युवक आन्दोलन की भूमिका लिखने वालो के सामने भविष्य की रूप रेखा सदैव नाचती रही है। आओ देखे कि इन परिस्थितियो में युवक क्या सोचता है ?

भारत में पीस कोर

भारत में पीस कोर के कार्यकर्त्ता काश्मीर के प्रश्न पर इतने अधिक चिंतित हैं कि यदि उनमें से कोई भी आपको इस विषय पर बात करता मिल जाए तो आप सरलता से इस बात का पता लगा सकते हैं कि यह अपनी जुबान से किस के मुंह की बात बोल रहा है और कौन से ऐसे तत्व हैं जिनका यह प्रतिनिधित्व करता है।

जब भारत में आम चुनाव के पश्चात् संसद का प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ तो उसमें सी० आई० ए० के बारे में चर्चा के दौरान कई राज सामने आए। संसद में यह आरोप लगाया गया कि अमरीकी दूतावास का कौंसिलर मिनिस्टर अपने दूतावास सम्बन्धी कार्य के साथ-साथ सी० आई० ए० का मुख्य अधिकारी भी है। उसका नाम लेनार्ड विस बताया गया और कहा गया कि अमेरिकन दूतावास के सूचना विभाग के कार्यालय का एक कमरा सी० आई० ए० के अधिकारी अन्य लोगों से सम्पर्क बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। दूतावास को मिली हुई डिप्लोमेटिक सुविधाओं का किस प्रकार हनन किया जाता है, इसका पता लगते ही मनुष्य की आस्था ऐसा कार्य करने वाले लोगों से उठ जाती है। यह दुःख का विषय है कि हमारे देश में ही हमारे आंचल में विषैला सांप पलता रहे और हम निःसहाय उसे खड़े देखते रहें।

सी० आई० ए० में दो प्रकार के दलाल हैं :—

१. संस्थाएं और
२. व्यक्ति विशेष

सी० आई० ए० में भर्ती होने के लिए नवयुवकों और विद्यार्थियों को तरजीह दी जाती है। दूसरा नम्बर पत्रकारों का है। विद्यार्थी और युवक आसानी से भुलावे में आ सकते हैं इसलिए उनकी ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। वे पत्रकार जो अपनी 'आमदन' बढ़ाना चाहते हैं उन्हें 'आधुनिक समस्याओं से सम्बन्धित' लेख लिखने के लिए अच्छी खासी रकम दी जाती है। सवाल लेख लिखने का नहीं बल्कि इस लेख के माध्यम से इस पत्रकार के हृदय में प्रवेश करके उसे सदा के लिए अमरीकी 'उदारवादिता' का समर्थक बनाना है। यह लेख यह कह कर लिखाए जाते हैं कि इनका प्रयोग समाचार पत्रों में किया जाएगा परन्तु यह सब लेख वाशिंगटन भेजे जाते हैं जहां इन लेखों की भली भांति छान बीन की जाती है और उन्हीं के आधार पर सी० आई० ए० अपना अगला कदम निर्धारित करती है।

दलाल कैसे भर्ती किए जाते हैं

एक 'नया दलाल' जिसे पुराना दलाल खोज कर लाता है, बहलाकर, फुसला कर, भर्ती तभी किया जाता है जब पुराने दलाल ने इसकी सिफारिश की हो। नये दलाल का परिचय सी० आई० ए० के अधिकारी से न कराकर उस व्यक्ति के साथ कराया जाता है जिसका यह काम होता है कि वह हर सप्ताह रिपोर्ट लेकर अधिकारी को दे। मालिक और 'नौकर' के बीच सीधा सम्बन्ध रखने की आज्ञा नहीं है। कौन जाने किस वक्त यह राज खुल जाए और इसकी भयानक प्रतिक्रिया हो। जासूसों का यह जाल बिल्कुल खुफिया ढंग से काम करता है। जब नया दलाल भर्ती कर लिया जाता है तो उसका पुनः नामकरण किया जाता है यह नाम देशी नहीं विदेशी रखा जाता है। आदमी के नाम पर नहीं बल्कि जानवर के नाम पर। कोई 'ईगल' है तो कोई "कैमल," कोई "पैंथर" है तो कोई "रीनो"। यह नामकरण क्यों? इसलिए कि भेद खुल न जाए! इस नकली नाम पर उसे रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा जाता है—सप्ताह में कम से कम एक रिपोर्ट। हर रिपोर्ट के दाहिने कोने पर नकली नाम लिखा जाता है उसके साथ जिसका 'इण्टरव्यू' किया गया हो उसका नाम व तिथि। रिपोर्ट विस्तृत नहीं बल्कि खास-खास बातों के बारे में होती है। 'थोड़ा लिखो, लेकिन समझदारी से लिखो', 'थोड़ा मिलो लेकिन जानकार से मिलो।'

बस क्या है रिपोर्ट बनते ही पुराना दलाल उछलने लगता है कि आखिर मुर्गी पकड़ ली गई। प्रत्येक दलाल के लिए अपने सम्बन्ध में निम्नलिखित जानकारी देना अति आवश्यक है:

क—निजी जानकारी

१. क्या आप मदिरा सेवन करते हैं ?

२ क्या आपके परिवार के किसी भी सदस्य ने कभी आजादी की लड़ाई में भाग लिया है ?

३. आपका सम्बन्ध किस राजनैतिक दल से है ?

४. राजनैतिक दलों में आपके घनिष्ट मित्र कौन से हैं और कहा हैं ? आप उन्हें कब से जानते हैं।

५ आपका कार्य क्षेत्र कौन सा है—युवक, श्रमिक या पढ़े लिखे लोग।

६. आपका संक्षिप्त परिचय।

ख—राजनैतिक जानकारी

१. प्रगतिशील विचारधारा वाले किन व्यक्तियों को जानते हो, उनके नाम व ठहरने का स्थान ?

२. आप उन्हें कैसे जानते हैं ?

३. आप उन्हे कब-कब मिलते है ?

४. उनका कार्यक्षेत्र कौन सा है ?

जैसे ही नए व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ली जाती है तो उस व्यक्ति की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए उसे काम सौंप दिया जाता है। सबसे पहला काम उसके जिम्मे यह लगाया जाता है कि वह अपने सभी राजनैतिक जानकारों के बारे में, विशेषतया साम्यवादियों और उनके सहयोगियों के बारे में, यथा सम्भव जानकारी दे। इस लिस्ट की फिर जांच पड़ताल की जाती है और फिर इसके आधार पर उस नए व्यक्ति को कहा जाता है कि वह उन जानकार व्यक्तियों से अधिक घनिष्ट सम्पर्क बढाए। उसे हर सप्ताह एक रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है उसमे जिस व्यक्ति से जानकारी प्राप्त की जाती है उसका नाम और बातचीत का स्थान एवं तिथि लिखी जाती है। प्रत्येक रिपोर्ट फर्जी नाम पर प्रस्तुत की जाती है। हर दलाल को उसका वेतन मास के अन्त मे दिया जाता है। भारत पर चीनी आक्रमण से पहले मासिक वेतन की रसीद कमेटी 'टु कम्बेट कम्यूनिज़म' के नाम पर ली जाती थी परन्तु उसके बाद यह विभाग कुछ समय के लिए बन्द कर दिया गया

क्योंकि साम्राज्यवादियों की नज़र में 'साम्यवादियों की साख कमज़ोर होनी शुरू हो गई थी'। दक्षिण पूर्व एशिया के प्रमुख अधिकारी को भारत से वापिस बुला लिया गया और थोड़े समय तक कमेटी का काम धीमा पड़ गया।

यह रिपोर्ट तैयार होने के बाद उस व्यक्ति के माध्यम से जिसे 'मध्य पुरुष' कहा जाता है, भारतीय प्रमुख अधिकारी को दी जाती है जो इसे सी० आई० ए० के प्रमुख अधिकारी को पेश करता है। 'मध्य पुरुष' के ही माध्यम से सम्पर्क कायम रखा जाता है।

दिल्ली में कुछ ऐसे लोगों की खोज की गई जिन्हें पत्रकार होने के नाते यह प्रलोभन दिया गया कि यदि वह अमरीकी पुस्तकों का अनुवाद करें तो उन्हें पर्याप्त धनराशि दी जाएगी—एक पत्रकार को ५००० रु० केवल ५० पृष्ठ की पुस्तक का अनुवाद करने के लिए पेश किए गए लेकिन उस स्वाभिमानी पत्रकार ने चांदी के चन्द ठीकरों पर अपना ईमान बेचने से इन्कार कर दिया।

इसी प्रकार एक साप्ताहिक समाचार पत्र के सम्पादक से कहा गया कि यदि वह अपने समाचार पत्र में एक विशेष लेख सम्पादकीय के रूप में छापें तो उन्हें अच्छी धनराशि प्रदान की जा सकती है लेकिन इस शर्त पर कि लेख अमेरिकन सूचना विभाग का अधिकारी लिखेगा। यद्यपि सम्पादक के लिए इतनी बड़ी पेशकश को ठुकराना आसान नहीं था परन्तु उस गर्वीले पत्रकार ने यह कह कर इन्कार कर दिया कि 'मैं अपनी कलम नहीं बेच सकता'।

बिचौले को उसकी सेवाओं के उपलक्ष में दी जाने वाली धन राशि रिपोर्ट तैयार करने वाले से थोड़ी कम मात्रा में होती है। मज़े की बात यह है कि हर जासूसी करने वाले व्यक्ति को यह आश्वासन दिया जाता है कि जो काम वह कर रहा है वह न तो गैर कानूनी है और न ही सरकार विरोधी अपितु साम्यवाद के खतरे का मुकाबला करने के लिए एक 'राष्ट्रीय कार्य' है।

बस यह मूल मन्त्र है और वशीकरण मन्त्र भी। इसके इशारे पर नई-नई संस्थाएं खड़ी कर दी जाती हैं। प्रातः उठिए तो पता लगेगा कि :

'मस्जिद तो बना दी पल भर में,
ईमां की हरारत वालों ने।"

पलक झपकते ही नई संस्था बन गई, नए पैड छप गए, और कुछ ही दिनों बाद पता लगा कि अमरीकी सूचना विभाग के सहयोग से सदस्यों को फिल्म दिखाई जा रही है। आहिस्ता-आहिस्ता सम्बन्ध बढ़ते जाते हैं और यहाँ तक पेशकश की जाती है कि यदि आप चाहें तो अमरीकी 'उदारवादिता' के सहारे अमेरिका जाने का निमन्त्रण भी पा सकते हैं।

एक बार ऐसे ही एक व्यक्ति भारत आये जिनका जन्म भारत में हुआ था परन्तु उन्होंने अमरीकी नागरिकता प्राप्त कर ली थी। इस सज्जन का नाम मोधक था। यह भारत में इसलिए आए कि पता लगा सकें कि कही भारत साम्यवादी तो नही बन जाएगा। प्रारम्भिक जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्होंने दिल्ली मे कंस्टीट्यूशन क्लब मे कुछ दिनो तक निवास किया और इस दौरान वह कई लोगों से मिले। ऐसा लगता है कि उन्हें विश्वास हो गया था कि अधिक देर तक पूँजी के बल पर लोगों की इच्छाएं और आकांक्षाए दबाई नही जा सकती। आर्थिक ढांचे मे यथानुसार परिवर्तन आएगा उसे साम्यवाद भी कह दिया जाए तो भारतीय जनता को आपत्ति नही होगी। न तो हिन्दू की भूख अलग है न मुसलमान की, न ईसाई की पेट की ज्वाला अलग है, न सिक्ख की। भूखा पेट रोटी मागता है—भिखारी के रूप में नहीं बल्कि एक स्वाभिमानी की तरह। जब तक आर्थिक ढांचे में आमूल परिवर्तन नही कर दिया जाता, यह सघर्ष जारी रहेगा पूंजीवादी व्यवस्था को न तो पूंजीपति बचा सकते हैं, न पूंजी के दलाल। इसलिए वे लोग जो धन का प्रलोभन देकर गरीब जनता के स्वाभिमान की चुनौती देते हैं उन्हें कदापि यह भूलना नही चाहिए कि गरीबी से सताए हुए लोगों की भी मर्यादा होती है। जब गरीब लोगो के विचारों का ज्वालामुखी फूटेगा तो उसकी धधकती हुई ज्वाला में पूंजीवादी व्यवस्था टिक नही सकेगी। परन्तु फिर भी यह कोलाहल क्यो ? धन का लालच क्यों दिया जाता है ? खुफिया काम करने के लिए। यह खुफिया काम ही नही बल्कि षडयन्त्र है, स्वाभिमानी लोगों के खिलाफ, प्रगतिशील राष्ट्रों के खिलाफ, ताकि प्रगति के पथ पर बढ़ते हुए उनके कदम डगमगा उठें, वे अपनी मंजिल से भटक जाए और अमरीकी 'उदारवादिता' की शरण में इस प्रकार सो जाएं जैसे सौतेली मा किसी बच्चे को लोरी देकर नहीं बल्कि विषैला दूध पिलाकर हमेशा के लिए मौत की गोद में सुला दे।

मोधक के चले जाने के पश्चात भारत मे एक अमेरिकन नीग्रो जार्ज कार्टर का आगमन हुआ। यह वही व्यक्ति हैं जिन्होंने वर्ल्ड असेम्बली आफ यूथ की भारतीय कमेटी का 'पुनर्गठन' किया। जार्ज कार्टर दिल्ली स्थित मेडनज होटल में तीन दिन

तक ठहरे और पानी की तरह पैसा बहाते रहे और इस बीच कुछ 'लाभदायक व्यक्तियों' से अपना सम्पर्क बढ़ाने में सफल हो गए। यह इसलिए आवश्यक समझा गया क्योंकि उस समय वर्ल्ड असेम्बली आफ़ यूथ के साथ 'सैनिक गुटबन्दी' के प्रश्न पर झगड़ा हो गया था। भारतीय कमेटी ने जापान की सैनाइशन संस्था के साथ मिलकर वर्ल्ड असेम्बली आफ़ यूथ के सम्मेलन में एक प्रस्ताव पेश करके सैनिक गुट बन्दी का विरोध किया था। उस समय पश्चिमी देशों पर सैनिक गुटबन्दी का भूत सवार था और वे नहीं चाहते थे कि कोई भी युवक संस्था इस नीति का विरोध करे। चुनांचे पारित प्रस्ताव वाशिंगटन की नज़रों में खटकने लगा और वह इस 'हठधर्मी' का बदला लेने के लिए मौके की तलाश करने लगे। वर्ल्ड असेम्बली आफ़ यूथ के पैरिस स्थित मुख्य कार्यालय और नई कमेटी के बीच किन शर्तों पर समझौता हुआ यह भी एक बहुत बड़ा राज़ है।

वर्ल्ड असेम्बली आफ़ यूथ ने कुछ वर्षों के बाद अपना अधिवेशन दिल्ली में बुलाया जिसकी अध्यक्षता एक नीग्रो ने की। यह अधिवेशन कुछ दिनों तक दिल्ली में चलता रहा परन्तु किसी भी प्रतिनिधि ने सैनिक गुटबन्दी के विरोध में प्रस्ताव पास करना तो एक ओर रहा, एक शब्द भी न कहा। उसका कारण यह था कि सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि मण्डलों में पाकिस्तान मिलिट्री आपरेशन का युवक विभाग भी शामिल था। वर्ल्ड असेम्बली आफ यूथ के अध्यक्ष से जब इस प्रतिनिधि मण्डल के बारे में प्रश्न किए गए तो अध्यक्ष महोदय आएं बाएं शाएं करने लगे। इस सम्मेलन में युवक कांग्रेस का प्रतिनिधि मण्डल भी शामिल था परन्तु इस प्रतिनिधि मण्डल में उन लोगों का बहुमत था जो प्रकट रूप में तो भारतीय थे परन्तु दिल से वे अमरीकी नीति के समर्थक थे और वे नहीं चाहते थे कि वाशिंगटन वाले उनसे नाराज हों। शायद इसी बात पर दोनों के बीच गोपनीय समझौता हुआ था। जहाँ कहीं भी भारतीय भावनाओं का प्रश्न उठा, भारतीय कमेटी ने भूल से भी उनका प्रतिपादन नहीं किया। इस प्रकार की अन्तर्राष्ट्रीय सूझ-बूझ को यदि अन्तर्राष्ट्रीय दिवालियापन कहा जाए तो उचित होगा। जो लोग अपनी कार्यवाहियों से शान्त वातावरण को दूषित करते है उनके साथ समझौता करना गद्दारी नहीं तो क्या है। वे भूल जाते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय एकता का यह अर्थ नहीं कि आप अपने राष्ट्रीय हितों को तिलाञ्जली दे दें। १९६५ के भारतीय झगड़े में १५ अमरीकी विद्यार्थियों का एक टोला भारत आया था ताकि वे भारतीय विद्यार्थियों से अपने सम्बन्ध बढा सकें। वास्तव में उनका उद्देश्य यह जानना था कि अमरीकी नीतियों के प्रति भारतीय विद्यार्थियों की क्या प्रतिक्रिया है?

जब भारत में अमरीकी सरकार की नीतियों के प्रति लोगों ने रोष प्रकट करना शुरू किया तो अमरीकी दूतावास ने यह उचित समझा कि अमरीकी नीतियों के प्रति उचित वातावरण पैदा किया जाए और इस सम्बन्ध में दूतावास की ओर से कई लोगों को जिनका सम्बन्ध युवक या विद्यार्थी संस्थाओं से था को आमन्त्रित किया गया। मूलतया इन बैठकों का उद्देश्य था भारतीय लोगों में अमरीका की खोई हुई प्रतिष्ठा को स्थापित करना क्योंकि उस समय भारतीय लोग यह जान गए थे कि १९६५ के भारत-पाक झगड़े मे भारत के विरुद्ध प्रयोग मे लाए जाने वाले पैंटन टैंक अमरीकी थे, जो गोला बारूद पाकिस्तानियों ने इस्तेमाल किया वह भी अमरीकी था। पाकिस्तान ने जो भी अस्त्र-शस्त्र इस्तेमाल किए वे सब अमरीकी थे। जम्मू की सीमा पर यदि मन्दिर की दीवार गोला बारूद से गिरी तो इसके लिए अमरीका जिम्मेदार है और अम्बाला में गिर्जा बर्बाद हुआ तो इसकी जिम्मेदारी भी अमरीका पर है। वे लोग जो मौत की गोद में सदा के लिए सुला दिए गए उनकी आत्मा अमरीका को अवश्य बुरा भला कहेगी। जिस मां का बेटा इससे छीन लिया गया वह अमेरिका का गुणगान नही कर सकती, जिस बहिन का सिंदूर रौंद दिया गया वह अमरीकी सरकार की नीतियों की निन्दा क्यों नही करेगी। जब हर ओर से अमरीकी नीतियों की आलोचना की जाने लगी तो अमरीकी सरकार बोखला उठी। अमरीका के इतिहास में उस समय अमरीकी प्रतिष्ठा को जबर्दस्त धक्का लग चुका था। जब गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी तो गाधी जी ने हमे सिखाया था कि 'पाप से घृणा करो, पापी से नहीं'। हमने ऐसा किया भी बावजूद इसके कि हमारे देश के सैंकड़ों नर नारियों को साम्राज्यवाद के खिलाफ़ लड़ते हुए अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। इसलिए हम अमरीका या उनके लोगों के विरोधी नहीं हैं बल्कि अमरीकी नीति के विरोधी हैं।

हम अमरीकी सरकार की कोरिया और वियतनाम सम्बन्धी हस्तक्षेप की नीति के विरोधी हैं, हम अमरीकी सरकार के इसलिए भी विरोधी हैं क्योंकि अमरीका ने एक छोटे से राष्ट्र क्यूबा के खिलाफ अतिक्रमण किया है। अमरीका इसलिए भी बदनाम है कि इसने हिरोशीमा और नागा साकी में असहाय और निरीह जनता पर बम बरसा कर लाखों लोगों को मौत के घाट उतारा है, इसके अतिरिक्त अमरीका सैनिक समझौतों द्वारा छोटे-छोटे राष्ट्रों को धमकाता है और उनकी आजादी का सौदा करता है। हमारा यह शुरू से ही निश्चित मत है कि अमरीका की इस नीति का समर्थन नहीं किया जा सकता। भारतीय लोगों की बात तो अलग रही अमरीकी लोग भी अमरीकी सरकार की इन गलत नीतियों का विरोध करते है। इसका ज्वलन्त

उदाहरण है अमरीकी जहाजरानों और सैनिकों का वियतनाम युद्ध मे अमरीकी सरकार की ओर से हस्तक्षेप मे भाग लेने से इंकार करना, अमरीका में नवयुवको की ओर से भारी प्रदर्शन, जन अधिकारों की रक्षा के लिए आन्दोलन और एटमी बमों के प्रयोग के विरोध मे विशाल जन सभाएं। इन विरोध सभाओ और प्रदर्शनो से यह स्पष्ट हो जाता है कि अमरीकी लोगो के दिल में अपनी सरकार के प्रति कितना रोष है। परन्तु यदाकदा हमें ऐसे लोग भी देखने में आते हैं जिनका काम दिन रात अमरीकी नीतियो का गुणगान करना है। अमरीका उनका स्वाभिमान छीन ले, तो वह इसे अपना अहोभाग्य समझेंगे, उनकी इज्जत लूट ले तो उन्हें परेशानी नही होगी, और इन सब चीजों के उपलक्ष में कुछ डालर मिल जाएं तो वे इसे दैवी देन समझेंगे। इस प्रकार के पिछलग्गू हर देश मे मिलेंगे, उनकी सस्थाएं भी मिलेंगी, परन्तु इनसे सजग और जागरुक रहना चाहिए। उदाहरणतया 'कांग्रेस फार कलचरल फ्रीडम' और 'फोरम फार फ्री एंटरपराईज' ऐसी सस्थाएं हैं जो दूसरे के स्वर मे ही गा सकती हैं। न उनकी अपनी आवाज है न अपना अस्तित्व। पूंजीवाद का समर्थन करेंगी और समाजवाद का विरोध। उनकी नीति है कि 'गरीब गरीब रहे और अमीर अमीर'। वे यह भी चाहती हैं कि जन साधारण अपनी मांगे मनवाने के लिए सघर्ष नही करें बल्कि पूंजीपतियों से दया की भीख मागे। इन संस्थाओं को कई प्रकार से सहायता भी मिलती है। 'एन्काउंटर' समाचार पत्रिका के सम्पादक स्टीफन स्पेंडर ने अपने पद से इसलिए त्याग पत्र दिया क्योंकि यह सिद्ध हो चुका था कि इस पत्रिका को सी० आई० ए० से धन की सहायता मिलती रही है। अमरीका में छपने वाले एक समाचार पत्र ''रैम्पार्ट'' ने उन संस्थाओ की सूची भी प्रकाशित की है जिन्हे परोक्ष रूप में सी० आई० ए० से सहायता दी जाती रही है और यह भी स्पष्ट हो गया है कि किस प्रकार विशुद्ध घरेलू मामलों में विदेशी हस्तक्षेप को बढावा दिया जाता रहा है।

सी० आई० ए०, विरोधी-सस्थाएं बनाने मे भी चतुर है और मजे की बात तो यह है कि इन सभी ऐसी सस्थाओ के नाम और काम मे 'प्रजातान्त्रिक प्रणाली' का नाम मात्र समावेश भी रहता है। पुरानी सस्थाओ को काबू करने का काम यदि असफल रहे तो नई सस्था को जन्म देना ही उचित समझा जाता है। ये सस्थाएं नाम मात्र होते हुए भी कुछ न कुछ बेवकूफ बनाने मे सफल हो जाती हैं। न तो इन्हे धन का अभाव होता है न साधन का। न इनका सम्बन्ध सांस्कृति से है न स्वतन्त्रता से। ये स्वय धोखे मे रहती हैं और दूसरों को धोखा देती हैं।

एशिया फाऊंडेशन भी एक ऐसा सस्थान है जिसे सान फ्रासिसको के कुछ नागरिकों ने इसलिए स्थापित किया था कि 'एशिया में स्वतन्त्र समाज का निर्माण हो सके और लोगों को समान मौके प्राप्त हों'। इस सस्थान ने विश्व के कई देशों में अपना जाल बिछा रखा है। इस सस्थान के बोर्ड ग्राफ़ ट्रस्टीज मे प्रमुख हैं एलासवर्थ बकंर (भारत मे भूतपूर्व अमरीकी राजदूत), ग्रेसस एल० कर्क (कोलम्बिया विश्वविद्यालय के अध्यक्ष) एडविन ओ० बिसचावर (भूतपूर्व अमरीकी वित्तमन्त्री)। यह संस्थान भारतीय लोगो को शिक्षण प्राप्त करने के लिए धन आदि की सहायता करता रहा है। यह संस्थान साल भर में लगभग ३० लाख डालर खर्च करता है। इस संस्थान का एशिया सोसायटी के साथ भी गहरा सम्पंक है और इसी के माध्यम से माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों और प्रबन्धकों के लिए ग्रीष्मकालीन विद्यालय स्थापित किए गए हैं। कई संस्थाओं का नाम इस बारे में लिया जा चुका है। न्यूयार्क टाइम्ज ने 'अमेरिकन फंडज आफ इण्डिया' को भी सी० आई० ए० का ही अंग बताया है। इसके अतिरिक्त एक ऐसी ही संस्था 'फाऊंडेशन फ़ार यूथ एण्ड स्टुडेंटस अफेयरज़' है जो 'इण्टरनेशनल स्टुडेंटस कांफ्रेंस' की धन इत्यादि से सहायता करती रही है। इस कान्फ्रेंस का मुख्य कार्यालय लीडन में है और यह सस्था लगभग १०,००० डालर प्रतिवर्ष व्यय करती है। थोड़ा समय पहले इस संस्था का अध्यक्ष एक भारतीय नवयुवक था जो इस संस्था में नेशनल काउंसिल आफ़ यूनिवर्सिटी स्टुडेंटस आफ़ इण्डिया' का प्रतिनिधित्व करता था। जब इस सस्था के बारे में समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ कि इण्टरनेशनल स्टुडेंटस कांफ्रेंस को सी० आई० ए० से सहायता मिलती रही है तो इस सस्था ने मार्च १९६९ में अपने आप को भंग कर दिया। इसके स्थान पर थोड़ा समय हुआ एक नई संस्था स्थापित की गई है जिसका नाम है—इस्टीटयूट इण्टरनेशनल द–एत्यूदियां सुरल-एजूकेशम अर्थात शिक्षा के लिए विद्यार्थियों की अन्तर्राष्ट्रीय सस्था जिसका प्रमुख कार्यालय ब्रसल्ज (बेलजियम) में कायम किया गया है। यह संस्था नई अवश्य है परन्तु पुरानी सस्था का नया नामकरण है या यूं कह लीजिए कि 'पुरानी शराब नई बोतलों में' है।

फाऊंडेशन फ़ार यूथ एण्ड स्टुडेंट अफेयरज की ओर से नेशनल काउंसिल आफ यूनिवर्सिटी स्टुडेन्ट्स आफ इण्डिया को धन की सहायता मिलती रही है। आश्चर्य की बात है कि इस सस्था को इस बात की खुली छूट रही है कि यह विश्वविद्यालयों में स्वच्छन्दता से कार्य करती रहे और शिक्षा शास्त्रियों का आशीर्वाद भी प्राप्त रहे। यहां यह उल्लेखनीय है कि इस संस्था का ९९ प्रतिशत बजट अज्ञात सूत्रों से

पूरा होता रहा है। नेशनल काऊंसिल ग्राफ़ यूनिवर्सिटी स्टुडेंट्स ग्राफ इण्डिया की नीव विचित्र परिस्थितियों मे रखी गई। विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी सघों की एक गैर-प्रतिनिधि बैठक में, जिसे तत्कालीन अध्यक्ष यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का आशीर्वाद प्राप्त था, १९५८ में इसकी आधारशिला रखी गई। कुछ अज्ञात सूत्रों के दबाव के कारण इस सस्था को थोड़े समय तक सरकार से भी आर्थिक सहायता मिलती .रही है। आर्थिक सहायता बाद में इसलिए बन्द कर दी गई कि यह संस्था जांच पड़ताल के लिए अपना हिसाब-किताब पेश न कर सकी। शायद उसे इस बात का डर था कि राज खुल जाएगा। इसके अतिरिक्त एक सज्जन ऐसे भी थे जिनका हिसाब-किताब फर्स्ट सिटी बैंक न्यूयार्क में तब तक चलता रहा जब तक कि उसे बैंक के प्रमुख अधिकारी ने हिसाब-किताब बन्द करने की माग न की।

कहा जाता है कि नेशनल काऊंसिल ग्राफ दी यूनिवर्सिटी स्टुडेंट्स ग्राफ इंडिया विश्वविद्यालयों के छात्र संघों को सम्बद्ध करने वाली संस्था है। परन्तु वास्तविकता यह है कि अधिकाश विश्वविद्यालयों में छात्र संघ तो बने ही नही। ६५ में से केवल १७ विश्वविद्यालयों में छात्र संघ हैं जो नामाकित किए जाते हैं। ३५ विश्वविद्यालयों मे सघ का कोई अस्तित्व नही लेकिन फिर भी नेशनल काऊंसिल ग्राफ दी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ग्राफ इण्डिया अपने आपको सब से अधिक शक्तिशाली और ८० लाख विद्यार्थियो की प्रतिनिधि बताती है। यह सच है कि इस सस्था के अधिकाश पदाधिकारियो को इस सस्था को मिलने वाली धन राशि के सूत्रों का ज्ञान नहीं है परन्तु यह भी सच है कि यह सस्था अपने सभी राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दस्तावीजों मे लाखों विद्यार्थियो की प्रतिनिधि बन कर पेश होती रही है। 'लाखो विद्यार्थियो का प्रतिनिधित्व' करने वाली इस संस्था का राष्ट्रीय कार्यालय दिल्ली की डिफेन्स कालोनी मे रहा है और ऐसा सुनने में आया है कि इस सस्था का मासिक व्यय किसी भी राजनैतिक दल के मासिक व्यय से कम नही होगा ? इनकी बैठको और अधिवेशनो में चाहे कुछ ही लोग भाग लें, व्यय की कोई कमी नहीं होगी और यह आश्चर्य की बात नहीं कि १७ प्रतिनिधियो की विचार गोष्ठी में १७००० रुपया खर्च हो जाए। यह विचार गोष्ठी तभी सफल हो सकती है जब या तो काश्मीर की शीतल जलवायु हो या मसूरी का आनन्दमय वातावर्ण। आखिर इसमे कौनसी बुरी बात है ? परनाले की ईंट परनाले पर ही लगेगी। नेशनल काऊसिल ग्राफ यूनिवर्सिटी स्टुडेन्ट्स ग्राफ इण्डिया के छपे हुए कागजो पर इस बात का दावा किया जाता है कि इस सस्था को यूनिवर्सिटी ग्रांटस कमीशन और शिक्षा मत्रालय से मान्यता प्राप्त है परन्तु पता लगा है कि इसमे कोई सत्यता नही। कोई भी व्यक्ति किसी अन्य

व्यक्ति को बिना स्वार्थ के कुछ नहीं देता। जो जिस साज बजाने वाले को पैसा देगा, वैसा ही स्वर उसके साज से निकलेगा।

सी० आई० ए० के भूतपूर्व प्रमुख एलन डलेस ने १९६७ में सी० आई० ए० के कार्य की सराहना करते हुए कहा था :—

"सी० आई० ए० को जिस चीज की आवश्यकता थी उसे मिल गई अर्थात गोपनीय सूचना।' परन्तु बात यहां तक ही नहीं, इससे भी आगे है। इस समय जो संस्थाएं सी० आई० ए० के इशारे पर काम कर रही है उनमें उल्लेखनीय है :—

क) इण्टरनेशनल कांफ्रेंस आफ स्टुडेंटस।
ख) इण्डिपेंडेन्ट रिसर्च सर्विस आफ़ न्यूयार्क।
ग) वर्ल्ड असेम्बली आफ़ यूथ।
घ) कमेटी आफ कारेसपोंडेंस न्यूयार्क।
ङ) दि पैन अमेरिकिन फाऊंडेशन।
च) दि अमेरिकिन सोसायटी आफ अफ्रीकन कलचर।
छ) दि इण्टरनेशनल मार्किट इन्स्टीट्यूट।
ज) दि अमेरिकिन फ्रेंडज आफ़ दि मिडल ईस्ट।
झ) इण्टरनेशनल डिवेलपमेंट फाऊडेशन आफ न्यूयार्क।
ञ) इण्टर नेशनल यूनियन आफ़ यग क्रिश्चन डेमोक्रेटस।
ट) नेशनल स्टुडेन्टस एसोसियेशन इन केनेडा।
ठ) यूनिवर्सिटी आफ म्यािमी।
ड) इण्टरनेशनल कनफेडरेशन आफ फ्री ट्रेड यूनियनज।
ढ) दि कोआपरेटिव लीग आफ़ अमेरिका।
ण) इण्टर नेशनल लेबर रिसर्च इन्स्टीट्यूट।
त) कार्फ्रेस आफ दि एटलांटिक कम्यूनिटी।
थ) इण्टरनेशनल सेक्रीटेरियेट आफ दि पैक्स रोमाना।
द) वेस्ट बर्लिन यूनियन फार दि एडवांसमेंट आफ एजूकेशनल ऐड इन डिवेलिपग कण्टरीज।
ध) इण्टर नेशनल प्रेस इन्स्टीट्यूट।
न) न्यूज पेपर गिल्ड आफ अमेरिका।
प) इण्टर नेशनल जरनलिटस्ट्स कांफ्रेंस इन जेनेवा।

फ) इण्टरनेशनल फेडरेशन ग्राफ जरनलिस्ट्स इन ब्रसल्ज़।

ब) रेडियो फ्री यूरोप।

भ) रेडियो लिब्रेशन।

म) रेडियो फ्री एशिया।

इन संस्थाओं को सी० आई० ए० की सिफारिश पर भिन्न-भिन्न संस्थानों से आर्थिक सहायता मिलती है। इन सस्थानों के नाम इस प्रकार हैं :—

१) टावर फंड।

२) गोथम फाऊंडेशन।

३) बोर्डन ट्रस्ट।

४) बेकन फण्ड।

५) पराइस फण्ड।

६) हाईट्स फण्ड।

७) विलफोर्ड–टेलफोर्ड फण्ड।

८) एडसल फण्ड।

९) सान मिगुअल फण्ड।

१०) काण्टफील्ड फण्ड।

११) मुनरो फण्ड।

१२) मिशिगान फण्ड।

१३) एन्डरू हैमिल्टन फण्ड।

१४) अपालिशन फण्ड।

१५) विनेवुड फण्ड।

१६) चार्ल्स पराईस विट्न फण्ड।

१७) जेम्ज कारलायल ट्रस्ट।

१८) एम० डी० एन्डरसन फाऊंडेशन।

१९) होब्लीजेल फाऊंडेशन।

२०) जे० एम० काप्लन फण्ड इन कारपोरेशन

२१) बेयरड फाऊंडेशन।

२२) जे० फ्रेड्रिक ब्राऊन फाऊंडेशन।

२३) रेब चेरिटेबल फाऊंडेशन।

२४) मार्शल फाऊंडेशन।

इसके अतिरिक्त कई संस्थाए और सस्थान ऐसे भी हैं जिनके नाम इसमें दर्ज किए जा सकते हैं। जब पहली बार दिल हिला देने वाली गाथा अमेरिकन नेशनल स्टुडेन्ट्स एसोशियेशन के पदाधिकारी से सुनी गई तो उसे इस बात की धमकी दी गई कि राज खोलने पर उसे जेल यात्रा करनी पड़ेगी और भयकर परिणामों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन वह नवयुवक तो निश्चय कर चुका था "तुम तीर आजमाओ, हम जिगर आजमाए" और यह भी कि सच बोलने वाला भयंकर परिणामों की चिन्ता नहीं करता। उस नवयुवक ने बताया कि सी० आई० ए० के दलाल व्यक्तियों के बारे में और विद्यार्थी सस्थाओं की राजनीति के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। लगभग २० संस्थान ऐसे हैं जिनकी नींव रखते समय उन्हे 'बेनामी' बनाया गया था। संस्थान का नाम तो केवल बाहरी दिखावा है, काम तो सब सी० आई० ए० का है। कई वर्षों से अन्तर्राष्ट्रीय सगठनों के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष सी० आई० ए० से बाकायदा वेतन पाते रहे हैं। इन्हें जासूसों की श्रेणी मे भर्ती करने से पहले सौगन्ध खानी पड़ती है कि वे हर बात गोपनीय रखेंगे और उन्हे यह भी चेतावनी दी जाती है कि यदि उन्होंने कोई भेद खोला तो उन्हें भारी क्षति उठानी पड़ेगी। जिन विद्यार्थियों को जासूसों की श्रेणी में शामिल किया जाता है उन्हें अमरीकी खुफिया विभाग के कोड में 'विट्टी' कहा जाता है।

न्यूयार्क टाइम्ज में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार दिल्ली मे इन्टरनेशनल यूथ सेन्टर, दि नेशनल स्टुडेंटस प्रेस काऊसिल आफ़ इण्डिया और दि फ्रेन्डज़ आफ़ इण्डिया ट्रस्ट को फाऊंडेशन आफ़ यूथ एण्ड स्टुडेंट अफेयरज़ तथा कैंथर वुड फाऊंडेशन से आर्थिक सहायता मिलती रही है। नेशनल काऊंसिल आफ़ दि यूनिवर्सिटी स्टुडेंटस आफ़ इण्डिया के भूतपूर्व एग्जिक्यूटिव सेक्रेट्री ने हिन्दुस्तान टाइम्ज दिनांक २१ फरवरी १६७० में एक वक्तव्य द्वारा कहा :—

> "एक योजना के लिए हमें अवश्य ही थोड़ी सी आर्थिक सहायता फाऊंडेशन फार यूथ एण्ड स्टुडेंट अफेयरज, न्यूयार्क से प्राप्त हुई थी। परन्तु हमे रत्तीभर भी सदेह इस सस्थान की गतिविधियों के बारे में न था। हमे इस बात का बिल्कुल ज्ञान न था कि इस संस्थान को सी० आई० ए० से सहायता मिलती है।'

हमे आश्चर्य है कि अज्ञानता का सहारा निजि बचाव के लिए कैसे लिया जा सकता है। जब तक समाचार पत्रों में सी० आई० ए० के बारे में छपा नही तब

तक तो यह बात ठीक थी कि वह अज्ञानता के शिकार थे परन्तु जानकारी होने के बाद कोई भी समाचार सी० आई० ए० की गतिविधियों का खण्डन करने के बारे में नही आया और या अगर आया भी होगा तो समाचार पत्रों ने अनावश्यक समझकर कहीं फेंक दिया होगा। यदि सूझ बूझ रखने वाली संस्था अज्ञानता का बहाना करे तो यह कोरा झूठ है। इण्टरनेशनल स्टुडेन्ट्स कौंसिल, जो १९६९ में भंग की जा चुकी है, का महामन्त्री एक भारतीय युवक था। केनेडा के विद्यार्थी नेता डेविड यंग ने सी० आई० ए० पर आरोप लगाया है कि इस संस्था ने अन्तर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठी में भाग लेने के लिए केनेडा के विद्यार्थियों को नामांकित किया था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि फाऊंडेशन फ़ार यूथ एण्ड स्टुडेन्ट अफेयरज की ओर से विचार गोष्ठियों के आयोजन के लिए आर्थिक सहायता मिलती रही है।

२३ फरवरी १९६८ को भारत में मनोनीत एशिया फाऊंडेशन के प्रतिनिधि रिचर्ड जी० हेगी ने स्वीकार किया कि यह सस्थान विभिन्न संस्थाओं को वर्ष में ४००,००० डालर की सहायता प्रदान करता रहा है, जिसमे अनुसधान का कार्य भी सम्मिलित है। भारत की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने ६ मार्च १९६८ को सदन पट पर बोलते हुए कहा था कि एशिया फाऊडेशन को सी० आई० ए० से धन मिलता रहा है और इस बात की कोई गारंटी नही कि भविष्य मे यह सहायता न मिले। एशिया फाऊडेशन भारत में कई योजनाओं के लिए आर्थिक सहायता देती रही है। इसी कारण भारत सरकार ने एशिया फाऊडेशन को अपनी कार्यवाहियां भारत में बन्द कर देने का आदेश दिया है। केन्द्रीय गृह मत्री ने संसद में २३ फरवरी १९६८ को बताया कि फाऊडेशन को सी० आई० से आर्थिक सहायता मिलती रही है इसलिए इसकी कार्यवाहिया आपत्तिजनक हैं।

सी० आई० ए०, सांस्कृतिक गतिविधियों, कलाकारो, खिलाडियो, प्रदर्शनियो और यात्रियों से सम्बन्धित संस्थाओं मे भी घुस पैठ करती है ताकि उन लोगो के जिन्हें एक देश से दूसरे देश में जाने की सुविधा रहती है, माध्यम से अन्य देश के लोगों के साथ सपर्क बढाया जा सके। भारतीय ससद में सभी दल के सदस्यों ने सी० आई० ए० की गतिविधियो पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह सस्था विभिन्न ढंगों मे राजनैतिक, शैक्षणिक और साहित्यिक क्षेत्रो में हस्तक्षेप कर रही है और उनकी गतिविधियों का संचालन भी करती है। केन्द्रीय जाच ब्यूरो की रिपोर्ट के आधार पर केन्द्रीय गृह मंत्री ने ६ दिसम्बर १९६७ को संसद मे बताया कि भारत में इन गति-विधियो को रोकने के लिए यथोचित कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा

कि सी० आई० ए० विद्यार्थी समुदाय का शोषण भी कर सकती है इसलिए सजग रहना आवश्यक है। अमरीकी गुप्तचर विभाग का वार्षिक बजट अमरीका के कुल बजट का छटा भाग है और इस विशाल धन राशि के कारण सी० आई० ए० ने सेना मे और शासकीय विभागो तथा निजि संस्थाओं में अपने पाँव जमा रखे हैं। १९ दिसम्बर १९६७ को न्यूयार्क टाईम्ज में प्रकाशित एक समाचार में यह लिखा गया था कि वाईट हाऊस पेनल के सदस्यों में इस विषय पर तीव्र मतभेद पाया जाता है कि सी० आई० ए० को खुले रूप से अन्य सस्थाओं को आर्थिक सहायता देने की छूट दी जाए या न। इस पेनल के अध्यक्ष डीन रस्क थे। समाचार में यह भी बताया गया कि ३१ दिसम्बर की निर्धारित सीमा तक इस पेनल की रिपोर्ट राष्ट्रपति को नही भेजी जा सकती। इसके अतिरिक्त इस पेनल ने अपना कार्य क्षेत्र भी चार योज-नाओं तक ही सीमित रखा है। इसका उद्देश्य यह है कि उन संस्थाओं को जिन्हे सी० आई० ए० से सहायता मिलती रही है चालू वर्ष के लिए सहायता दी जाती रहे और इसके साथ-साथ नीम-अधिकारी संस्था बनाने का काम भी शुरू किया जाए जो कि आहिस्ता-आहिस्ता विदेशों में शिक्षा और साहित्य संबंधी कार्यवाहियों को चला सके। इसी कार्य की पूर्ति के लिए उस समय राष्ट्रपति लिंडसन जानसन ने १९ सदस्यों पर निर्मीत डीन रस्क की अध्यक्षता मे एक समिति का निर्माण ६ अप्रेल १९६७ को किया था ताकि इस विषय पर विचार किया जा सके कि विदेशों मे विद्यार्थी संस्थाओं और अन्य गुटों को खुले रूप से आर्थिक सहायता कैसे प्रदान की जाए। इस समिति के निर्माण की आवश्यकता इसलिए पडी क्योंकि नेशनल स्टुडेन्ट्स एसोसिएशन के पदा-धिकारियों ने सी० आई० ए० पर आर्थिक सहायता करने का आरोप लगाया था और कहा था कि गत १५ वर्षो से सी० आई० ए० जासूसी करने का काम करती रही है।

सी० आई० ए० इस बात का निरन्तर प्रयास करती है कि अन्य देशों में लोगों के विचारो को निश्चित दिशा प्रदान करने के लिए समाचार पत्रों की सहायता ली जाए। लगभग १० लाख डालर १९६१ मे अमेरिकन न्यूज पेपर गिल्ड को इसलिए दिए गए ताकि अमरीकी जनता के विचारों को नई दिशा दी जा सके। इस गिल्ड के अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क का लाभ उठा कर और यह भी जानते हुए कि यह गिल्ड इण्टरनेशनल फेडरेशन आफ जरनलिस्टस इन बरसल्ज से तथा इण्टर अमेरिकन फेडरेशन आफ़ जरनलिस्टस इन पनामा से सम्बद्ध है इस बात का प्रयास किया गया कि समाचार पत्रों में काम करने वाले कर्मचारियो, समाचार एजसियों और रेडियो सम्बन्धी सस्थाओं मे नए चेहरे ढूंढे जा सकें जो सी० आई० ए० के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हों। इस गिल्ड को आर्थिक सहायता के लिए धन राशि हेमिल्टन

फाऊंडेशन इन फिलेडेलफिया से प्राप्त हुई जो कि सी० श्राई० ए० की ही संस्था है। इतनी बड़ी धन राशि देने का अभिप्राय: यह था कि गिल्ड के सदस्य डालर की माया से प्रसन्न होकर अन्य देशों के पत्रकारों के साथ सम्बन्ध बढ़ाकर उनके आगे अमरीकी नीतियों का समर्थन करें। एक भारतीय युवक नेता जो सी० श्राई० ए० की दलाली करता रहा है, ने बताया कि १६६० में उसने सी० श्राई० ए० के माध्यम से भारत में होने वाली एक आवश्यक राजनैतिक बैठक में अमरीकी प्रतिनिधि मण्डल भेजने का निर्णय कराया था ताकि उस बैठक में भाग लेने वाले चीन और रूस के प्रतिनिधि मंडलों को सम्मेलन से अलग किया जा सके। यह प्रमाण है सी० श्राई० ए० द्वारा राष्ट्रीय एव अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर युवकों व विद्यार्थियों में हस्तक्षेप का। इस नवयुवक को वियाना मे हुए विश्व युवक मेले के समय फांसा गया था और इसके बाद १६६० में हुई श्राकरा की बैठक मे नेशनल स्टुडेन्ट्स एसोसियेशन आफ़ अमेरिका ने इस नवयुवक को सी० श्राई० ए० के जाल में भर्ती करने पर राजी कर लिया था। श्राकरा में हुई बैठक के तीन महीने बाद, इस नवयुवक को सी० श्राई० ए० से सूचना प्राप्त हुई कि एक भारतीय नवयुवक नेता जो श्राकरा बैठक मे मौजूद था, सी० श्राई० ए० का भी दलाल था। क्योंकि कुछ भारतीयों ने चीन और रूस से प्रतिनिधि बुलवाए हुए थे इसलिए वह चाहता था कि इस सम्मेलन मे अमरीकन भी भाग लें ताकि तटस्थता की नीति न अपनाई जा सके। इस नवयुवक को इसलिए पूरा खर्चा देकर भेजा गया कि वह यह काम कर सकता था। परिणाम स्वरूप नई दिल्ली से श्राकरा का हवाई जहाज़ का टिकट दे दिया गया।

अमरीकी सरकार परोक्ष रूप से अमेरिकन सेंट्रल ट्रेड यूनियन आर्गेनाईजेशन की इसलिए सहायता करती रही है ताकि इस सस्था द्वारा विश्व के अन्य नवोदित राष्ट्रों मे क्रांति-विरोधी भावना पैदा की जा सके। इससे पूर्व इस संस्था का सारा खर्चा सी० श्राई० ए० एक फर्जी फाऊंडेशन द्वारा अदा करती रही है। सी० श्राई० ए० का पैसा देने का काम यूनाइटड स्टेट्स एजेंसी फार इण्टरनेशनल डिवेलपमेंट के हवाले कर दिया गया है इस नई सस्था से जिन अमरीकी सस्थाओं को सहायता दी जा रही है उनमें अमेरिकन सेंट्रल ट्रेड यूनियन आर्गेनाईजेशन भी शामिल है। इस के माध्यम से अमेरिकन रिटेल कलर्कस इण्टरनेशनल और इण्टरनेशनल फेडरेशन आफ़ पेट्रोलियम एण्ड केमीकल वर्कर्ज को आर्थिक सहायता दी जाती है। यूनाईटिड स्टेट्स एजेंसी फार इण्टरनेशनल डिवेलपमेंट को क्षेत्रीय लेबर संस्था बनाने के लिए भी सहायता दी जाती रही है। अमेरिकन सेंट्रल ट्रेड यूनियन आर्गेनाईजेशन

(एफलशिग्रो) के माध्यम से दी जाने वाली आर्थिक सहायता के लिए किसी भी देश में उनकी अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस स्थान पर सी० आई० ए० को पीछे हटने पर विवश होना पड़ा है उन स्थानों पर सी० आई० ए० का कार्य चलाने के लिए नई संस्थाओं को जन्म दिया जा चुका है ताकि यह ज़ाहिर हो सके कि नई सस्था कलुषित नहीं है।

सी० आई० ए० के लिए कोई भी ढग अपनाना बुरा नही। जैसे तैसे काम बनना चाहिये चाहे उसके लिए कुछ भी क्यों न करना पड़े। यही कारण था कि एक रूसी वैज्ञानिक को फांसने के लिए प्रेम-जाल फैलाया गया और एक सुन्दरी की सेवएं प्राप्त करके उस वैज्ञानिक को थोड़े समय के लिए अमेरिका में शरण लेने के लिए तैयार किया गया। यह आरोप रूसी समाचार पत्र 'इजवेस्तिया' के ६ फरवरी १९६८ के पर्चे में छपा। घटना इस प्रकार है : सी० आई० ए० ने एक अमरीकी वैज्ञानिक की धर्मपत्नी को डालरों का लालच देकर कहा कि वह रूसी वैज्ञानिक को, जो अन्तर्राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन में भाग लेने के लिए आया हुआ था, प्रेम जाल मे फंसाए। इस तरह वशीभूत करने के पश्चात रूसी वैज्ञानिक को वियाना स्थित होटल के कमरे से इस तरह निकाला गया कि कानों कान इसकी खबर भी न हो। इस प्रमिका ने बड़ी चतुराई के साथ रूसी वैज्ञानिक को पश्चिमी जर्मनी में सी० आई० ए० के दलालों के हवाले कर दिया जिन्होने इस वैज्ञानिक पर दबाव डाला कि वह रूसी विज्ञान सम्बन्धी भेद बताए। जब उसे मजबूर किया गया तो उसके सिर से प्रेम का भूत उतर गया। उसने सोचा कि प्रेम-पाश में फंसा कर उसे अपने ही देश के ख़िलाफ़ जासूसी करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। प्रेम का तिलसिम टूटते ही वह रूसी वैज्ञानिक वहाँ से भाग निकला और वापिस अपने देश आ पहुँचा। वियाना से पश्चिमी जर्मनी लाते समय रूसी वैज्ञानिक को जो पासपोर्ट सी० आई० ए० ने दिया वह जाली था और उसमें उस वैज्ञानिक को एक सैनिक अधिकारी दिखाया गया था और उसे चुपके चुपके पश्चिम जर्मनी में फ्रेंकफर्ट लिवाया गया था।

यह एक अनोखा ढंग है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को प्रेम-जाल मे फास कर जासूसी करने पर विवश कर दिया जाता है। मनुष्य की कमजोरी का लाभ उठाकर जब उसे प्रेम के फंदे में जकड लिया जाता है तो फिर नशीली आंखों से ओझल होना कठिन हो जाता है। उसकी अपनी कमजोरी उसके लिए कठिनाईयां पैदा कर देती हैं। वह भागना चाहता है तो प्रेमिका उसे अपनी बाहों में जकड़

होती है। वह जानता है कि इस स्त्री का प्रेम केवल दिखावा है लेकिन उसके हाव-भाव से कुछ क्षणों के लिए प्रभावित हो जाता है। बस, यह थोड़े से क्षण ऐसे हैं जिनमें वह स्त्री भेद जानने का प्रयास करती है क्योंकि वह भी जानती है कि वह उस मनुष्य के साथ प्रेम दिल से नहीं बल्कि अपने अधिकारियों की आज्ञा का पालन करने के लिए कर रही है।

अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में प्रायः इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। उन स्थानों पर ही यह सम्भव है जहाँ मेलजोल की आज़ादी हो। यह सम्बन्ध आने वाले सम्मेलनों में भी कायम रखे जाते हैं और तब तक यह काम जारी रहता है जब तक कि पूरा भेद हासिल न कर लिया जाए।

सी० आई० ए० वाले साम, दाम, दण्ड, भेद, चारों ढंग अपनाते हैं। परन्तु यह बात अलग है कि अधिकांश लोग इन चक्र से बच निकले हैं और उन्होंने सी० आई० ए० की गुप्तिया गतिविधियों पर प्रकाश डाला है। उनकी आवाज एक चेतावनी है उन लोगों को जो सम्भवतः इस चक्र में उलझे हुए हैं।

युवक मंच पर

सी० आई० ए० के दो तरुण मोर्चे है—युवको के लिए वर्ल्ड असेम्बली आफ़ यूथ (वेय) और विद्यार्थियों के लिए इण्टरनेशनल स्टुडेन्ट्स कांफ्रेंस (यह संस्था अब तोड़ दी गई है क्योंकि इस संस्था पर आरोप लगाया गया था कि इसका पूरा संचालन सी० आई० ए० करता था)।

दोनों संस्थाए पश्चिमी रंग में ढली हुई हैं। एक नहला है तो दूसरा दहला। ये हमेशा इस ताक में रहती हैं कि किसी न किसी प्रकार कोई शिकार फंस जाए। इन संस्थाओं के तौर तरीके अन्य संस्थाओं से भिन्न है। स्वाल गंदम जवाब चना। न इनको विद्यार्थियों के हित से कोई लगाव है न युवकों की समस्याओं से। दोनों संस्थाएं सी० आई० ए० की हिज मास्टर वायस् है। इनका अपना कुछ नहीं सब बेगाना है। पूरी की पूरी संस्था गिरवी रखी हुई है। इसके उपलक्ष में इन संस्थाओं के जिम्मे केवल यही काम है कि ऐसे युवकों का गुट तैयार किया जाए जो युवक आन्दोलन मे बराबर शीत युद्ध जारी रख सकें ताकि युवा शक्ति बट जाए और युवकों की क्रातिकारी परम्पराओं को ठेस लगती रहे। युवक राग रंग में मस्त होकर आन्दोलन करना भूल जाएं। युवक देश भक्ति का मही प्रेम का राग अलापें और परिस्थितियों के गुलाम बन जाए।

विश्व युवक संस्था (वर्ल्ड असेम्बली आफ़ यूथ) तटस्थ रहने की नीति और विश्व शान्ति का विरोध करती है। स्वतन्त्रता के लिए जूझ रहे लोगों का समर्थन करना तो बहुत बड़ा प्रश्न रहा, इस संस्था ने भूल से भी कभी स्वतन्त्रता प्रिय लोगो का साथ नही दिया। पश्चिमी गुट बन्दी के दायरे में संस्था की नीतियों को सीमित रखना ही इसका मुख्य उद्देश्य रहा है और इसी भावना को लेकर नवोदित राष्ट्रों मे

युवक आन्दोलन की जड़ें खोखली की जाती रही हैं। यह अलग बात है कि भारी कोशिशों के बावजूद इस संस्था को हर स्थान पर मुंह की खानी पड़ी है। इसी संस्था की सब कार्यवाहियां गुप्त रूप से अमेरिका द्वारा संचालित की जाती हैं क्योंकि अमेरिका के कम्यूनिस्ट–विरोधी कट्टर पंथियों को विश्वास है कि प्रगतिशील युवक आन्दोलन ही साम्राज्यवादी शक्तियों से टक्कर ले सकता है इसलिए वे लोग इस संस्था के माध्यम से प्रगतिशील नीतियों का विरोध करना ही उचित समझते हैं।

यही कारण है कि इस संस्था की कार्य-प्रणाली व सोचने का ढंग प्रजातांत्रिक प्रणाली से मेल नहीं खाता। सम्भवतः यही कारण है कि राष्ट्रीय समितियों का गठन चुपके-चुपके कर दिया जाता है और उन्हीं लोगों को संस्था का पदाधिकारी बनाया जाता है जो अपना दिल-व-दिमाग दूसरे के पास गिरवी रखने को तैयार हों। परिणाम स्वरूप इस प्रकार की संस्थाएं तोड़ने-फोड़ने व विघटनकारी कार्यवाहियों का केन्द्र बन जाती हैं।

दुःख का विषय है कि ऊपर लिखित विश्व की दोनों संस्थाओं से सम्बद्ध संस्थाएं भारत मे भी मौजूद है। उनका जन्म क्यों और कैसे हुआ यह जानने के लिए इतिहास के कुछ पन्ने उलटने पड़ेंगे।

दो विश्व युद्धो के बीच ऐसा दिखाई देता था कि सारा संसार सुकड सा गया हो। वैज्ञानिक प्रगति के बढ़ते हुए चरणों ने समय पर विजय प्राप्त कर ली। उस समय की स्थिति से यह आभास होने लगा कि यदि विश्व के किसी एक कोने मे कोई घटना घटित हुई तो उसकी प्रतिक्रिया विश्व के दूसरे कोने मे देखी जा सकेगी।

युद्ध की भीषण प्रतिक्रिया ने शान्तिप्रिय लोगो के हृदय मे नई चेतना पैदा की। अन्तर्राष्ट्रीय एकता की भावना सर्वप्रथम मजदूर वर्ग में दिखाई देने लगी और यह बात सिद्ध हो गई कि आम जनता के हितों को तिलांजलि देकर कोई राष्ट्र उन्नत होने का दम नहीं भर सकता। यद्यपि विश्व के कोने-कोने में रहने वाले लोग धर्म, भाषा, जाति, रंग व खान-पान के आधार पर एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं परन्तु आशाओं और आकांक्षाओं को किसी भी बंधन में जकड़ा नहीं जा सकता। वे सब नव-निर्माण के द्योतक हैं और विश्व शान्ति के प्रहरी।

यही कारण है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं का गठन शुरू हुआ जिनका उद्देश्य मित्रता और शान्ति के लिए निरन्तर प्रयास करना था ताकि

आने वाला संसार युद्ध के भीषण परिणामों से सुरक्षित रखा जा सके। इसी प्रकार राष्ट्रीय संस्थाओं से भी यह आशा की जाने लगी कि वे भी राष्ट्रीय शक्ति एवं जन-मानस के कल्याण की भावनाओं का परिचायक बनेंगी। विश्व तानाशाही के पंजे से मुक्त होगा, आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक शोषण की दीवारें गिरा दी जाएंगी।

परन्तु युद्ध के विषैले कीटाणु अन्दर ही अन्दर रेंगते रहे और समय पाकर शान्त वातावर्ण को दूषित करते हुए दिखाई देने लगे। वर्ल्ड असेम्बली आफ़ यूथ इन्हीं विषैले कीटाणुओं का मूर्त रुप है जिसका काम घिनौना है, जिसकी हर कार्य-वाही में बन्धुत्व-विरोधी भावनाओं का समावेश है और केवल उन्ही नीतियो का समर्थन करना है जो लड़खड़ाते हुए साम्राज्यवाद को सहारा दे सकें।

१९४५ में लन्दन में पहला अन्तर्राष्ट्रीय युवक सम्मेलन हुआ जिसमे वर्ल्ड फेडरेशन आफ़ डेमोक्रेटिक यूथ की स्थापना की गई। तीन वर्ष पश्चात १९४८ मे लन्दन में एक अन्य सम्मेलन अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, केनेडा, बेल्जियम, डेन्मार्क और नीदर लैंड के इशारे पर बुलाया गया और इस सम्मेलन में एक नई संस्था 'वर्ल्ड असेम्बली आफ यूथ' की रूप रेखा तैयार की गई और एक वर्ष बाद एक नई संस्था का जन्म हुआ।

युवकों के लिए यह जानना स्वाभाविक था कि आखिर दो संस्थाओं को स्थापित करने की क्या आवश्यकता थी ?

वर्ल्ड असेम्बली आफ यूथ द्वारा प्रसारित प्रचार सामग्री में लिखा है कि जब इस संस्था का जन्म हुआ उस समय 'अन्तर्राष्ट्रीय समाज सेवी संस्थाओं का विचार अपनी चरम सीमा पर था'। युद्ध की भीषण प्रतिक्रिया के पश्चात विश्व के शान्त वातावर्ण मे आग लगाने का काम ब्रिटेन की राष्ट्रीय युवक संस्थाओ की तदर्थ समिति के जिम्मे लगा और उसी ने ही यूरोप की अन्य युवक संस्थाओ के साथ सम्पर्क बढाने का काम प्रारम्भ किया, इसी लन्दन सम्मेलन मे युवको मे शीत युद्ध आरम्भ करने की पृष्ठ भूमि तैयार की गई जो कुछ समय बाद सिद्धहस्त साबित हुई। इसका ज्वलंत उदाहरण है वर्ल्ड असेम्बली आफ़ यूथ का गत २५ वर्षो का इतिहास जिसके हर पन्ने पर अमिट दाग लगे हुए हैं। वे दाग इसलिए अमिट हैं क्योंकि वर्ल्ड असेम्बली आफ यूथ ने अपनी घिनौनी गतिविधियों से युवक आन्दोलन को साम्राज्य-वाद का पिछलग्गू बनाने का दुसाहस किया है। इस संस्था का सदैव यही मुख्य उद्देश्य रहा है कि किस प्रकार साम्यवाद का विरोध किया जाए ताकि अमेरिकन ढंग की

प्रजातान्त्रिक प्रणाली जिसे अमेरिका में 'जन-पूंजीवाद' की संज्ञा दी जाती है विश्व के अन्य देशों में भी पनप सके। इस संस्था का जनहित, प्रगति और स्वाधीनता से उतना ही प्रेम है जितना अमेरिका को सैनिक गुट बन्दी, मार्शल प्लान और आईक सिद्धान्त से। क्योंकि इन सब कार्यवाहियों के पीछे एक ही भावना काम करती है कि किस प्रकार नवोदित राष्ट्रों को आर्थिक गुलामी की जंजीरों मे पुनः जकड़ा जा सके

वर्ल्ड असेम्बली आफ़ यूथ की प्रत्येक नीति से भेदभाव की बू झलकती है यह संस्था काले और गोरे के प्रश्न पर रग-भेद नीति का विरोध करने की हिम्मत नहीं रखती। यही कारण है कि जब दक्षिण अफ्रीका मे गोरी चमड़ी वाले युवकों ने एक ही समिति में काली चमड़ी वाले युवको के साथ बैठने से इंकार कर दिया तो वर्ल्ड असेम्बली आफ़ यूथ ने एक ही देश में दो राष्ट्रीय समितियों को मान्यता देकर प्रमाणित कर दिया कि यह संस्था म्लान सरकार की रंग-भेद नीति के आगे केवल घुटने ही नहीं टेक सकती वरन् अपनी नीतियों को भी कुर्बान कर सकती है वह उभरते हुए जवानों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करें और नवयुवक शान्त रहें यह कैसे सम्भव हो सकता है ?

एक ओर तो वर्ल्ड असेम्बली आफ़ यूथ रंग-भेद नीति के प्रश्न पर अपना ईमान गिरवी रख चुकी है और दूसरी ओर लोगो की आखो मे धूल झोकने के लिए एक नीग्रो को अपनी संस्था के प्रधान पद पर सुशोभित भी कर सकती है। हाथी के दांत खाने के और, दिखाने के और। जब दक्षिण अफ्रीका के युवको का प्रश्न इस संस्था के सम्मुख रखा गया तो इसी संस्था ने अपनी एक विज्ञप्ति मे कहा :

> "ऐसा लगता है कि यदि दक्षिण अफ्रीका में दो राष्ट्रीय समितिया (यूरोपियन और गैर यूरोपियन) काम करती रहे तो यह निश्चित ही हमारी सफलता का प्रमाण होगा ...... यदि इस प्रकार दो अलग २ समितिया बना दी जाएं तो ऐसी अवस्था में प्रत्येक समिति को अपने प्रतिनिधि वर्ल्ड असेम्बली आफ़ यूथ मे भेजने का अधिकार होगा। यदि दक्षिण अफ्रीका के युवक इसे स्वीकार करलें तो यह अवश्य ही एक महान कार्य होगा।
>
> (विज्ञप्ति क्रम ९६। व अ। १२)

जब यह विज्ञप्ति यूरोपियन यूथ कौंसिल के सम्मुख रखी गई तो उन्होंने इस सुझाव को भी ठुकरा दिया और मानव अधिकारो के चार्टर पर हस्ताक्षर करने मे इन्कार कर दिया। परन्तु इस अवहेलना के बावजूद यूरोपियन यूथ कौंसिल को

वर्ल्ड असेम्बली आफ़ यूथ से निष्कासित न किया गया। बल्कि वर्ल्ड असेम्बली आफ़ यूथ ने आगे चल कर कहा :

"हम केवल इतना कर सकते हैं कि सावधान रहें ताकि हमारे 'मित्र' जो हमारे लिए कार्य कर रहे हैं हतोत्साहित न हों.........हम भविष्य से समझौता करने के प्रयास मे इन 'मित्रों' से सम्बन्ध विच्छेद न करें अपितु इस बात की निरन्तर कोशिश करते रहें कि भविष्य में कोई और महत्वपूर्णकार्य किया जा सके।"

'अपने मित्रों को हतोत्साहित न करें' परन्तु किस लिए ? यह प्रश्न पूछना सर्वदा अनुचित समझा जाएगा क्यों कि इसका सीधा अर्थ यह होगा कि भविष्य के साथ समझौता करने का प्रयत्न किया जा रहा है। भले ही वर्ल्ड असेम्बली आफ यूथ वर्तमान से समझौता करले और भविष्य को हमेशा के लिए गिरवी रख ले।

परन्तु वर्ल्ड असेम्बली आफ़ यूथ का कोई भी तर्क गैरयूरोपियन यूथ कौंसिल को बाध्य न कर सका कि वह सही मार्ग अपनाए और रंग-भेद नीति को तिलांजली दे दे। जहाँ तक वर्ल्ड असेम्बली आफ़ यूथ का सम्बन्ध है इसकी इतनी भी हिम्मत न हुई कि रंग-भेद की नीति का समर्थन करने वाली गैर-यूरोपियन यूथ कौंसिल को सदस्यता से निष्कासित कर दे।

वर्ल्ड असेम्बली आफ यूथ न तो साम्राज्यवाद का विरोध करती है और न ही उपनिवेशवाद का। यही कारण है कि इस संस्था ने कभी भी युवकों को साम्राज्यवाद का विरोध करने के लिए आह्वान नही दिया। हंगरी और चेकोस्लावेकिया के प्रश्न पर वर्ल्ड असेम्बली आफ़ यूथ टीका टिप्पणी कर सकती है लेकिन जब साम्राज्यवादियों ने १९५६ में स्वेज नहर के प्रश्न की आड़ में मिस्र पर आक्रमण किया तो वर्ल्ड असेम्बली आफ़ यूथ इस कुकर्म को मा का दूध समझ कर पी गई। एक शब्द भी उन्हो ने साम्राज्यवादियों के विरोध मे न कहा। जब गोवा, दमन और देव पर पुर्तगाली तानाशाही बर्बरता पूर्ण अत्याचार कर रही थी तो वर्ल्ड असेम्बली आफ यूथ के कान बहरे हो गये थे, अरब देशों पर इस्रायली आक्रमण के दौरान इसने अपनी आख पर पट्टी बाध ली और वियतनाम पर अमरीकी आक्रमण के समय तटस्थ हो गई। यह है वर्ल्ड असेम्बली आफ यूथ का असली रूप। आज तक वर्ल्ड असेम्बली आफ यूथ की किसी भी बैठक मे आक्रांताओं

के विरुद्ध आवाज नहीं उठाई गई। इससे बढ़कर साम्राज्यवाद की और अधिक सहायता क्या हो सकती है कि जब लेबनान और जार्डन में अमरीकी नौ सैनिक और ब्रिटिश फौजें उतारी गईं तो वर्ल्ड असेम्बली आफ़ यूथ का कोई भी पदाधिकारी इस नृशंस और बर्बरता पूर्ण कदम के आगे अंगुली भी न उठा सका।

यह केवल किस्सा या कहानी होती, तो आंखें मूंदी जा सकती थीं लेकिन यह तो एक हकीकत है जिसका परिचय वर्ल्ड असेम्बली आफ़ यूथ के सब प्रचार सम्बन्धी प्रसारिकाओं में मिलेगा।

इस आशय से कि विश्व में स्वतन्त्रता प्रिय लोगों को बल न मिले वर्ल्ड असेम्बली आफ यूथ एक अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्था—वर्ल्ड फेडरेशन आफ़ डेमोक्रेटिक यूथ—का डट कर विरोध करती है।

जून १९५१ में बर्लिन शहर में युवकों का एक वृहत् विश्व मेला हुआ जिसके बारे में वर्ल्ड फेडरेशन आफ डेमोक्रेटिक यूथ ने प्रचार हेतु एक बुलेटिन निकाला। जिसका विरोध करते हुए वर्ल्ड असेम्बली आफ़ यूथ ने शिकायत की कि इण्टरनेशनल यूनियन आफ़ स्टुडेन्ट्स के प्रधान ने युवकों को क्यों आह्वान किया है कि 'विश्व शान्ति की स्थापना के लिए शस्त्रीकरण का विरोध करें' और 'जर्मनी के एकीकरण के लिए इसलिए प्रयास करें ताकि जर्मन समस्या का समुचित हल ढूंढा जा सके'। वर्ल्ड असेम्बली आफ यूथ ने यह भी कहा कि 'वर्ल्ड फेडरेशन आफ डेमोक्रेटिक यूथ ने पश्चिमी अर्थ व्यवस्था को अस्त व्यस्त करने के लिए युवकों को हड़ताल करने का आह्वान क्यों दिया है' और 'वर्ल्ड फेडरेशन आफ डेमोक्रेटिक यूथ निशस्त्रीकरण का समर्थन क्यों करती है'। उन्होंने इस बात का भी गिला किया कि इण्टर नेशनल यूनियन आफ़ स्टुडेन्ट्स के अध्यक्ष ने अमरीका की युद्ध सम्बन्धी नीति का विरोध किया है और क्यों इस बात की माग की है कि जर्मनी और जापान का निशस्त्रीकरण कर दिया जाए और जर्मनी और जापान के विद्यालयों एवं विश्व-विद्यालयों में विद्यार्थियों को सैनिक शिक्षण न दिया जाए।

वर्ल्ड असेम्बली आफ यूथ ने इस बात की भी शिकायत की कि वर्ल्ड फेडरेशन आफ डेमोक्रेटिक यूथ के उद्देश्यों में क्यों इस बात पर बल दिया गया है कि 'विश्व-शान्ति के लिए आन्दोलन में तेजी लाई जाए', 'कोरियाई लोगों की आजादी की लड़ाई का समर्थन किया जाए' और 'वियतनाम के बहादुर लोगों की जो अमरीकी साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ रहे हैं सहायता की जाए'।

वर्ल्ड फेडरेशन ग्राफ़ डेमोक्रेटिक यूथ के चार्टर का उल्लेख करते हुए वर्ल्ड असेम्बली ग्राफ यूथ ने अपना रोष प्रकट करते हुए कहा कि यह सर्वथा अनुचित है कि :—

'बड़े-बड़े पूंजीपतियों, जिनका नेतृत्व अमरीकी साम्राज्यवाद करता है, की युद्ध सम्बन्धी नीति का विरोध किया जाए।"

"मार्शल प्लान ग्रौर एटलांटिक पैक्ट की आलोचना की जाए।"

"साम्राज्यवादियों के दमन चक्र का डट कर मुकाबला किया जाए ताकि परतन्त्रता की बेड़ियों में जकड़े हुए राष्ट्र स्वतन्त्र हो सकें।"

"सब देशों के युवकों को आह्वान किया जाए कि वे वियतनाम, कोरिया, अंगोला, मुजांबिक इत्यादि देशों में छिड़े हुए स्वतन्त्रता संग्राम की सहायता करें ताकि विश्व में शान्ति का वातावरण स्थापित हो सके।"

'विश्व के सब युवकों को अन्तर्राष्ट्रीय एकता के लिए मिलकर कार्य करना चाहिए ताकि उनकी शक्ति क्षीण न हो"—यह कुछ ऐसे मौलिक प्रश्न हैं जिनको लेकर वर्ल्ड असेम्बली ग्राफ यूथ सदैव वर्ल्ड फेडरेशन ग्राफ़ डेमोक्रेटिक यूथ का विरोध करती रही है। अतः हम निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि वर्ल्ड असेम्बली ग्राफ़ यूथ विश्व शान्ति की शत्रु है। यह युवकों में अन्तर्राष्ट्रीय मैत्री का विरोध करती है, और यह नहीं चाहती कि उपनिवेशवाद का कड़ा विरोध करने वाले राष्ट्रों की सहायता की जा सके। इसकी दृष्टि में साम्राज्यवाद का विरोध करने का अर्थ है 'पश्चिमी अर्थ व्यवस्था का विरोध'। वर्ल्ड असेम्बली ग्राफ यूथ का कोई भी तर्क किसी भी कसौटी पर खरा नहीं उतर सकता क्योंकि इस संस्था ने सदैव सैनिक गुट बन्दी का समर्थन किया है और साम्राज्यवादियों के तलवे चाटे हैं।

वर्ल्ड असेम्बली ग्राफ़ यूथ का चार्टर देखकर कोई भी यह कहे बिना नहीं रह सकता कि यह चार्टर अमरीका की विदेश नीति की ही प्रतिलिपि है। वर्ल्ड फेडरेशन ग्राफ़ डेमोक्रेटिक यूथ की नीति का विरोध सोवियत संघ की नीति का विरोध नहीं वरन् विश्व के सब राष्ट्रों का विरोध है जो शान्ति प्रिय हैं। भारत भी उसी शान्ति की नीति का प्रबल समर्थक है, अन्य देश भी इसी दिशा में निरन्तर प्रयास करते हैं ताकि युद्ध के बादल सदा के लिए ओझल हो जाएं।

वर्ल्ड असेम्बली आफ़ यूथ यह भी आरोप लगाती है कि वर्ल्ड फेडरेशन आफ़ डेमोक्रेटिक यूथ स्पेन सरकार की तानशाही का विरोध करती है। करे भी क्यों न? स्पेन के तानाशाहों ने जन-मानस की भावनाओं को कुचल कर रख दिया है। वर्ल्ड असेम्बली आफ़ यूथ को तो स्पेन के तानाशाहों का विरोध करने पर आपत्ति है परन्तु हम तो इन तानाशाही देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, पश्चिम जर्मनी, पुर्तगाल, टर्की, पाकिस्तान, दक्षिणी रोडेशिया और दक्षिणी अफ्रीका को भी शामिल करते हैं। ये सब देश हमारी दृष्टि मे विरोध के पात्र हैं क्योंकि इन देशों में स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानियों पर अत्याचार किया जाता है, उन्हें जेल की काल कोठडी में कैद किया जाता है, बिना मुकदमा चलाए देश भक्तों को फांसी दी जाती है। भला, हम भारतीय भी इस दुराचारी तानाशाही को देख कर चुप कैसे रह सकते हैं।

परन्तु जब हम तानाशाही का विरोध करते है, तो वर्ल्ड असेम्बली आफ यूथ की दृष्टि में हम 'पथ भ्रष्ट' है। प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि वह कैसे भी विचार रखे, परन्तु यदि कोई संस्था इस प्रकार के विचार रखे जिससे विश्व शान्ति और विश्व बन्धुत्व को खतरा हो तो उस सस्था की नीतियो का विरोध करना मानव-धर्म बन जाता है।

१६५२ से लेकर आज तक वर्ल्ड फेडरेशन आफ डेमोक्रेटिक यूथ ने कई बार प्रयास किया है कि वर्ल्ड असेम्बली आफ यूथ सहयोग की भावना अपनाए और विश्व के युवकों में मैत्री के लिए काम करे। परन्तु दो सस्थाओं के बीच हुई लिखा-पढ़ी को देख कर ऐसा लगता है कि जहा वर्ल्ड फेडरेशन आफ डेमोक्रेटिक यूथ 'युवकों में अन्तर्राष्ट्रीय मैत्री पर बल देती रही है' वर्ल्ड असेम्बली आफ यूथ का काम केवल झूठे आरोप लगाने के और कुछ नही रहा है। इसने बार-बार इस बात की माग की है कि वर्ल्ड फेडरेशन आफ डेमोक्रेटिक यूथ अपनी नीति का स्पष्टीकरण करे। दूसरे शब्दों में इसका सीधा अर्थ यह है कि वर्ल्ड असेम्बली आफ यूथ अमरीका की युद्ध सम्बन्धी नीती की समर्थक है। वह वियतनाम में अमरीकी हस्तक्षेप की विरोधी नही और न ही इस्राईल को आक्रांता मानती है। भला, इसका समर्थन कैसे सम्भव हो सकता है। सत्य कटु हो सकता है, परन्तु सत्य तो सत्य है चाहे इसका परिणाम कुछ भी हो।

वर्ल्ड फेडरेशन आफ डेमोक्रेटिक यूथ ने कई बार सुझाव दिया कि दोनों संस्थाओं के बीच प्रतिनिधि मण्डलों का आदान-प्रदान हो चाहे वह सांस्कृतिक क्षेत्र हो

या खेल का मैदान, विचार गोष्ठी हो या बृहत् सम्मेलन। परन्तु वर्ल्ड असेम्बली आफ यूथ ने इस सुझाव को भी ठुकरा दिया। आखिर किस लिए ?

क्या यह सत्य नहीं कि वर्ल्ड असेम्बली आफ यूथ ने गलत रुख अपनाकर यह सिद्ध कर दिया है कि वह लौह पर्दे के पीछे है। नहीं तो क्या आवश्यकता है कि यह संस्था युवकों और उनकी संस्थाओं के साथ भी अलगाव की नीति अपनाए। इसके अतिरिक्त कई ऐसे दृष्टान्त है जिनसे यह विदित होगा कि कुएं के मेंढक की भांति वर्ल्ड असेम्बली आफ यूथ के द्वार केवल उन्ही लोगों के लिए खुले हैं जो साम्राज्यवाद के समर्थक हैं। वर्ल्ड असेम्बली आफ यूथ की सदस्यता के द्वार साम्यवादी देश के युवको के लिए बन्द हैं। कोई भी प्रगति शील युवक संस्था इसमे प्रवेश नही पा सकती। केवल वही लोग इस संस्था के साथ सम्पर्क बढ़ा सकते हैं जो काठ के उल्लू हों। इस संस्था से सम्बन्धित संस्थाएं केवल वही हैं जिनका दृष्टिकोण पश्चिमी ढांचे में ढला हुआ है। कोई भी तटस्थ संस्था इसके निकट नही आ सकती।

यदि हम वर्ल्ड असेम्बली आफ़ यूथ के सम्मेलनों में भाग लेने वाले राष्ट्रों की सूची पर दृष्टि पात करें तो ज्ञात होगा कि ऐसे राष्ट्रो की संख्या अधिक रही है जो सदस्य तक भी नहीं हैं। आन्तरिक रिपोर्ट के अनुसार १९४९-५० में इस संस्था के २९ सदस्य थे, १९५०-५१ में इनकी संख्या ३३ हो गई और १९५२ में यही संख्या घटकर ३२ हो गई। इसी प्रकार क्रमशः प्रेक्षकों की संख्या १५, २० और २१ थी।

विश्व के कई छोटे से छोटे देश भी इसी गिनती में शामिल हैं। इस प्रकार वर्ल्ड असेम्बली आफ यूथ विश्व व्यापी संस्था न बनकर केवल साम्राज्यवादी विचार धारा की पिछलग्गू बन गई है।

वर्ल्ड असेम्बली आफ यूथ के नियम ४ उपनियम 'ब' के अन्तर्गत किसी भी राष्ट्रीय समिति को अपना चन्दा अदा न करने पर सदस्यता से अलग किया जा सकता है। परन्तु वास्तव में यह उपनियम विधान की शोभा बढाने के लिए रखा गया है वास्तविकता कुछ और है। १ अप्रेल १९५१ तक राष्ट्रीय समितियों से वसूल की जाने वाली चन्दे की रकम कुल मिलाकर ५१८,८९१ फ्रांक (बेल्जियम सिक्का) थी जिसमें एक वर्ष बाद १४१ ८८० फ्राक की वृद्धि हुई। अगस्त १९६२ में डाकर (सेनीगाल) के स्थान पर आयोजित वर्ल्ड असेम्बली आफ यूथ की बैठक में एक महत्व पूर्ण निर्णय लिया गया जिसके आधार पर किसी भी राष्ट्रीय समिति को चन्दा न देने के उपलक्ष मे संस्था के किसी भी पद पर खड़ा होने के अधिकार से वंचित किया जा सकता था।

परन्तु स्वयं कोषाध्यक्ष ने यह स्वीकार किया कि १९५२ तक ३२ राष्ट्रीय समितियों अर्थात ६०% ने अपना चन्दा अदा ही नहीं किया। जहाँ तक हमें विदित है चन्दा न देने पर किसी भी राष्ट्रीय समिति को आज तक वर्ल्ड असेम्बली आफ़ यूथ की प्राथमिक व सक्रिय सदस्यता से अलग नहीं किया गया और न ही किसी राष्ट्रीय समिति को चन्दा न देने पर चुनाव में खड़ा होने या वोट डालने के अधिकार से वंचित किया गया। इसलिए यह जानना आवश्यक है कि यदि ६०% राष्ट्रीय समितियां चन्दा अदा नहीं करतीं तो वर्ल्ड असेम्बली आफ़ यूथ को मिलने वाली पर्याप्त धनराशि कहाँ से आती है ?

कोषाध्यक्ष ने अपनी प्रारम्भिक रिपोर्ट में लिखा है कि 'धन तो हमारी संस्था का जीवन और प्राण है'। यदि यह बात सत्य है तो 'जीवन और प्राण' प्रदान करने की जिम्मेदारी किस पर है ?

वर्ल्ड असेम्बली आफ़ यूथ से प्राप्त आंकड़ों से पता लगता है कि १९४९-५० में इस संस्था को प्राप्त होने वाली धनराशि का ८३ प्रतिशत ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम से तथा १९५०-५१ में ८७ प्रतिशत ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम और फ्रास से प्राप्त हुआ। इसमें एक देश ने तो ४६ प्रतिशत धन राशि प्रदान की। यह सिद्धहस्त बात है कि संस्था को मिलने वाली कुल धनराशि का ५६ प्रतिशत ऊपर लिखे हुए देशों से प्राप्त हुआ। इसके विपरीत हर वर्ष संस्था को चन्दा में प्राप्त होने वाली धन राशि की मात्रा कम होती गई है।

मजे की बात तो यह है कि कुल धन राशि का ३५ प्रतिशत तो केवल एक राष्ट्र देता रहा है। भला, वह राष्ट्र कौन हो सकता है जिसकी 'दान वीरता और उदारता पर वर्ल्ड असेम्बली आफ यूथ की नींव खड़ी है।'

१९५१ में इन्हीं देशों (अर्थात अमेरिका, ब्रिटेन, फास और बेल्जियम) ने निर्धारित धन राशि का ८२ प्रतिशत और वास्तविक प्राप्त होने वाली धनराशि का ९१ प्रतिशत अदा किया। १९४९ और १९५१ के बीच 'इन्हीं चार देशो ने निर्धारित धन राशि का ८७ प्रतिशत अदा किया जिसमें अकेले अमेरिका की ओर से ३५ प्रतिशत धन प्राप्त हुआ'। इसके अतिरिक्त उसी वर्ष फ्रास की राष्ट्रीय समिति ने वेय से वसूल करने वाली धनराशि जो इसे सफर-खर्च के लिए मिलनी थी, कुल मिलाकर ११७,१३३ फ्राक तक छोड़ दी।

१९५२ में वेय को ५७६२०९ फ्रांक का घाटा रहा क्योंकि उस वर्ष का व्यय कुल मिलाकर १०,३४,४३५ फ्रांक था। अक्तूबर १९५१ मे २००,००० फ्रांक का घाटा दिखाया गया। (बुलेटिन नं० ९)

१९५२ के बजट में व्यय होने वाली राशि १,६७४,००० फ्रांक थी जबकि आय केवल ७५६,००० फ्रांक थी। (सर्कुलर नं० १७/ब अ/१५)

यदि एक ही वर्ष की आय और व्यय के आकड़े आपस में मेल नही खाते तो चकित होने की कोई बात नही। यह आंकड़े हमने वेय के विभिन्न सर्कुलरों और बुलेटिनों से प्राप्त किए हैं जिनको तैयार करने की जिम्मेदारी कई विशेषज्ञों पर है जिन्हे आकड़े तैयार करने के लिए ही ७००० फ्रांक प्रति व्यक्ति प्रति मास दिऐ जाते हैं ताकि आकड़ों में वास्तविकता की झलक आ सके। इसके अतिरिक्त आकड़े एकत्र करने और उन्हे वास्तविक रूप देने का काम भी तो सरल नही, और हो सकता हैं कि आय-व्यय का ब्यौरा देते समय इन्ही विशेषज्ञों को एक दूसरे के आंकड़े देखने का अवसर न मिला हो! आखिर राष्ट्रीय आय के बारे मे भी तो अर्थ शास्त्रियो की राय एक दूसरे से भिन्न होती ही है।

परन्तु हमें यह देखना है कि घाटा किस प्रकार पूरा किया गया :

फाऊंडेशन फार यूथ एण्ड स्टुडेन्ट अफेयरज ने ९० प्रतिशत धन राशि यात्रा कोष में ग्रांट के रूप में प्रदान की। इस फाऊडेशन की आय के स्रोत के बारे मे कुछ भी कहना असम्भव है।

अज्ञात स्रोतों से प्राप्त दान द्वारा। वर्ल्ड असेम्बली आफ़ यूथ की डाकर में हुई बैठक मे (डाकर प्रस्ताव क्रमाक ३) एक प्रस्ताव द्वारा (वेय प्रसारिका क्रमाक १४) अज्ञात स्रोत से प्राप्त होने वाले दान की स्वीकृति इसलिए दी गई ताकि कार्यालय का काम चलाने में पड़ी हुई बाधाएं दूर हो सकें। परिणाम स्वरूप कुमारी हेलन डेल को वर्ल्ड असेम्बली आफ़ यूथ का सहायक महासचिव नियुक्त किया गया।

इस संस्था को दान देने वाला व्यक्ति किन कारणों से अपना नाम गोपनीय रखना चाहता है? इसलिए कि सम्भवतः कोई ऐसी समिति जो अमरीकी न हो उसे साम्यवाद-विरोधी गतिविधियों के पलक्ष में दण्डित न करे।

गारंटी कोष से प्राप्त धनराशि द्वारा जो अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, ईटली और नीदर लैंण्ड से प्राप्त होती है और जो १९५२ में कुल मिलाकर २३७,९८९ फ्रांक थी।

सरकार द्वारा प्राप्त सहायता, चाहे वह परोक्ष हो या अपरोक्ष। कोषाध्यक्ष की रिपोर्ट ने सारा भेद ही खोल कर रख दिया! रिपोर्ट में लिखा गया है कि "अधिक मात्रा मे धन देने वाले देश चिंतित हैं क्योंकि उन्हें अपने देश में सुरक्षित व्यवस्था दिखाई नहीं देती। धन की बडी मात्रा तो सरकारी कोष से निकाली जाती है इस कारण उन्हे डर है कि कही सरकारी नीति में परिवर्तन आने पर इस धन राशि में कमी न कर दी जाए।"

(सरकूलर क्र० ११७/ब अ/१५)

यहाँ यह लिखना आवश्यक है कि वर्ल्ड असेम्बली आफ़ यूथ की न्यूयार्क स्थित बैठक मे यह निश्चय किया गया था कि सरकार को किसी भी युवक आन्दोलन मे परोक्ष रूप से नियन्त्रण या हस्तक्षेप न करने दिया जाए। और जब युवक संस्थाए स्वावलम्बी न बन सकें तो इन संस्थाओं को चलाने के लिए लोगों से धन इकत्रित किया जाए या उन स्रोत्रों से सहायता ली जाए जिन्हें इन सस्थाओं को सहायता देने की आवश्यकता का पूर्ण आभास हो।

लेकिन वर्ल्ड असेम्बली आफ़ यूथ अपनी मर्यादा को भूलकर कुछ सस्थानों के पास अपने आपको गिरवी रखती रही।

करोड़पति डेविड डेविस की सहायता से।

यूरोपियन यूथ कौंसिल द्वारा प्राप्त धनराशि से।

इस प्रकार यात्रा कोष मे घाटे की राशि पूरी की गई। १९५१-५२ में यात्रा के लिए १,८४४,००० फ्रांक धनराशि मे से ४१५,००० फ्राक धनराशि एशिया मे वर्ल्ड असेम्वली आफ़ यूथ के काम के प्रसार हेतु निर्धारित की गई। इस धनराशि से एशिया में अमरीकी दलालों का जाल बिछाने का काम किया गया।

कोषाध्यक्ष की रिपोर्ट में दर्ज है कि 'कोई भी राष्ट्रीय समिति जिसे अपने सदस्यों का विश्वास प्राप्त हो और जिसे जन-साधारण का सहयोग मिलता हो उसे अपनी संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए धन का कभी भी अभाव नही रह सकता।'

इससे तो यही परिणाम निकाला जा सकता है कि वह राष्ट्रीय समिति जो अपना वार्षिक हिस्सा अदा नही कर सकती वह एक जीती-जागती संस्था नहीं है।

कोषाध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट (सरकूलर क्र० ११७/व ध/ १५) में इस बात पर भी जोर दिया है कि यदि संस्था की प्रचार सामग्री न पढ़ी जाए तो ऐसी सामग्री कितनी भी उपयुक्त क्यों न हो, उपयोगी नहीं समझी जा सकती। यह कहना सत्य है कि न तो वर्ल्ड असेम्बली आफ यूथ की कार्यकारिणी के सदस्य और न ही इसकी राष्ट्रीय समितियों ने कभी कोई चन्दा दिया है। एक बार जब कार्यकारिणी ने यह निश्चय किया कि संस्था की प्रसारिका 'वेय फोरम' केवल उन्हीं लोगों को भेजी जाए जो इसका चन्दा अदा करते हों तो जिन्हें 'वेय फोरम' भेजना बन्द कर दिया गया उन्होंने कभी इस बात की शिकायत न की। इसका सीधा अर्थ यह है कि वर्ल्ड असेम्बली आफ़ यूथ द्वारा प्रकाशित सामग्री में कोई भी सदस्य दिलचस्पी नही रखता। लेकिन मज़े की बात यह है कि एक बार 'वेय फोरम' के बारे में जब बैठक में चर्चा की गई तो लगभग ३/४ सदस्यों ने इस पत्रिका को कभी पढा तक भी न था।

वर्ल्ड असेम्बली आफ़ यूथ प्रजातन्त्र विरोधी तत्वों को प्रोत्साहन देने के लिए पूर्वी यूरोप से जो युवक अपना देश छोड़ कर अन्य भागों में आकर बसते हैं उन लोगो के साथ और उनकी संस्थाओं के साथ विशेष सम्बन्ध स्थापित करती है। क्योंकि ये लोग न घर के होते हैं न घाट के, अतः इन लोगों को आसानी से पिट्ठू बनाकर उन्हे अपनी मातृ भूमि के विरुद्ध षडयन्त्र रचने के लिए उकसाया जा सकता है। यूरोप में इन लोगों की कई संस्थाएं हैं। अमेरिका मे भी इन संस्थाओं के काम को बढ़ावा देने का काम पूरे ज़ोर से जारी है। इन लोगो के जिम्मे यह काम लगाया जाता है कि वे अपनी मातृ भूमि पर तथाकथित 'आतंक का अध्ययन करें, मनन करें और साम्यवाद का विरोध करने के लिए तैयार रहें।' इन सब संस्थाओं की कार्य प्रणाली एक जैसी है और वर्ल्ड असेम्बली आफ़ यूथ का इन संस्थाओं के साथ घनिष्ट सम्बन्ध है।

वर्ल्ड असेम्बली आफ़ यूथ का यह मत है कि पूर्व और पश्चिम के बीच पाए जाने वाले अन्तर को कम नही किया जा सकता। परन्तु आश्चर्य तो यह है कि यह संस्था एक नागरिक में और अपने देश से भागने वाले एक भगोडे मे कोई अन्तर नही देखती। इस संस्था की विकास परिषद का सब से अधिक बजट इन 'भगौड़ी संस्थाओं'-को आर्थिक सहायता देने पर व्यय होता है। १९५१ मे इसी कार्यवाही को

बढ़ावा देने व इसके औचित्य के लिए एक प्रस्ताव भी पास किया गया था जिसमें लिखा था :—

> "..........कि राष्ट्रीय समितिया इस दिशा में निरन्तर प्रयास करें कि उन लोगों को जिन्हें अपनी मातृ भूमि छोड़ कर अन्य देशो मे पनाह लेनी पड़ती है, अपने इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए पूर्ण सुविधा दी जानी चाहिए।"

राजनैतिक दमन का विरोध करने के नाम पर वर्ल्ड असेम्बली आफ यूथ प्रस्ताव तो पास कर सकती है परन्तु उसके पास इस विषय पर कोई उत्तर नही कि क्यों इस संस्था ने मैकारथीजम और रंग भेद का विरोध नही किया ? यह संस्था उपनिवेशवाद की जड़ों को मजबूत बनाने के लिए उन देश भक्तो के प्रति कोई हमदर्दी नहीं रखती जो साम्राज्यवाद के बलबूते पर पलने वाले देशो मे हर प्रकार की कुर्बानी दे रहे हैं। जब पैटरिक लुमुम्बा की निर्मम हत्या की गई तो वर्ल्ड असेम्बली आफ यूथ इस दुर्घटना पर दो आंसू भी न बहा सकी। जब फ्रास मे प्रगतिशील युवको के आन्दोलन को दबाने के लिए दमन चक्र प्रारम्भ हुआ तो यह संस्था सो गई। जब स्पेन मे बहादुर देश भक्तों के विरुद्ध दमन की कार्यवाहियां जारी थी तो वर्ल्ड असेम्बली आफ यूथ के पदाधिकारी कुम्भकर्ण की नींद सोए हुए थे। पुर्तगाल की धरती पर कितने लोग असहाय अवस्था में छटपटा रहे हैं उनको देखने की हिम्मत इस संस्था में नही है क्योंकि यदि यह संस्था दमन का विरोध करेगी तो इसका अपना अस्तित्व खतरे मे पड़ जाएगा, इसको मिलने वाली आर्थिक सहायता बन्द हो जाएगी, वे भवन गिर जाएगा जिसकी नींव पर वर्ल्ड असेम्बली आफ़ यूथ खड़ी है। यही कारण है कि दमन पुर्तगाल में हो या स्पेन मे, या किसी अन्य देश में, वर्ल्ड असेम्बली आफ़ यूथ गूंगे और बहरे की तरह न कान से सुन सकती है और न जबान से बोल सकती है। बोले भी क्यों कर, इसकी दुकान दूसरे के पास गिरवी है।

इस संस्था की इन्ही नीतियो और गतिविधियो के कारण थोड़े ही काल मे कई क्षतियां हुई हैं, उन पर दृष्टिपात करें तो पता लगेगा कि यह संस्था दिन प्रतिदिन अपना अस्तित्व खोती जा रही है।

गैर-यूरोपियन यूथ कौंसिल आफ़ साऊथ अफ्रीका ने दिसम्बर १९५२ में इस संस्था को तिलांजलि दी। आयर लैंड १९५२ में इससे अलग हो गया। इससे पूर्व आर० ड्रेज जो बेल्जियम यूथ कौंसिल के नेता और दक्षिणी रोडेशिया के सहायक

महा मन्त्री थे ने १९५१ मे इस सस्था से त्याग पत्र दे दिया क्योंकि वर्ल्ड असेम्बली आफ यूथ ने इन देशों में काम करने वाली राष्ट्रीय समितियों को बिना कारण ही भंग कर दिया था। आस्ट्रिया ने जून १९५३ में इस संस्था से सम्बन्ध विच्छेद कर लिए और उसी वर्ष उत्तरी रोडेशिया और सूरिनाम भी इस संस्था से अलग हो गए।

एक-एक करके यह कड़ी टूटती गई और इसकी साख कम होती गई क्योंकि लोग इसका असली रूप पहचानने लग गए थे।

वर्ल्ड असेम्बली आफ़ यूथ और इसकी भारतीय शाखा :

१९५५ मे अमरीकी नवयुवक जार्ज कार्टर जो निग्रो थे और वर्ल्ड असेम्बली आफ यूथ की ओर से एशिया के लिए सचिव नियुक्त थे, भारत आए। ठीक उसी समय श्रीमती रूजवेल्ट भी भारत यात्रा पर आई हुई थी। यह महिला भूतपूर्व राष्ट्रपति की धर्मपत्नी थीं। कारणवश इन्होंने अपने प्रति भारतीय सौहार्द को देख कर यही उचित समझा कि अमरीकी युवकों और भारतीय युवकों के बीच ताल-मेल बढाया जाए। इससे सुन्दर अवसर कब मिल सकता था कि जार्ज कार्टर भी भारत में मौजूद थे। दिल्ली के मेडन होटल में बिराजमान यही अमरीकी युवक एक विशिष्ट व्यक्ति बने हुए थे। उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामन्त्री से मिलकर इस बात का आश्वासन लिया कि भारतीय शाखा अमरीकी प्रभुत्व के नीचे काम करने वाली वर्ल्ड असम्बली आफ यूथ के साथ अपना नाता जोड लेगी। यह बात स्वाभाविक थी क्योंकि उस वक्त भी कांग्रेस में ऐसे तत्व मौजूद थे जो अमरीका को अपना 'मसीहा' समझते थे और समाजवाद के कट्टर शत्रु थे। इनके शरीर पर देशी वस्त्र तो जरूर थे परन्तु उनकी आत्मा मर चुकी थी। यह वही लोग थे जो अब कांग्रेस से बाहर निकल चुके हैं और उनकी नीतियों पर प्रत्येक व्यक्ति आक्षेप कर रहा है। श्री जवाहरलाल नेहरू के जीवन काल मे ये लोग भीगी बिल्ली की भांति काम करते थे। अन्दर ही अन्दर यह लोग षडयन्त्र की भूमिका अदा करने के लिए अपने विश्वस्त सहयोगियों द्वारा युवकों में पदार्पण कर चुके थे। बस क्या था जार्ज कार्टर को अपना ध्येय पूरा करने मे किसी कठिनाई का सामना न करना पड़ा। बम्बई के वातानुकूल बंगले मे सेठ रामकृष्ण बजाज बिराजमान हो थे ही उन्ही को इस सस्था की भारतीय शाखा का अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। यह घोषणा क्यो हुई उसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है?

जार्ज कार्टर के भारत आगमन से पहले जो राष्ट्रीय समिति भारत में काम कर रही थी उस समिति के सदस्यों ने अपने राष्ट्रीय गौरव को गिरवी रखने से इंकार कर दिया था। उन्होने अमरीका की इसलिए घोर निन्दा की थी क्योंकि अमरीका पाकिस्तान के साथ सैनिक गुट बन्दी में शामिल हो चुका था। अमरीका ने पाकिस्तान को भारत के विरुद्ध प्रयोग में लाने के लिए हथियार दिए थे। कौन ऐसा भारतीय होगा जो इस कार्यवाही की निन्दा नही करेगा ? जिस व्यक्ति में राष्ट्रीय गौरव जागता है वह अमरीका की हथियार देने वाली नीति का कभी समर्थन नहीं कर सकता। भारतीय राष्ट्रीय समिति ने ऐसा ही किया और खुले ढंग से वर्ल्ड असेम्बली आफ़ यूथ (भारतीय कमेटी) की ओर से डटकर विरोध किया। अमरीका नाराज हो गया। उसे यह कैसे गवारा था कि इस राष्ट्रीय समिति को कायम रहने दिया जाए। परिणाम स्वरूप जार्ज कार्टर अमरीका वापिस जाते समय भारतीय युवकों को एक भेंट दे गए—वह थी नई राष्ट्रीय समिति जिसका कार्यालय 'महात्मा गांधी मार्ग, बम्बई' पर खोल दिया गया।

दो वर्ष पश्चात इसी समिति ने जी० रविन्द्र वर्मा को अपना अध्यक्ष घोषित कर दिया। जी० रविन्द्र वर्मा पुराने राजनैतिक खिलाडी हैं। विद्यार्थी आन्दोलन से सम्बन्धित होने के बावजूद इनकी कार्य शैली भारतीय लोगों की देश भक्ति की भावना को छू भी नही पाई। यह व्यक्ति आजकल सिण्डी केट के साथ हैं और उसकी नीति का समर्थन करते हैं। थोड़े समय पश्चात् रविन्द्र वर्मा वर्ल्ड असेम्बली आफ़ यूथ के अध्यक्ष चुने गए। कितना बड़ा सम्मान मिला, व्यक्ति को नही बल्कि भारत को, परन्तु इस संस्था ने इस सम्मान को एक ओर रख कर केवल उन्ही नीतियों का समर्थन किया जो प्रतिक्रियावादी थी।

आज तक जितने भी भारतीय युवक इस संस्था के अध्यक्ष बने हैं वे सब के सब सिण्डीकेट में चले गए हैं। और यदि कोई एक आध बच गया हो तो ऐसा व्यक्ति निसन्देह निर्भीक होगा! वह स्वयं इस सस्था को छोड़ देगा। जब पहली राष्ट्रीय समिति बिना किसी कारण भंग कर दी गई तो उसका एक कारण यह भी बताया गया था कि पिछली समिति वर्ल्ड असेम्बली आफ यूथ के नाम पर वर्ल्ड असेम्बली आफ़ यूथ और अमेरिका के आपसी सम्बन्धों को खराब करना चाहती थी। उस समय यह बात विचित्र लगती थी परन्तु आज तो अमरीका मे भी वर्ल्ड असेम्बली आफ यूथ का चित्र धूमिल है। जार्ज कार्टर ने भारत आकर राष्ट्रीय समिति के रूप मे परिवर्तन लाने के लिए तीन महीने तक निरन्तर प्रयास किया। और इस प्रयास मे तत्कालीन

युवक कांग्रेस के पदाधिकारियों ने सहयोग दिया। युवक कांग्रेस के तत्कालीन युवक नेता भी सिण्डीकेट में चले गए हैं। दिल्ली में भारतीय युवक कांग्रेस की परामर्शदाता समिति की बैठक ४-५ दिसम्बर १९५४ को हुई जिसमें यह निर्णय किया गया था :

> "अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी वर्ल्ड असेम्बली आफ यूथ की गतिविधियों में रुचि ले और यदि इसे आमन्त्रित किया जाए तो यह भारतीय राष्ट्रीय समिति में शामिल हो जाए, परन्तु इस शर्त पर कि सारी समिति पुनः गठित की जाए।"
> (सरकूलर क्र० १ नं० वाई डी/पी.आर./१२४७५ दिनांक ६-१-१९५५)

थोड़े समय बाद कांग्रेस के कार्यालय से एक सरकूलर क्रम ५ संख्या वाई० डी०/पी० आर०/ ७ मार्च १९५५ को जारी किया गया जिस पर दो व्यक्तियों के हस्ताक्षर थे और दोनों व्यक्ति युवक कांग्रेस और सेवा दल के प्रमुख नेता थे। इस सरकूलर में कांग्रेस कमेटियों को आदेश दिया गया था कि वे वर्ल्ड असेम्बली आफ़ यूथ के काम में रुचि लें। यह स्पष्ट है कि उस समय कांग्रेस जैसी महान संस्था में ऐसे लोग मौजूद थे जो समाजवाद के समर्थक नहीं थे परन्तु ये लोग संस्था पर पूर्ण अधिकार जमाए हुए थे और निरन्तर इस कोशिश में रहते थे कि अवसर मिलने पर प्रगतिशील आन्दोलन का गला घोंट दिया जाए। और ऐसा हुआ भी। इन लोगों ने कांग्रेस में सत्तारूढ होने का पूरा लाभ उठाया और डट कर वर्ल्ड असेम्बली आफ यूथ की सहायता की। यहां तक कि दिल्ली में इसका अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलवाया गया और दिल्ली में इस संस्था ने एक विशालकाय भवन का निर्माण किया जिसको देखकर आश्चर्य होता है कि वह संस्था जिसका अस्तित्व केवल कागजों पर है किस प्रकार १२ लाख रुपये की धन राशि से एक भवन तैयार कर सकती है? यह पैसा कहां से आया और क्यों आया, यह पूछना 'देश द्रोह' होगा क्योंकि इस धन में काला धन भी शामिल है और सरकारी धन भी, इसमें शोषण करने वालों की आत्मा वास करती है, साम्राज्यवाद की इससे बू आती है। इस भवन की कहानी बहुत रुचिकर है क्योंकि इस भवन का निर्माण करने वाले देशी भी थे और विदेशी भी थे— अन्तर्राष्ट्रीय रंगमंच बनाया गया, कूटनीतिज्ञों की बस्ती में। कौन कहता है कि चाणक्य मर गया? उसकी नीति जिन्दा है उसके नाम पर दिल्ली में एक बस्ती कायम है जहां विश्व के कूटनीतिज्ञ रहते हैं और इस बस्ती में विदेशी संस्थान की सहायता से युवक केन्द्र भी कायम है जिसे वर्ल्ड असेम्बली आफ यूथ की मान्यता ही नहीं आशीर्वाद भी प्राप्त है।

ऊपर लिखा जा चुका है कि जब कांग्रेस ने सरकूलर भेज कर अपनी शाखाओं को आदेश दिया कि वे वर्ल्ड असेम्बली आफ यूथ से सम्पर्क बढ़ाएं तो इसकी भूमिका कुछ दिन पहले ही तैयार कर ली गई थी और इस संस्था का प्रचार शुरू कर दिया गया था। उस समय से ही युवक कांग्रेस और सेवा दल का सम्बन्ध इस संस्था से रहा है। यह अलग बात है कि कांग्रेस के अन्दर भी शुरू से लेकर आज तक वर्ल्ड असेम्बली आफ यूथ का विरोध होता रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि प्रगतिशील लोगों की आवाज न सुनी गई और सिण्डीकेट के इशारे पर वही काम होता रहा जिसकी चर्चा करते ही प्रत्येक व्यक्ति यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इतने वर्षों तक निस्तब्धता क्यों छाई रही ?

वर्ल्ड असेम्बली आफ यूथ द्वारा पहली एशियाई विचार गोष्ठी १९५६ में दिल्ली में बुलाई गई। इस विचार गोष्ठी में ३० भारतीय प्रतिनिधि और १५ एशियाई देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए और इन लोगों ने एशिया के विभिन्न राजनैतिक और गैर-राजनैतिक युवक आन्दोलनों का प्रतिनिधित्व किया। 'सागर को गागर में भर दिया,' कितना बड़ा कमाल दिल्ली में हुआ इसकी चर्चा क्यों न की जाए ? १५ प्रतिनिधियों ने ३० भारतीय प्रतिनिधियों के साथ मिल कर एशिया के युवक आन्दोलन का नक्शा बदलने की कसम खाई परन्तु उन्हें सफलता न मिल सकी क्योंकि भारत के ४५ करोड़ लोग सजग और जागरूक थे और वे खूब समझते थे कि एशिया की धरती पर वर्ल्ड असेम्बली आफ यूथ क्यों पदार्पण कर रही है ? यह संस्था किसके हितों की रक्षा करेगी यह बताने की आवश्यकता नहीं थी।

मजे की बात यह है कि जब से भारतीय राष्ट्रीय समिति ने अपना सम्बन्ध वर्ल्ड असेम्बली आफ यूथ से जोड़ा है इसने आज तक कभी अपना चन्दा अदा नहीं किया। यहाँ यह लिख देना भी आवश्यक है कि जो भी संस्था वर्ल्ड असेम्बली आफ यूथ से सम्बन्ध रखती है उसकी गतिविधियों पर शक करना स्वाभाविक है। भारतीय लोगों ने अमरीकी सरकार की उन नीतियों का तीव्र विरोध किया है जिसका

अन्य देशों में

श्री लका मे अमरीकी गुप्तचर संस्था ने थोडा समय हुआ एक सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना की और इस सम्बन्ध में एक नीग्रो रिसर्च स्कालर की सेवाएं प्राप्त की क्योंकि इस केन्द्र का उद्देश्य उन लोगों से सम्पर्क बढ़ाना था जिनका रग गोरा नही था। इस केन्द्र की गतिविधियो के बारे मे सारे श्री लका में भारी प्रतिक्रिया हुई और यह जानने का प्रयास किया गया कि इस केन्द्र की स्थापना के पीछे कौन सा भेद छिपा हुआ है। जन-साधारण को इस बात की पूर्ण जानकारी थी कि अमरीका के दक्षिणी प्रान्तों में रग-भेद नीति के आधार पर काली चमड़ी वाले व्यक्तियों के साथ वर्बरता पूर्ण व्यवहार किया जाता है, परन्तु वह सरकार जो अपने देश मे रंग-भेद नीति को समाप्त नहीं कर सकी किस प्रकार निग्रो को श्री लका भेज कर अपनी रग-भेद नीति पर पर्दा डालना चाहती है ?

लोग यह भी जानने के लिए उत्सुक थे कि आखिर शान्ति के अग्रदूत डाक्टर मार्टिन लूथर किंग की अमरीका मे दिन दहाड़े हत्या क्यों की गई ? वे यह भी जानना चाहते थे कि गोरी चमड़ी वालों के लिए बने हुए विद्यालयों मे काली चमड़ी वाले विद्यार्थी के प्रवेश पाते ही उन पर शिकारी कुत्तों से वार क्यों कराया जाता रहा है ? परन्तु इन प्रश्नों का उत्तर अमरीकी गुप्तचर सस्था के किसी भी अधिकारी से नही पूछा जा सकता क्योंकि ऐसा पूछना तो 'प्रजातन्त्र के प्रतिकूल' होगा। इस तथ्य को प्रकाशित करने का अर्थ समझा जाएगा कि आप साम्राज्यवादी हत्यकाण्डों का भाण्डा फोड़ने के लिए 'साम्यवादी ढग' अपना रहे हैं !

अमरीकी गुप्तचर सस्था, काले रंग के युवको को अपने दाव मे फंसाने के लिए काले रंग की आड भी ले सकती है ताकि खुफ़िया काम करने मे आसानी हो।

अमरीकी सूचना विभाग का एक नौजवान अधिकारी गुप्तचर संस्था में उस समय भर्ती किया गया था जब वह विद्यार्थी था। इसी अधिकारी को कई बार विद्यार्थी नेताओं के साथ सम्पर्क स्थापित करते हुए देखा गया। यहां यह बात उल्लेखनीय है कि अमरीकी सूचना विभाग का यह अधिकारी एक डिप्लोमेट है। इस गुप्तचर विभाग ने विशेष तौर पर दांतों का इलाज करने वाले डाक्टरों को भी भर्ती कर रखा है जिनका काम उपयुक्त व उपयोगी सूचना प्राप्त करना है ताकि अमरीकी गुप्तचर सस्था उसका उपयोग कर सके। कई अध्यापकों और विद्यार्थियों को गुप्तचर विभाग के माध्यम से अमरीका भी भेजा जा चुका है ताकि वे 'युवकों के लिए प्रशिक्षण' कार्यक्रम में निपुणता प्राप्त कर सकें। 'युवकों के लिए प्रशिक्षण' का यह कार्यक्रम केवल ढोंग है और यह वास्तव में एक सरल तरीका है युवकों को फुसलाने का। यह अलग बात है कि श्री लंका की धरती पर विघटनकारियों के पांव जम नहीं सके क्योंकि इस देश की शानदार परम्पराए हमेशा साम्राज्यवाद-विरोधी इतिहास की कड़ियों में निहित हैं।

कुछ मास हुए सियरा ल्योन मे बुलाए गए सम्मेलन को असफल बनाने के लिए अमरीकी गुप्तचर संस्था ने एड़ी चोटी का ज़ोर लगाया। उन्हें डर था कि आज़ादी का समर्थन करने वाले प्रतिनिधि अमरीकन साम्राज्यवाद का विरोध अवश्य करेंगे जिससे अमरीका की साख कम होगी। परिणाम स्वरूप इस सम्मेलन के महा सचिव के जाली हस्ताक्षरों से अमरीकी गुप्तचर संस्था ने सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों को सूचना भेजी कि 'सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है', यहां तक ही नहीं इसी गुप्तचर संस्था ने सम्मेलन के लिए भेजा गया सब सामान जैसा कि कान के साथ लगा कर सुनने वाले यंत्र किसी हवाई कम्पनी के साथ मिल कर रास्ते में ही उतरवा लिए और उसे सियरा ल्योन न जाने दिया। गुप्तचर संस्था की यह कोशिश थी कि किसी प्रकार सम्मेलन असफल हो जाए। गुप्तचर संस्था अपने कार्य की पूर्ति के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती। परिणाम यह निकला कि ज़ाम्बिया और केनिया के प्रतिनिधियों को सम्मेलन मे आने के लिए भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ा।

जुलाई १९६९ में हुए इस सम्मेलन में गुप्तचर विभाग ने बाधा डालने का प्रयास केवल इसलिए किया कि इस सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों में अंगोला, मोज़म्बिक, गिनीबिसाओ मे चल रहे स्वतन्त्रता संग्राम के अग्रणी भाग ले रहे थे।

अन्य देशों में

श्री लंका मे अमरीकी गुप्तचर संस्था ने थोडा समय हुआ एक सास्कृतिक केन्द्र की स्थापना की और इस सम्बन्ध मे एक नीग्रो रिसर्च स्कालर की सेवाएं प्राप्त की क्योंकि इस केन्द्र का उद्देश्य उन लोगों मे सम्पर्क बढ़ाना था जिनका रंग गोरा नहीं था। इस केन्द्र की गतिविधियो के बारे मे सारे श्री लका में भारी प्रतिक्रिया हुई और यह जानने का प्रयास किया गया कि इस केन्द्र की स्थापना के पीछे कौन सा भेद छिपा हुआ है। जन-साधारण को इस बात की पूर्ण जानकारी थी कि अमरीका के दक्षिणी प्रान्तो में रंग-भेद नीति के आधार पर काली चमडी वाले व्यक्तियों के साथ बर्बरता पूर्ण व्यवहार किया जाता है, परन्तु वह सरकार जो अपने देश मे रंग-भेद नीति को समाप्त नहीं कर सकी किस प्रकार निग्रो को श्री लंका भेज कर अपनी रंग-भेद नीति पर पर्दा डालना चाहती है ?

लोग यह भी जानने के लिए उत्सुक थे कि आखिर शान्ति के अग्रदूत डाक्टर मार्टिन लूथर किंग की अमरीका मे दिन दहाडे हत्या क्यों की गई ? वे यह भी जानना चाहते थे कि गोरी चमड़ी वालों के लिए बने हुए विद्यालयों में काली चमड़ी वाले विद्यार्थी के प्रवेश पाते ही उन पर शिकारी कुत्तो से वार क्यों कराया जाता रहा है ? परन्तु इन प्रश्नों का उत्तर अमरीकी गुप्तचर संस्था के किसी भी अधिकारी से नहीं पूछा जा सकता क्योंकि ऐसा पूछना तो 'प्रजातन्त्र के प्रतिकूल' होगा। इस तथ्य को प्रकाशित करने का अर्थ समझा जाएगा कि आप साम्राज्यवादी हृदयकण्डों का भाण्डा फोड़ने के लिए 'साम्यवादी ढग' अपना रहे है।

अमरीकी गुप्तचर सस्था, काले रग के युवकों को अपने दाव मे फंसाने के लिए काले रंग की आड भी ले सकती है ताकि खुफिया काम करने मे आसानी हो।

अमरीकी सूचना विभाग का एक नौजवान अधिकारी गुप्तचर संस्था में उस समय भर्ती किया गया था जब वह विद्यार्थी था। इसी अधिकारी को कई बार विद्यार्थी नेताओं के साथ सम्पर्क स्थापित करते हुए देखा गया। यहां यह बात उल्लेखनीय है कि अमरीकी सूचना विभाग का यह अधिकारी एक डिप्लोमेट है। इस गुप्तचर विभाग ने विशेष तौर पर दांतों का इलाज करने वाले डाक्टरों को भी भर्ती कर रखा है जिनका काम उपयुक्त व उपयोगी सूचना प्राप्त करना है ताकि अमरीकी गुप्तचर संस्था उसका उपयोग कर सके। कई अध्यापकों और विद्यार्थियों को गुप्तचर विभाग के माध्यम से अमरीका भी भेजा जा चुका है ताकि वे 'युवकों के लिए प्रशिक्षण' कार्यक्रम में निपुणता प्राप्त कर सकें। 'युवकों के लिए प्रशिक्षण' का यह कार्यक्रम केवल ढोंग है और यह वास्तव में एक सरल तरीका है युवकों को फुसलाने का। यह अलग बात है कि श्री लंका की धरती पर विघटनकारियों के पांव जम नहीं सकें क्योंकि इस देश की शानदार परम्पराएं हमेशा साम्राज्यवाद-विरोधी इतिहास की कड़ियों में निहित हैं।

कुछ मास हुए सियरा ल्योन में बुलाए गए सम्मेलन को असफल बनाने के लिए अमरीकी गुप्तचर संस्था ने एड़ी चोटी का ज़ोर लगाया। उन्हें डर था कि आज़ादी का समर्थन करने वाले प्रतिनिधि अमरीकन साम्राज्यवाद का विरोध अवश्य करेंगे जिससे अमरीका की साख कम होगी। परिणाम स्वरुप इस सम्मेलन के महा सचिव के जाली हस्ताक्षरों से अमरीकी गुप्तचर संस्था ने सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों को सूचना भेजी कि 'सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है', यहां तक ही नहीं इसी गुप्तचर संस्था ने सम्मेलन के लिए भेजा गया सब सामान जैसा कि कान के साथ लगा कर सुनने वाले यंत्र किसी हवाई कम्पनी के साथ मिल कर रास्ते में ही रुकवा लिए और उसे सियरा ल्योन न जाने दिया। गुप्तचर संस्था की यह कोशिश थी कि किसी प्रकार सम्मेलन असफल हो जाए। गुप्तचर संस्था अपने कार्य की पूर्ति के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती। परिणाम यह निकला कि जाम्बिया और केनिया के प्रतिनिधियों को सम्मेलन में आने के लिए भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ा।

जुलाई १९६६ में हुए इस सम्मेलन में गुप्तचर विभाग ने बाधा डालने का प्रयत्न केवल इसलिए किया कि इस सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों में अंगोला, मोज़म्बिक, गिनीबिसाओ में चल रहे स्वतन्त्रता संग्राम के अग्रणी भाग ले रहे थे।

अन्य देशों में

श्री लंका में अमरीकी गुप्तचर संस्था ने थोडा समय हुआ एक सास्कृतिक केन्द्र की स्थापना की और इस सम्बन्ध मे एक नीग्रो रिसर्च स्कालर की सेवाए प्राप्त की क्योंकि इस केन्द्र का उद्देश्य उन लोगों से सम्पर्क बढाना था जिनका रग गोरा नही था। इस केन्द्र की गतिविधियो के बारे में सारे श्री लका में भारी प्रतिक्रिया हुई और यह जानने का प्रयास किया गया कि इस केन्द्र की स्थापना के पीछे कौन सा भेद छिपा हुआ है। जन-साधारण को इस बात की पूर्ण जानकारी थी कि अमरीका के दक्षिणी प्रान्तों मे रंग-भेद नीति के आधार पर काली चमड़ी वाले व्यक्तियों के साथ बर्बरता पूर्ण व्यवहार किया जाता है, परन्तु वह सरकार जो अपने देश मे रंग-भेद नीति को समाप्त नहीं कर सकी किस प्रकार निग्रो को श्री लंका भेज कर अपनी रंग-भेद नीति पर पर्दा डालना चाहती है ?

लोग यह भी जानने के लिए उत्सुक थे कि आखिर शान्ति के अग्रदूत डाक्टर मार्टिन लूथर किंग की अमरीका में दिन दहाड़े हत्या क्यों की गई ? वे यह भी जानना चाहते थे कि गोरी चमडी वालों के लिए बने हुए विद्यालयों में काली चमड़ी वाले विद्यार्थी के प्रवेश पाते ही उन पर शिकारी कुत्तो से वार क्यों कराया जाता रहा है ? परन्तु इन प्रश्नों का उत्तर अमरीकी गुप्तचर सस्था के किसी भी अधिकारी से नही पूछा जा सकता क्योंकि ऐसा पूछना तो 'प्रजातन्त्र के प्रतिकूल' होगा। इस तथ्य को प्रकाशित करने का अर्थ समझा जाएगा कि आप साम्राज्यवादी हत्यकण्डों का भाण्डा फोडने के लिए 'साम्यवादी ढग' अपना रहे हैं !

अमरीकी गुप्तचर सस्था, काले रंग के युवकों को अपने दाव मे फंसाने के लिए काले रंग की आड़ भी ले सकती है ताकि खुफिया काम करने मे आसानी हो।

अमरीकी सूचना विभाग का एक नौजवान अधिकारी गुप्तचर संस्था में उस समय भर्ती किया गया था जब वह विद्यार्थी था। इसी अधिकारी को कई बार विद्यार्थी नेताओं के साथ सम्पर्क स्थापित करते हुए देखा गया। यहां यह बात उल्लेखनीय है कि अमरीकी सूचना विभाग का यह अधिकारी एक डिप्लोमेट है। इस गुप्तचर विभाग ने विशेष तौर पर दांतों का इलाज करने वाले डाक्टरों को भी भर्ती कर रखा है जिनका काम उपयुक्त व उपयोगी सूचना प्राप्त करना है ताकि अमरीकी गुप्तचर संस्था उसका उपयोग कर सके। कई अध्यापकों और विद्यार्थियों को गुप्तचर विभाग के माध्यम से अमरीका भी भेजा जा चुका है ताकि वे 'युवकों के लिए प्रशिक्षण' कार्यक्रम में निपुणता प्राप्त कर सकें। 'युवकों के लिए प्रशिक्षण' का यह कार्यक्रम केवल ढोंग है और यह वास्तव में एक सरल तरीका है युवकों को फुसलाने का। यह अलग बात है कि श्री लंका की धरती पर विघटनकारियों के पांव जम नहीं सकें क्योंकि इस देश की शानदार परम्पराएं हमेशा साम्राज्यवाद-विरोधी इतिहास की कड़ियों में निहित हैं।

कुछ मास हुए सियरा ल्योन में बुलाए गए सम्मेलन को असफल बनाने के लिए अमरीकी गुप्तचर संस्था ने एड़ी चोटी का ज़ोर लगाया। उन्हें डर था कि आज़ादी का समर्थन करने वाले प्रतिनिधि अमरीकन साम्राज्यवाद का विरोध अवश्य करेंगे जिससे अमरीका की साख कम होगी। परिणाम स्वरुप इस सम्मेलन के महा सचिव के जाली हस्ताक्षरों से अमरीकी गुप्तचर संस्था ने सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों को सूचना भेजी कि 'सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है', यहां तक ही नहीं इसी गुप्तचर संस्था ने सम्मेलन के लिए भेजा गया सब सामान जैसा कि कान के साथ लगा कर सुनने वाले यंत्र किसी हवाई कम्पनी के साथ मिल कर रास्ते में ही उतरवा लिए और उसे सियरा ल्योन न जाने दिया। गुप्तचर संस्था की यह कोशिश थी कि किसी प्रकार सम्मेलन असफल हो जाए। गुप्तचर संस्था अपने कार्य की पूर्ति के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती। परिणाम यह निकला कि ज़ाम्बिया और केनिया के प्रतिनिधियों को सम्मेलन में आने के लिए भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ा।

जुलाई १९६९ में हुए इस सम्मेलन मे गुप्तचर विभाग ने बाधा डालने का प्रयास केवल इसलिए किया कि इस सम्मेलन मे भाग लेने वाले प्रतिनिधियों में अंगोला, मोज़म्बिक, गिनीबिसाओ में चल रहे स्वतन्त्रता संग्राम के अग्रणी भाग ले रहे थे।

यह कैसे सम्भव हो सकता था कि साम्राज्यवादी और उनके पिछलग्गू इस सम्मेलन की सफलता को एक आंख से देख सकते !

लाइबेरिया भौगोलिक दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण देश है परन्तु इस देश पर वास्तविक रूप में फ़ायर स्टोन कम्पनी राज्य कर रही है। डालर शाही ने समूचे देश की आर्थिक व्यवस्था पर रबड़ की पैदावार के माध्यम से अपना प्रभुत्व जमा रखा है। यह आश्चर्य की बात है कि इस देश में न तो अनाज की उपज होने दी जाती है और न ही इस देश में प्याज उगाया जा सकता है। देश के सर्वोच्च व्यक्ति की कोठी भी फ़ायर स्टोन कम्पनी ने बनवाई है ताकि उस देश की आर्थिक व्यवस्था और राजनैतिक सत्ता पर डालर का प्रभुत्व बना रहे। इस देश में हीरे जवाहरात की कमी नहीं है और यही कारण है कि इस देश का शोषण करने के लिए साम्राज्यवादी हर प्रकार के हथकण्डे अपना चुके हैं।

दक्षिणी अफ्रीका की रंग-भेद नीति का लाभ उठा कर अमरीकी गुप्तचर संस्था अनाधिकृत व्यापार चलाने के लिए कई नई-नई फर्मों की नीव डाल चुकी है जिनके नाम और काम मे कोई सामंजस्य नहीं है। इसी देश मे एक व्यक्ति जिसे 'हीरों का बादशाह' कहा जाता है को इस प्रकार के अनाधिकृत कार्य चलाने के लिए निपुण माना गया है। यह व्यक्ति हीरों की तस्करी का काम करता है और इस ढंग से जिन-जिन देशों में इसने तस्करी के अड्डे कायम कर रखे हैं वहा ऐसे तरीके अपनाए जाते हैं जिससे विध्वसक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सके। इस काम में बैंक आफ़ इगलैंड इनकी पूरी-पूरी सहायता भी करता है। कुछ चीनी दलाल भी कई देशों मे इन्हीं कार्यों मे सलग्न हैं। अमरीकी गुप्तचर संस्था साम्यवाद के विरोध के नाम पर वास्तव में सोवियत रूस का विरोध करती है अमरीकी गुप्तचर संस्था के लिए अवांच्छनीय नही है कि वे चीनियों से तालमेल बढ़ाए क्योंकि अमरीकी गुप्तचर सस्था और लाल चीन दोनों ही सोवियत रूस के शत्रु हैं। और इसी कारण दोनों में कोई मतभेद नही है और दोनों एक दूसरे के मित्र हैं।

ईस्राईल एक ऐसा देश है जहा हीरों की कोई भी कान नहीं हैं परन्तु आश्चर्य की बात है कि ईस्राईल सारी दुनिया मे हीरों का सब से बड़ा व्यापारी है जो हीरे को निर्यात करता है। ऐसा क्यों ? इसका कारण यह है कि ईस्राईल मध्य एशिया मे साम्राज्यवादी शक्तियों का दलाल है। अरब देशों पर ईस्राईल आक्रमण से मध्य एशिया की शान्ति खतरे में पड़ चुकी है जिससे विश्व शान्ति को भी खतरा है।

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा ईस्राईली आक्रमण की कई बार आलोचना की जा चुकी है परन्तु इसके बावजूद ईस्राईल शरारत करने पर तुला हुआ है क्योंकि उसे साम्राज्यवादी देशों का सहयोग प्राप्त है। दिन प्रतिदिन आक्रांताओं की स्थिति दृढ बनाने का प्रयास किया जाता है। कुछ समय हुआ ईस्राईली सेना ने बड़ी बर्बरता पूर्ण ढंग से कैरो के एक विद्यालय पर बम बरसाए। अलअक्सा मस्जिद को आग लगाने का काम अकेले रोहण का ही नही बल्कि अमरीकी गुप्तचर संस्था की सोची समझी साजिश का नतीजा था ताकि अरब देश के लोगों को भयभीत किया जा सके। ईस्राईल को साम्राज्यवादी देशों से पर्याप्त सहायता मिलती है। इस बात से इकार नहीं किया जा सकता कि अलअक्सा मस्जिद में आग लगाने के काम के पीछे एक ऐसी भावना निहित थी जिसका उद्देश्य अरब भावना को ठेस पहुँचाना था। रोहण की बात तो अलग रही, ईस्राईल सरकार स्वयं कई मस्जिदों को गिरा चुकी है। कई धार्मिक स्थानों पर अब यहूदियों के लिए नाच गाने के केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं। दूसरे लोगों के धर्म के प्रति इस प्रकार की अवहेलना करके ईस्राईल ने यह सिद्ध कर दिया है कि वह हिटलरी तानाशाही से कम नही हैं। ईस्रायल से अरब वासियों को जबर्दस्ती निष्कासित करने और उनकी जायदाद को हड़पने का निरन्तर प्रयास जारी है। सबसे शर्मनाक बात यह है कि वे लोग जो उस देश के वासी हैं उन्हे अपने ही देश में भिखारी बना दिया गया है और उन्हे खुले आकाश के नीचे सड़कों पर रहने के लिए बाध्य किया जाता है। दरयासीन में कत्लेआम की दुःखद घटना भुलाई नही जा सकती और न ही उन घटनाओं पर पर्दा डाला जा सकता है जो साम्राज्यवादियों और उनके दलालों ने फलस्तीन की पवित्र धरती पर अमानुषिक व्यवहार से घटित की हैं। इन सब कार्यवाहियों के पीछे अमरीकी गुप्तचर संस्था का हाथ है।

ईस्राईल की सरकार लगातार युद्ध का वातावरण बनाए रखने के लिए यदा-कदा ऐसे काम करती रही है जिससे मध्य एशिया की शान्ति खतरे में पड़ी रहे और अनेकों रोहण अरब वासियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए तैयार किए जा सकें। संसार के लोग जानते हैं कि पागलपन का बहाना लेकर न्यायाधीश ने रोहण को अपराधी मानने के बावजूद कानून के अन्तर्गत मिलने वाले भारी दड को एक ओर रख कर न्याय की खिल्ली उड़ाई है। रोहण का यह पागलपन असली नही बल्कि ईस्राईल सरकार की अरब-विरोधी नीति की देन है। साम्राज्यवादी शक्तियां नही चाहतीं कि अरब राष्ट्रीयता पनप सके क्योंकि अरब राष्ट्रीयता साम्प्रदायिक नही बल्कि समाजवाद की प्रतीक है।

अमरीकी गुप्तचर संस्था के कई घिनौने रूप हैं। कभी-कभी तो यह बड़े-बड़े पूँजीपतियों के हितों के रक्षक के रूप में, कभी-कभी तेल के बड़े व्यापारी बन कर यह संस्था अरब राष्ट्रीयता पर कुठाराघात करने के लिए हथियारों की सहायता लेकर हमारे सन्मुख आती है। कभी-कभी तो घिसे-पिटे राजाओं की मदद भी करती है ताकि राजवाड़ा शाही की मुर्दा लाश को पुनः जिन्दा किया जा सके। जहां खनिज पदार्थ किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था को सुनियमित बना सकते हैं वहाँ अरब देशों के आर्थिक स्रोत 'तेल' का शोषण करने के लिए तेल ही उसके शत्रुओं का सबसे बड़ा तीखा हथियार है। जब स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया तो उस समय मिस्र पर तीन देशों ने आक्रमण किया। यह आक्रमण मिस्र के विरोध के लिए नहीं बल्कि अरब राष्ट्रीयता का विरोध करने के लिए किया गया था। इसी कारण ईस्रायल और अमरीका की सरकारों मे ताल-मेल है।

पिछले कुछ महीनों से अमरीकी गुप्तचर संस्था की गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई है। कुछ समय पहले फ्रांस मे इसी गुप्तचर संस्था ने मजदूरों के एक सर्वप्रिय नेता को अगवा कर लिया था। यह नया ढंग अपनाया गया था कार्यकर्ताओं को भयभीत करने का।

घाना मे क्वामेइन्क्रूमा का तख्ता उलटने में भी अमरीकी गुप्तचर संस्था का ही हाथ था। यहां यह बात उल्लेखनीय है कि जब क्वामेइन्क्रूमा ने अपने इलाका मे रबड़ की उपज द्वारा घाना के आर्थिक ढाचे को स्वावलम्बी बनाने का प्रयास शुरू किया उस दिन से ही अमरीका इस ताक मे था कि किस प्रकार स्वतन्त्रता सेनानी इन्क्रूमा को मार्ग से हटाया जा सके। परिणाम स्वरूप फायर स्टोन कम्पनी और अमरीकी गुप्तचर सस्था ने घाना मे षडयन्त्र द्वारा इन्क्रूमा का तख्ता उल्ट दिया।

एशिया हो या अफ्रीका, अमरीकी गुप्तचर विभाग की काली करतूतें देखने को मिलेंगी। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि इन काली करतूतों का पर्दा फाश किया जाए।

अमरीकी गुप्तचर संस्था इस बात का विशेष ध्यान रखती है कि इसका सीधा सम्पर्क युवक नेताओं से बना रहे और विशेषतया उन लोगों से जो भविष्य में सरकारी काम काज में प्रमुख स्थान प्राप्त करने वाले हों। यही एक सरल ढंग है सरकारी मशीनरी को प्रयोग में लाने का। उन युवक नेताओं की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है जिनका सम्बन्ध किसी प्रगतिशील संस्था से रहा हो जिससे उनकी प्रगतिशील भावना को डालर की सहायता से कुण्ठित किया जा सके।

सरकारी कर्मचारियों को विचार गोष्ठियों में भी आमन्त्रित किया जाता है और कभी-कभी तो प्रशिक्षण केन्द्रों में उन्हें बुलाया जाता है। इस प्रकार के निमंत्रण किसी सांस्कृतिक संस्था के नाम पर भेजे जाते है ताकि सरकारी कर्मचारियों को इन कार्यक्रमों में भाग लेने पर कोई आपत्ति न हो।

अफ्रीका में नाईजीरिया की स्वतन्त्रता ने एक नये युग का प्रादुर्भाव किया। सदियों से सोई हुई चेतना शक्ति सजग और जागरूक हो उठी। भला यह कैसे सम्भव था कि साम्राज्यवादी इस नई चेतना से समझौता कर लेते। अंग्रेजी साम्राज्यवाद की सदैव यह नीति रही है कि 'बांटो और राज्य करो' परन्तु इसी नीति में थोड़ा परिवर्तन अवश्य आया और 'बांटो और राज्य करो' के स्थान पर 'बांटो और चले जाओ' की नीति अपनाई गई। भारत के बंटवारे के समय अंग्रेजों ने भी ऐसा ही किया और देश को दो टुकड़ों में बांट दिया। इससे पूर्व अंग्रेज़ी सरकार ने हिंदु और मुसलमानों में मन-मुटाव पैदा करने के लिए कोई कसर न छोड़ी। नाईजीरिया में साम्राज्यवादी शक्तियों ने ऐसा ही किया परन्तु उन्हें मुंह की खानी पड़ी और इनकी सब कोशिशें विफल रही और नाईजीरिया का बंटवारा न हो सका। बाईफरा को नाईजीरिया से अलग करवाने के लिए अलगाव सम्बन्धी शक्तिया साम्राज्यवादियों के इशारे पर काम करती रहीं। यह सिद्धहस्त बात है कि इस अलगाव सम्बन्धी आन्दोलन के पीछे साम्राज्यवादियों और चीनियो का हाथ था जिन्होने धन से तथा अन्य प्रकार से अलगाव पसंदों की पूरी सहायता की। यह अलग बात है कि नाईजीरिया की राष्ट्र-वादी सरकार ने अलगाव पसन्दो की दाल न गलने दी। अफ्रीकी महाद्वीप सी० आई० ए० की गतिविधियों का केन्द्र बन चुका है और कई अफ्रीकी देशो में सी० आई० ए० का घिनौना रूप देखने को मिला है। अफ्रीकी राष्ट्र गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के बाद प्रगति के पथ पर बढ रहे हैं। उनकी इस प्रगति को देख कर साम्राज्यवादी बौखला उठे हैं। वे शासक जिन्हें अफ्रीका के लोगों की बुद्धि और योग्यता पर शक था इन्ही अफ्रीकी लोगों की कार्य कुशलता पर परेशान हैं। साम्राज्यवाद की हार को विजय में परिणत करने के लिए सी० आई० ए०, एम० आर० ए० और पीस कोर इत्यादि संस्थाएं घुस पैठ की नीति को अपना कर अपनी घृणास्पद कार्यवाहियों को जारी रखने का प्रयास कर रही हैं। पश्चिमी देश अब भी अफ्रीका के लोगों को 'जानवर' समझते हैं और उन्हें 'असभ्य' कहते हैं, परन्तु तथा कथित सभ्यता के ठेकेदार भूल जाते हैं कि अफ्रीका प्रगतिशील और जागरुक विचारों की जन्मभूमि है। हमें वे दिन याद हैं जब अफ्रीका में रहने वाले लोगो को भेड़ बकरी की तरह जहाजो में लाद कर दूसरे स्थानों पर 'गुलामों' के रूप में भेजा जाता था। भेड़-बकरियों की

भांति नीग्रो बिकते थे। इस अवस्था पर किसको क्षोभ नहीं होगा ? एक नई चेतना की लहर उठी जिसने अफ्रीका के लोगों की सोई हुई आत्मा को जगा दिया। आज अफ्रीका के लोग अपने देश का निर्माण कर रहे हैं और वे उन संस्थाओं को राष्ट्रीय गौरव और मान-मर्यादा के प्रति चुनौती समझते हैं, जिनका काम तथा कथित 'दान वीर' बनकर अफ्रीका को पुनः गुलामी के फंदे में बांधना है। आज़ादी के पहरेदार को सदैव सजग रहना चाहिये और इसके साथ ही उन संस्थाओं से भी सावधान रहना चाहिए जो आज़ादी की शत्रु हैं।

सी० आई० ए० और कम्बोडिया

सी० आई० ए० इसलिए भी बदनाम है क्योंकि इसका काम राज्य सरकारों का तख्ता उलटना और अपने पिछलग्गुओं का गद्दी पर आसीन करना है। जहां सैनिक शक्ति द्वारा राज्य सरकार का तख्ता उल्टना असम्भव हो वहा सी० आई० ए० पैसे का लालच देकर विधायकों को खरीदने का काम भी करती है। इन विधायकों को अपने दल छोड़ने पर विवश कर दिया जाता है। इस प्रकार सरकारों में परिवर्तन लाया जाता है। जब कोई विधायक बिक जाए तो उससे यह आशा नही की जा सकती कि वह आपके प्रति सहानुभूति प्रकट करेगा।

सी० आई० ए० ने हेती मे सरकार का तख्ता उल्टने का षडयन्त्र १९६४, १९६५, १९६८ और १९६९ में किया। माफिया ने हेती के तानाशाह फ्रांकोयस दुवालियर के विरुद्ध षडयन्त्र को विफल बना दिया। हेती के बारे में लगातार संघर्ष माफिया और सी० आई० ए० के बीच काफ़ी समय तक चलता रहा। १९६८ के आक्रमण के समय २४० से अधिक अमरीका से शिक्षण प्राप्त हेती सैनिक इस षडयन्त्र में शामिल थे। हेती के राष्ट्रपति भवन पर जो बम गिराए गए उस बी-२५ हवाई जहाज का संचालन अमरीकी वायु सेना का जय हम्फ़री कर रहा था जो कि अब लेवोर्न फ्लोरिदा में बतौर लकड़ी के ठेकेदार के काम कर रहा है। क्योंकि सी० आई० ए० धन इत्यादि से षडयन्त्रकारियों की सहायता करती रही है इसलिए राष्ट्रपति दुवालियर को सी० आई० ए० के इशारे पर केच हेती मे छाता से उतरने वाली फौज के विरुद्ध लड़ने के लिए दूसरे देशों से हथियार प्राप्त करने पड़े। १९६५ तक हेती ने अमेरिका से कई जंगी जहाज भी अपनी इच्छा के प्रतिकूल खरीदे। १९६३ में राष्ट्रपति दुवालियर और वाशिंगटन के बीच मन-मुटाव शुरू हुआ और तभी से सी० आई० ए० का प्रकोप हेती पर प्रारम्भ हो गया।

कम्बोडिया मे प्रिन्स सिहानुक का तख्ता उल्टने की क्रिया बहुत दिलचस्प है। सिहानुक अपने देश से बाहर गये हुए थे और इससे पूर्व कि अपनी मातृभूमि लौटने के लिए रवाना होते, सैनिक टुकड़ी के एक जनरल लोन नोल ने सिहानुक सरकार का तख्ता उल्ट दिया। यह षडयन्त्र अकेले लोन नोल के मस्तिष्क की उपज नही था बल्कि इस योजना के पीछे सी० आई० ए० का हाथ था। पश्चिमी गुट वाले लोन नोल को अपना 'पुराना और घनिष्ट मित्र' एव 'सेना में शक्तिशाली' व्यक्ति मानते हैं। परन्तु वास्तविकता यह है कि लोन नोल मे न तो सैनिक सूझ-बूझ है और न ही शासन करने की योग्यता। यहां तक कि जिस सेना के वह प्रमुख थे उसने कभी भी लोन नोल को महत्वपूर्ण व्यक्ति नही समझा। कम्बोडिया से फ्रांस का प्रभुत्व समाप्त होने के बाद अमेरिका ने आर्थिक सहायता के नाम पर दल-बल सहित कम्बोडिया मे प्रवेश किया ताकि कम्बोडिया की धरती को फौजी अड्डे में बदल कर समूचे हिन्द चीन को अपने अधिकार में कर लिया जाए। लोन नोल ही एक ऐसा सैनिक कर्मचारी निकला जो अमेरिका के इशारे पर चल सकता था। जब सिहानुक ने १९६३ में अमरीका से मिलने वाली सैनिक सहायता बन्द कर दी थी तो लोन नोल ने इस का विरोध किया था।

लोन नोल को इस बात का ज्ञान था कि सिहानुक आम जनता मे सर्वप्रिय हैं इसलिए उसने यही उचित समझा कि सिहानुक की अनुपस्थिति मे उनका तख्ता उल्ट दिया जाए। इस समाचार ने विश्व भर मे हलचल मचा दी क्योंकि कम्बोडिया की तटस्थ नीति के सभी प्रशसक थे।

सिहानुक ने अपनी प्रतिक्रिया बताते हुए कहा कि उसका तख्ता उल्टने के लिए सी० आई० ए० ने षडयन्त्र रचा। उन्होने इस बात को बिल्कुल निराधार बताया कि कम्बोडिया मे राजनैतिक स्थिति डांवाडोल थी जैसा कि कम्बोडिया की राष्ट्रीय परिषद ने कहा है। सिहानुक ने यह भी आरोप लगाया कि 'राजनैतिक डांवा डोल स्थिति' तो केवल एक बहाना है जिसके द्वारा सी० आई० ए० का उद्देश्य पूरा हो सकता है। यदि कम्बोडिया की इस घटना के पीछे अमरीकी षडयन्त्रकारियो का हाथ नहीं था तो अमरीका को जल्दी क्या पडी थी कि वह तुरन्त ही कम्बोडिया मे लोन नोल सरकार को मान्यता प्रदान कर दे। ऐसा दिखाई देता है कि एक ओर तो सी० आई० ए० ने अपना विध्वसकारी कार्य पूर्ण किया और उधर वाशिंगटन में तुरन्त इस काम पर सरकारी मुहर लगा दी गई। मशीनगनों की नोको पर और सगीन के साए तले राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई गई और इसी अनाधिकृत बैठक

नें सिहानुक की तमाम ताकत अपने हाथ में ले ली। बस क्या था बाड़ ने खेत को खाने का ठेका अपने जिम्मे ले लिया। पहले तो अमरीका अप्रत्यक्ष रूप से कम्बोडिया में घुस पैठ करता था अब उसे लोन नोल सरकार से घुसपैठ ही नहीं बल्कि सब अधिकारों को हथियाने का लाइसेंस भी मिल गया।

कम्बोडिया में सैनिक विद्रोह इतनी जल्दी क्यों हुआ और किस लिए हुआ इसकी जानकारी आवश्यक है ताकि फिर कभी ऐशिया की धरती पर साम्राज्यवादियों के पांव टिक न सकें। सर्व प्रथम तो यह कि अमरीकी जंगबाज़ अमरीका को वियतनाम और लाओस की जग में होने वाली सैनिक क्षति और राजनैतिक हार की पूर्ति करना चाहते थे क्योंकि उन्हें विदित था कि हिन्द चीन में वियतनाम की बहादुर जनता अपनी आज़ादी के लिए लड़ रही है और लाओस के लड़ाकू लोग जीवन की बाजी लगाकर भी अपने देश को साम्राज्यवादी चगुल से निकालने का प्रण किए हुए हैं। रह गया प्रश्न कम्बोडिया का यदि सिहानुक का प्रभुत्व रहा तो कम्बोडिया में साम्राज्यवादी हत्थकण्डे न चल सकेंगे। इसी कारण अमरीका ने हिन्द चीन में अपनी राजनैतिक हार का बदला लेने के लिए लोन नोल सरकार को गद्दी आसीन किया। यह ठीक है कि कम्बोडिया पर लोन नोल सरकार का कब्ज़ा है लेकिन आम जनता न तो लोन नोल के साथ है और न अमरीकी नीति के साथ। जिस देश की आज़ादी को गिरवी रखा जा रहा हो उस स्वाभिमानी राष्ट्र के लोग कुछ समय के लिए भले ही शांत हो जाएं, लेकिन एक न एक दिन तूफान बन कर अवश्य उठेंगे और वह दिन दूर नहीं जब समूचा हिन्द चीन साम्राज्यवादी हत्थकण्डो से मुक्त हो जाएगा।

अमरीका के राष्ट्रपति निकसन ने अपने एक वक्तव्य में कहा था कि "अमरीका शान्ति पर विजय पाना चाहता है" परन्तु वास्तव में यह विजय शान्ति स्थापित करने के लिए नही बल्कि एशिया के देशों को चारों ओर से घेरने के लिए अमरीका की नई चाल—'सैनिक विजय प्राप्त करना' है ताकि जिन देशों में इतनी शक्ति है कि वे अमरीकी साम्राज्यवाद का विरोध करने की हिम्मत रखते हों, उन्हे क्षीण बनाया जा सके। जनता के आन्दोलनों को दबाने के लिए अमरीकी साम्राज्यवाद कभी पीछे नही रहा। यह न केवल दमन चक्र में सहयोगी रहा है बल्कि दमन के लिए हथियार भी देता रहा है। सी॰आई॰ए॰, राज्य सरकारों का तख्ता उल्टने के बाद अमरीकी दुम छल्लों को धन इत्यादि से सहायता भी करती है। दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों की आज़ादी को छीनने के निरन्तर कई प्रयास किए जा चुके हैं परन्तु

हर बार षडयन्त्रकारियों को मुंह की खानी पड़ी है। भले ही चन्द मुट्ठी भर लोग डालर के मोह-पाश मे राष्ट्रीय चेतना को तिलांजली दे दें परन्तु जन साधारण की रगो में बहने वाला रक्त राष्ट्रीय चेतना के अविरल वेग का परिचायक है। लोग अपना बलिदान देकर भी अपने राष्ट्र की रक्षा कर सकते है इसलिए यदि इस चिंगारी को थोडी देर के लिए दबा दिया जाए तो यह चिंगारी अन्दर ही अन्दर सुलगती रहेगी और समय पाकर अपनी लपेट में उन शक्तियों को लेगी जो राष्ट्र हित के विरुद्ध काम करते हैं।

जान फोस्टर डलेस का सिद्धान्त कि 'एशिया के लोग एशिया वालो से लड़े" एक सोची समझी साज़िश का प्रति रुप था जिसका मूल उद्देश्य यह था कि एशिया के लोगों को उकसा कर, फुसला कर, बहला कर अपने नवोदित राष्ट्रों मे विध्वसकारी गतिविधियों के लिए तैयार किया जा सके। जागरुक एशिया तो चट्टान से भी अधिक शक्तिशाली होगा, एशिया के लोगो मे जागरुकता आने का सीधा अर्थ यह होगा कि नव शक्ति का उदयमान होना और जुल्म व अन्याय से टकरा जाना। भला साम्राज्यवादियों को यह स्थिति रुचिकर कैसे लग सकती है ? यह ठीक है कि शक्तिशाली एशिया ही साम्राज्यवाद को चुनौती दे सकता है और इसे परास्त कर सकता है।

कम्बोडिया बहुत पहले ही साम्राज्यवादी चगुल मे फस गया होता यदि राज कुमार सिहानुक अपनी बुद्धिमत्ता और कार्य कौशल से इसे रोक न सकते। कम्बोडिया की राजनीति का अध्ययन करने वाले लोगों को निश्चित ही यह बात आसानी से समझ में आ गई होगी कि "इधर तख्ता उल्टा और उधर अमरीका ने 'नई' सरकार को मान्यता भी प्रदान करदी"। एक ओर तो राष्ट्रपति निक्सन बार बार आश्वासन दिला रहे हैं कि हिन्द चीन से अमरीकी फौजें हटा ली जाएंगी और दूसरी ओर युद्ध की स्थिति बराबर कायम रखी जा रही है। अमरीकी गृह विभाग पर सी०आई०ए० का इतना जबर्दस्त नियन्त्रण है कि यह जानना सम्भव नही कि भविष्य मे किस देश की आज़ादी पर हमला किया जाएगा और किस सरकार का तख्ता उल्टा जाएगा जो अमरीकी नीति के समर्थक नहीं हैं। सी०आई०ए० की एक निश्चित योजना है कि किस प्रकार दक्षिण-पूर्व एशिया मे गृह युद्ध छेड़ा जा सके। इस गृह युद्ध के लिए सी० आई० ए० हर प्रकार की सहायता देती है और इन योजनाओं को पूरा करने के लिए तन, मन, धन, से सहायता भी प्रदान करती है।

१९६३ मे जान फोस्टर डलेस ने कहा था :—

"वियतनाम की लड़ाई को अलग से नहीं देखा जा सकता, इसका सम्बन्ध हिन्द चीन के भविष्य से जुड़ा हुआ है।"

हिन्द चीन का भविष्य, अमरीकी सैनिक अधिकारियों के अनुसार, तभी सुरक्षित रह सकता है जबकि पूरा हिन्द चीन टुकड़े-टुकड़े कर दिया जाए और प्रजातांत्रीय सरकारों का तख्ता उल्ट कर अपने दुमछल्लों को गद्दी आसीन कर दिया जाए।

१६५३ में राजकुमार सिहानुक ने डलेस को समझाने का विफल प्रयास किया था। सिहानुक ने खुले शब्दों में डलेस को बता दिया था कि स्वतन्त्र और तटस्थ कम्बोडिया वियतनाम और लाओस में शांति स्थापना के लिए प्रयाग कर कर सकता है। इस पर डलेस ने कहा था :—

> "जब तक हमारे शत्रु, वियतकाग, परास्त नहीं हो जाते और आपको सम्भवत: इस बात का ज्ञान भी होगा कि किस प्रकार इन्हीं वियतकांग गुरील्लों ने तुम्हारे ख्मेर वश और शानदार परम्पराओं को, तुम्हारी सहस्रों वर्ष पुरानी सभ्यता और तुम्हारी प्रजातान्त्रिक प्रणाली का तहस नहस करके रख दिया है और जब तक यह भयानक खतरा टल नहीं जाता हम फ्रांसिसियों को जिन्होंने हिन्द चीन में हमारी आज़ादी की रक्षा के लिए भारी क्षति उठाई है, हतोत्साहित नहीं कर सकते। हम इस समय युद्ध के भयंकर मोड़ पर खड़े हैं। हमें अवश्य विजय प्राप्त करनी है।"

डलेस सिद्धान्त ही अमरीकी विदेश नीति का मूलाधार रहा है। १६६७ में सी० आई० ए० ने ख्मेर परिवार के कुछ लोगों की सहायता से एक षडयन्त्रकारी योजना बनाई थी कि यह लोग राजसत्ता अपने हाथ में ले लें। इस षडयन्त्र में थाई लैंड के कई मुख्य अधिकारी भी शामिल थे और उन्होंने थाई लैंड की सीमा के पास अपना अड्डा भी जमा रखा था। इस षडयन्त्र का पता एक साल बाद लगा। राज कुमार की सर्वप्रियता से घबरा कर ही लोन नोल सरकार ने सिहानुक के वापिस कम्बोडिया लौटने पर प्रतिबन्ध लगा रखा है।

पाकिस्तान को हथियार देने की नीति

अमरीका की सदैव यह नीति रही है कि पाकिस्तान को सैनिक सहायता मिलती रहे ताकि पाकिस्तान के शासक प्रसन्न होकर अमरीकी उदारवादिता के प्रति आभार प्रकट करते हुए पाकिस्तान में अमरीकी सैनिक अड्डे स्थापित करने की अनुमति दे दें। अमरीका जानता है कि पाकिस्तान को हथियार देकर इसने एक ही तीर से दो शिकार कर लिए—पाकिस्तानी शासक भी खुश हो गए और अमरीकी जंगबाज भी। आखिर हथियार तो बेचने ही थे—बजाए नई दुकान खोलने के पाकिस्तान सरकार ने अपनी दुकानदारी अमरीका के पास पट्टे मे लिख दी। अमरीकी सरकार सैनिक अड्डे बनाना चाहती थी उसे अड्डे मिल गए और पाकिस्तान के सैनिक शासकों को कुछ और वर्षों तक सत्तारुढ रहने का लाइसेंस भी मिल गया।

पाकिस्तान सीटो पैक्ट का सदस्य है और इस नाते अमरीकी गुट मे शामिल भी है और चूंकि अमरीका ने आक्रांताओं की सहायता देने का प्रण ले रखा है इसलिए पाकिस्तानी आक्राताओं को हथियार देना भी इसी का काम है। जब पाक-अमरीकी सैनिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, उस समय भारतीय नेताओ ने चेतावनी दी थी कि पाकिस्तान को हथियार देने का मतलब है एशिया की शान्ति को भग करना क्योंकि पाकिस्ताम इन हथियारो का प्रयोग अवश्य भारत के खिलाफ करेगा परन्तु अमरीकी सरकार ने उस समय आश्वासन दिया था कि पाकिस्तान ये हथियार भारत के खिलाफ इस्तेमाल नही करेगा। लेकिन पाकिस्तान ने इन हथियारो को लेने के बाद जो घिनौनी हरकत की वह इतिहास के पन्नों पर एक कलुषित दाग है। पाकिस्तान ने अपनी सैनिक शक्ति को सुदृढ समझ कर भारत पर

आक्रमण किया। यह बात अलग है कि भारतीय जवानों ने हर मोर्चे पर पाकिस्तानियों के दांत खट्टे किए।

कई वर्षों से अमरीका निरन्तर पाकिस्तान को हथियार देता रहा है, कभी स्वयं और कभी अन्य देश के द्वारा। यह जानते हुए भी कि शीत युद्ध की भूमिका रखने के बाद पाकिस्तान इन हथियारों को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करेगा, चीन के खिलाफ नही क्योंकि चीन और पाकिस्तान भारत विरोधी होने के नाते आपस में मिल चुके हैं, फिर भी अमरीका हथियार देने से बाज नही आता। यदि अमरीका ने अपनी इस नीति मे शीघ्र परिवर्तन न किया तो अमरीका का नाम आते ही जन साधारण यह सोचने पर विवश हो जाएगा कि आज का अमरीका आक्राताओं का सहयोगी है, युद्ध का समर्थक है और आजादी का शत्रु। जब अमरीका ने पाकिस्तान की हथियारों के लिए प्रार्थना पर विचार करना शुरू किया तो भारत सरकार ने अमरीकी सरकार को कह दिया था कि उनका यह कदम शान्ति के लिए अहितकर होगा, परन्तु हथियारो की सप्लाई जारी रही।

यह अलग बात है कि अमरीका के हथियार, गोला बारुद और पैटन टैंकों ने जब भारतीय सीमाओं की ओर रुख किया तो अमरीकी पैटन टैंको के सीने भारतीय गोलियों से छलनी कर दिए गए। पाकिस्तान का रवैया अपने पड़ोसियो के प्रति हमेशा भिन्न रहा है और सदैव भारत विरोधी। सीटो, सैंटो की सहायता से पाकिस्तान अपने लोगों की हथियारो से 'सेवा' करता रहा हैं। पाकिस्तान के लोगों को इन्ही हथियारो के बलबूते पर 'मौलिक प्रजातन्त्र' और 'सैनिक तानाशाही' के बीच गेंद की भांति उछाला जाता रहा है। जन आन्दोलनों को बुरी तरह से दबाया जाता है और राजनैतिक दलों पर प्रतिबन्ध लगता है। पाकिस्तान में न तो प्रजातन्त्र का बीज अंकुरित होने दिया जाता है और न ही प्रजातन्त्र मे विश्वास रखने वाली संस्थाओं को काम करने का मौका दिया जाता है।

प्रजातन्त्र के स्थान पर धर्मान्धता का बोल बाला है। भारत की धर्मनिर्पेक्षता पर बराबर कटाक्ष किए जाते हैं। धर्म के नाम पर पाकिस्तान के शासको ने पाकिस्तान की जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश तो की ही है चीन जैसे धर्म-विरोधी देश को भी उल्लू बनाया है। कारण यह है कि दोनों देश—चीन और पाकिस्तान—भारत को एक आख से नही देख सकते। भारत का विकास उनकी नजरों में अखरता है। स्वतन्त्र भारत की प्रगति उनके लिए शूल है। भारत की

उन्नति को देखकर पाकिस्तान के हृदय में दाह पड़ जाता है। परन्तु सन्तोष जनक बात यह है कि जहां पाकिस्तान सरकार का रुख भारत-विरोधी और जनता विरोधी है वहां पाकिस्तानी जनता सजग और जागरूक हो रही है और इन्हें इस बात का पूर्ण ज्ञान है कि रोटी की लड़ाई को धार्मिक नारों से छिपाया नहीं जा सकता। पाकिस्तान के समाचार पत्रों में इस बात की बराबर चर्चा होती है कि किस प्रकार सी० आई० ए०, शासन में घुस पैठ कर रहा है।

पाकिस्तान जमाते इस्लामी के महा सचिव अब्दुल खालिक ने यह आरोप लगाया है कि सी०आई०ए० पाकिस्तान को अमरीकी सैनिक अड्डे में परिणत करना चाहता है। उन्होंने पाकिस्तान की जनता को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सी० आई० ए० की गतिविधियों पर रोक न लगाई गई तो किसी न किसी दिन पाकिस्तान 'वियतनाम' बन सकता है। उन्होंने अमरीकी दूतावास के एक अधिकारी पर एतराज वाली कार्यवाहिया करने का आरोप भी लगाया। परन्तु इन गतिविधियों पर रोक तो तब लग सकती है जब सरकार ऐसा करने को तैयार हो। जब सरकार ने स्वयं सी० आई० ए० को अतिथि के रूप में घर बुलाया हो तो कौन कहे मेहमान से कि :
"बाज आए ऐसी मुहब्बत से, उठा लो पान-दान अपना"

यद्यपि पाकिस्तानी नेताओं मे जागृति देर से आई है परन्तु इस बात से इन्कार नही किया जा सकता कि पाकिस्तान में सी० आई० ए० का जाल तेजी से फैलता जा रहा है और इसका मुख्य कारण यह है कि पाकिस्तान को अमरीका से हथियार इत्यादि मिलते रहे हैं और इसी प्रलोभन में शासक लोग जनता की भावनाओं की अवहेलना करते रहे हैं। कुछ समय पूर्व अमरीका ने पाकिस्तान को टर्की के माध्यम से १०० अमरीकी टैंक देने का निर्णय किया था। भारतीय संसद में इस विषय पर ध्यान आकर्षित प्रस्ताव द्वारा अमरीकी सरकार को चेतावनी देते हुए संसद सदस्यों ने कहा था कि अमरीका की हथियार देने की नीति क्षोभ पूर्ण है। जब तक अमरीका की विदेश नीति दूसरे देश के लिए अहितकर रहेगी, उस देश के लोगों को निश्चय ही इस नीति का विरोध करना पड़ेगा चाहे इस दिशा में उन्हें कितना अधिक प्रयास क्यों न करना पड़े। जन-साधारण द्वारा किया गया इस प्रकार का विरोध ही उस देश को इतिहास के पन्नों में जीवित रख सकता है।

इस दिशा में उस देश के लोगों को उनसे भी चौकस रहना पड़ता है जिनका काम चोरी छिपे उस देश में घुस पैठ करना है। पाकिस्तान में अमरीका की दाति-

शाली लाबी है। और इसमें बड़े-बड़े राजनीतिज्ञ जो दक्षिण पंथी हैं भी शामिल हैं। जुल्फकार अली भुट्टो जो पाकिस्तान के विदेश मन्त्री रह चुके हैं इतने समझदार निकले कि उन्होने चीन का पिछलग्गू बनना भी स्वीकार किया और अमरीका का भी। एक कुशल दलाल की भांति वह विक्रेता से भी दलाली खा गए और ग्राहक से भी। उन्होंने चीन को जो आश्वासन दिया उसके बिल्कुल प्रतिकूल अमेरिका को आश्वासन दिया। १९६७ मे सी०आई०ए० की सहायता से चलने वाले एक संस्थान ने जुल्फकार अली भुट्टो को काफी धन राशि दी ताकि वह विदेश यात्रा कर सकें।

लाल फीता शाही की सहायता तो सी० आई० ए० करता ही है परन्तु कई प्रमुख अधिकारियों को भी वेतन देकर अपने गुट में शामिल कर लेता है और यही अधिकारी समय पड़ने पर अमरीकी नीति के समर्थन के लिए उपयुक्त वातावर्ण तैयार करते हैं। इस प्रकार पाकिस्तान में प्रजातन्त्र की समाप्ती के पश्चात, पाकिस्तान पर लाल फीताशाही का ही राज्य रहा है।

पाकिस्तान में होने वाले आम चुनावों पर अपना प्रभाव डालने के लिए अमरीका ने पी० एल० ४८० के अन्तर्गत पाकिस्तान में जमा हुए ५ करोड़ रुपये की धन राशि निकाल ली थी। पाकिस्तान में पी० एल० ४८० के अन्तर्गत लगभग १०० करोड़ रुपया जमा है। अमरीका ने बहुत बड़ी सख्या में पाकिस्तानी रुपये डालरों के बदले मे खरीद किए हैं। पाकिस्तान के डालर रिजर्व मे पिछले दिनों काफी वृद्धि हुई है यद्यपि पाकिस्तान के निर्यात मे कोई परिवर्तन नही हुआ है और न ही डालर वाले इलाकों में इसका निर्यात बढा है और न ही आयात में वृद्धि हुई है। पाकिस्तानी नोटों का इतनी बड़ी सख्या मे खरीदा जाना मामूली बात नही है बल्कि उस योजना का विस्तार है जिसके द्वारा आने वाले दिनो मे पाकिस्तान के चुनाव पर असर डाला जा सकेगा।

पश्चिमी जर्मनी और जापान में भी ऐसी ही स्थिति है। इन दोनों देशो में अमरीको प्रभाव बहुत हद तक पाया जाता है। वहां लोगों को इस बात की शंका है कि यह सब मिली भगत दोनों सरकारों की मर्जी से ही हुई है। अन्यथा ये देश कैसे अमरीका को अपने देश की धरती पर अड्डे बनाने की अनुमति दे सकते थे। जब तक पश्चिम जर्मनी इस प्रभाव से मुक्त रहीं हो जाता यूरोप में शान्ति स्थापित करना असम्भव है। कुछ समय हुआ भारतीय दूतावास को हिदायत दी गई थी कि वह पाकिस्तान को टैंक बेचने के प्रश्न पर अमरीका से ऊचे स्तर पर वार्तालाप करे।

ऊंचे स्तर का अर्थ है—निर्णय लेने वाला स्तर। सब से ऊंचा स्तर निश्चय ही राष्ट्रपति का हो सकता है। डिप्लोमेटिक स्तर पर इसका अर्थ है—सेक्रेट्री आफ़ स्टेट। परन्तु वास्तव मे न तो राष्ट्रपति को अधिकार है निर्णय लेने का और न ही सेक्रेट्री आफ़ स्टेट को, असल शक्ति तो सी० आई० ए० और पेंटागन के हाथ मे है जहां अन्य किसी व्यक्ति को कोई नही पूछता।

अमेरिका चिल्ला-चिल्ला कर एलान कर चुका है कि वह न तो पाकिस्तान को हथियार देगा न भारत को, परन्तु इसके बावजूद पाकिस्तान को काफ़ी मात्रा मे पुर्जे सप्लाई किए जा चुके है और पाकिस्तान की सैनिक शक्ति में जो क्षति हुई थी उसको पूरा किया गया है। १९६७ से पहले पाकिस्तान के पास हथियार बन्द गाड़िया भारत से अधिक थी और यदि अमरीका द्वारा पाकिस्तान को मिलने वाले पुर्जो को पाकिस्तानी कारीगर प्रयोग मे ला सकें तो इसका सीधा अर्थ यह होगा कि अमरीका द्वारा हथियार न देने का एलान केवल धोका है और इसकी तह मे वास्तविकता कुछ और है।

पाकिस्तान को किसी भी देश से सैनिक आक्रमण का कोई खतरा नही है क्योंकि पाकिस्तान के पड़ोसी देशो मे भारत की नीति तो शान्तिप्रिय है, चीन के साथ पाकिस्तान की गहरी मित्रता है। तो फिर पाकिस्तान को हथियार देने का अभिप्राय क्या हो सकता है। पिछले २३ वर्षो मे एक बार भी भारत ने पाकिस्तान पर आक्रमण नही किया। इसके विपरीत पाकिस्तान ने शुरू से ही भारतीय सीमाओ पर छेड़छाड जारी रखी है और काश्मीर की धरती पर अनाधिकृत अधिकार कर रखा है। काश्मीर का लगभग आधा भाग पाकिस्तान ने हथिया रखा है और उसका कुछ भाग तो इसने चीन को भेंट रूप मे दे दिया है। चोर चोरी के माल को गज़ों से माप कर नही लाठियों से माप कर देता है क्योकि उसकी कोई हानि नही होती। ठीक इसी प्रकार पाकिस्तान ने किया।

१९६५ की मुठभेड़ से पूर्व पाकिस्तान को अमरीका से जो टैंक मिले उनकी कीमत किताबो मे कई लाख डालर कम दिखाई गई है। पाकिस्तान का आधा सैनिक बजट अरिका पूरा कमरीका रहा है। पाकिस्तानी सेना के साढ़े चार डिविज़नो को अमरीका से प्रशिक्षण प्राप्त हुआ और इन लोगों के शिक्षण का सारा खर्च अमरीकी सरकार ने दिया। अमरीका की सहायता से पाकिस्तान में हवाई अड्डों का निर्माण हुआ है, हथियारों के लिए स्टोर बनाए गए हैं और सैनिक सामान भी दिया गया है।

सम्भवतः इसलिए कि पाकिस्तान सीटो, सेंटों ग्रौर नाटो जैसे सैनिक गुटों में शामिल है।

अमरीका ने पाकिस्तान को हथियार बन्द गाड़ियां भी दी हैं और अम्फीबीयन गाड़ियां इस्तेमाल करने के लिए भी दी हैं इसके अतिरिक्त सावर, सुपर सावर और हवा से भी तेज चलने वाले हवाई जहाज सप्लाई किए हैं। यह अमरीका की नीति रही है कि एशिया में युद्ध का वातावरण बना रहे ताकि छोटे-छोटे देशों को सैनिक गुटबन्दी में शामिल होने के लिये बाध्य किया जा सके। पाकिस्तान पश्चिमी गुट बन्दी में शामिल है और अमरीका का पिछलग्गु बना हुआ है। इस नीति की आड़ में पाकिस्तान की यह कोशिश रही है कि कैसे भारत को निशाना बनाया जाए। पाकिस्तान उस देश से सहायता लेने को तैयार है जो भारत को नीचा दिखाना चाहता हो। चीन और अमरीका का पाकिस्तान के साथ गठ बन्धन कितना विचित्र लगता है ? अमरीका सम्भवतः यह समझता है कि वह अपनी नीति से भारत को डरा धमका कर अपने वश मे कर सकता है ताकि इतना बड़ा देश साम्राज्यवाद का विरोधी बन कर कही साम्राज्यवाद विरोधी शक्तियों को इकट्ठा न कर ले और जिससे अमरीका की दुकानदारी बन्द न हो जाए।

ऐसी ही दुकानदारी को चमकाने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से अमरीका और उसकी केन्द्रीय गुप्तचर संस्था 'रबात' में मौजूद थी। रबात काण्ड के बारे में विदेशी एजंटों ने डटकर साम्प्रदायिक भावनाओं को उत्तेजित करने का काम किया। भारत में वे राजनैतिक दल, जिन्होने 'रबात कांड' की चर्चा करते हुए भारत सरकार की विदेश नीति की भर्त्सना की, सरकार विरोधी प्रदर्शन करते रहे। इन प्रदर्शनों के पीछे भी विदेशी हाथ था। क्या ही अच्छा होता यदि ये लोग रबात के प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करके यह जानने का प्रयत्न करते कि अरब राष्ट्रीयता और मुस्लिम धर्मान्धता जो पैन-इस्लामिज्म का प्रचार करती है उसमें कितना अन्तर है। एक ओर जहां पैन-इस्लामिज्म अरब लोगों में और मुसलमानों में कोई अन्तर नहीं समझता, अरब राष्ट्रीयता इन दोनों को अलग-अलग समझती है। कभी-कभी राष्ट्रीय भावनाओं का जोर हो जाता है और कभी-कभी धर्मान्धता का, चाहे यह थोड़े समय के लिए रहो। धर्मान्धता की तह में उपनिवेशवादी शक्तियां काम करती हैं क्योंकि धर्म के नाम पर ही ये शक्तियां लोगों में बंटवारा करने का दुःसाहस कर सकती हैं। यही कारण है कि धर्म के नकली ठेकेदार सदा 'धर्म खतरे में है' का नारा देते हैं।

इसलिए इन दो विचार धाराओं के बीच संघर्ष मे राष्ट्रवादी और प्रगतिशील शक्तियों के लिए केवल एक ही रास्ता था कि वे राष्ट्रवादी शक्तियों का साथ दें चाहे उन्हें कितनी भी कठिनाई का सामना क्यों न करना पड़े। श्री जवाहर लाल नेहरू ने, जो राष्ट्रीयता की भावनाओं से ओत-प्रोत होकर लोगों को प्रगति के पथ पर चलने का आह्वान देते रहे, अपने जीवन काल में धर्मान्धता का विरोध किया।

पाकिस्तान की नीव धार्मिक रूढ़िवादिता के आधार पर रखी गई और इसके साथ-साथ पाकिस्तान ने हमेशा भारत-विरोधी रुख भी अपनाया ताकि किसी न किसी बहाने प्रतिक्रियावादी शक्तियां पाकिस्तान की गलत नीतियो पर पर्दा डालती रहे। १९४९ मे पाकिस्तान ने पहली अल-मोतमर कांफ्रेंस बुलाई और इसे भारत के विरुद्ध इस्तेमाल करना चाहा। पाकिस्तान ने रुढिवादी देशों को इस्लाम के नाम पर प्रगतिशील शक्तियों का विरोध करने के लिए उकसाया। परन्तु जब १९५४ में अरब राष्ट्रीयता का प्रादुर्भाव हुआ तो ब्रिटिश साम्राज्यवादी बौखला उठे और बदलती हुई परिस्थितियों से मुंह मोड़कर अरब देशों में हुई अपनी पराजय का बदला लेने का भरसक प्रयत्न करते रहे। पश्चिमी देशों ने धर्म के नाम पर बलवे कराए, और भाई-भाई के दिलों मे घृणा के बीज बो दिए। हमने देखा कि टर्की, ईरान, ईराक, पाकिस्तान और ब्रिटेन ने 'बगदाद संधि' की नीव रखी और इसके माध्यम से भारत और मिस्र का विरोध करना शुरु किया क्योंकि यह दोनों देश ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जड़ें हिला कर स्वतन्त्र हुए थे। इस सधि के आधार पर साम्राज्यवादियों ने धर्म का नाम डटकर इस्तेमाल किया। यह अलग बात है कि 'बगदाद पैक्ट' बगदाद में ही दफना दिया गया और १९६४ में अरब राष्ट्रीयता ने मुसलमानों को पैन-इस्लामिजम से विमुख कर दिया।

१९६७ में जब अरब के लोग पराजित हो गए तो इस्राईल ने यह प्रचार शुरु कर दिया कि अरब वालों की पराजय इस कारण हुई है कि अरब देशों ने 'इस्लाम से विमुख' होकर विदेशी विचार धारा अर्थात समाजवाद को अपनाया है। इस प्रचार का उद्देश्य यह था कि आने वाले दिनों मे इस्लाम के नाम पर शिखिर सम्मेलन की भूमिका तैयार की जा सके।

ईस्लाम धर्म के नाम पर ईस्लामिक शिखिर सम्मेलन की योजना विफल हो जाती यदि रोहन अल-अक्सा मस्जिद को आग न लगाता। मस्जिद के जलाए जाने खिलाफ़ लोगों में रोष आना स्वाभाविक था परन्तु इस रोष को नई दिशा देने के

लिए धर्म के ठेकेदारों ने इस अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहा और इस बात का प्रयास शुरु किया कि धर्म की आड़ में कोई स्थायी संस्था बनादी जाए या फिर किसी प्रकार का गठ-बन्धन किया जाए। रबात सम्मेलन और अल-अक्सा मस्जिद में आग लगाने की घटना के पीछे एक सोचा समझा षडयन्त्र था कि किस प्रकार समाजवाद की ओर बढ़ते हुए अरब लोगों के चरण रुक जाएं और पश्चिम एशिया गोपनीय गतिविधियों का केन्द्र बन जाए।

भारत में इसी धर्मान्धता के शिकार भारतीय जन संघ, प्रतिक्रियावादी स्वतंत्र पार्टी और राजनीति में पिछाड़ खाए हुए सिण्डीकेट ने वही काम शुरु किया जिसकी रुप रेखा रबात सम्मेलन में रखी जाने वाली थी। एक ही थैली के चट्टे-बट्टे इकट्ठे हो गए और एक ही स्वर में राग अलापते हुए विश्व में राष्ट्रवादी शक्तियों को क्षीण बनाने की भावना से मैदान मे उतर आए। इन सब पार्टियों को सहायता मिली साम्राज्यवादी टुकड़ों पर पलने वाले समाचार पत्रों से और झूठा प्रचार करने वाले रेडियो से जिसमें बी० बी० सी० भी शामिल था।

रबात सम्मेलन की ओट मे ये पार्टियां चाहती थी कि भारत सरकार की शान्ति प्रिय और साम्राज्यवाद-विरोधी नीति का विरोध किया जाए। पाकिस्तान के इशारे पर धर्म के ठेकेदार धर्म-निरपेक्ष भारत के खिलाफ़ तो थे ही भारत में भी धर्म के ठेकेदार और उनके पूँजीपति दलाल भारत सरकार के खिलाफ इकठ्ठे हो गए। पूँजीपति इस देश का हो या उस देश का उसकी मनोवृत्ति और काम करने का ढंग एक जैसा है। दोनों शोषक हैं और उनके साये में गरीबी और भूख पलती है, सुख और समृद्धि नही। भारतीय हिन्दुओं में जन संघ ने यह प्रचार शुरु किया कि भारत ने रबात सम्मेलन में शामिल होकर इस देश का अपमान किया है परन्तु वे भूल गए कि किसी सम्मेलन में जाने या न जाने से कोई भी राष्ट्र अपमानित नहीं होता। यदि किसी सम्मेलन में कुछ देशो की चाल चलने न दी जाए तो यह स्वयं एक बहुत बडी सफलता है। यदि रबात मे भारत के प्रतिनिधित्व का प्रश्न न उठता तो पाकिस्तान निश्चय ही इस सम्मेलन को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता। जब दो देशों के बीच विचारों का संघर्ष जारी हो तो संघर्ष से घबराकर भाग जाना कायरता है। इसलिए भारत का रबात में भाग लेना आवश्यक था।

किसी भी देश के शान्त वातावरण को दूषित करने के लिए सी० आई० ए० व उसके पिछलग्गू सदा इस ताक में रहते हैं कि लोगों का ध्यान आर्थिक समस्याओं से हट जाए और वे साम्प्रदायिकता के संकीर्ण दायरे में फंस कर दगे इत्यादि कराते

रहें। विशेषतया उन क्षेत्रों में साम्प्रदायिक दंगे कराए जाते है जो औद्योगिक क्षेत्र हैं ताकि सर्वहारा वर्ग की एकता भंग की जा सके। यह सर्व विदित है कि जब सर्वहारा वर्ग के लोग शक्तिशाली होगे पूंजीवाद अपनी मनमानी न कर सकेगा। यही कारण है कि पूंजीपति व उनके दलाल सर्वहारा वर्ग की शक्ति को क्षीण बनाने के लिए कई ढंग अपनाते हैं जिसका परिणाम यह होता है कि कभी-कभी साम्प्रदायिक व प्रतिक्रियावादी तत्वों की उकसाहट पर इन औद्योगिक क्षेत्रो में दगे व बलवे होते है। जब गांधी जन्म शताब्दी वर्ष में विश्व के सब लोग शाति के अग्रदूत महात्मा गांधी को भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली भेंट कर रहे थे तो गाधी जी के जन्म स्थान गुजरात में खून की होली खेली जा रही थी। नन्हें मुन्ने बच्चे, वयो वृद्ध पुरुष और स्त्रियां और जवान लोग मौत की गोद मे सुला दिए गए। यह गाधी जी की 'दोबारा हत्या' करने का प्रयास था। यह कहना अनुचित न होगा कि साम्प्रदायिक दंगों के पीछे विदेशी पूजी और भारत की साम्प्रदायिक सस्थाएं काम कर रहीं थी। सी० आई० ए० को ऐसे तत्वो की आवश्यकता रहती है जो समय पड़ने पर शांत वातावरण में साम्प्रदायिकता की चिंगारी लगा सकें।

गत वर्ष भारत में साम्प्रदायिक दंगे भयानक रूप अख्तियार कर लेते यदि भारत की जनता सजग और जागरूक न होती। स्थान २ पर राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए 'शांति दल' स्थापित किए गए जिसके परिणाम स्वरूप साम्प्रदायिक तत्वो को मुह की खानी पडी। साम्प्रदायिकता अभिशाप है, वरदान नहीं—यह आवाज हर जगह गूंजने लगी। वातावरण पुनः शात हुआ और लोगों ने ठण्डे दिल से यह सोचना शुरु किया कि आखिर इन दगो से उन्हें क्या मिला ? कौन रात भर पेट पर पत्थर बांध कर सोया रहा, किस के घर अनाज न होने से चूल्हा न जला, किस की रोजी छीन ली गई, किसका सुहाग लुट गया, किस घर मे हाहाकार मच गया, कौन जीवन भर के लिए अपाहिज बना दिया गया ? लोग समझ गये कि भारत की इस धरती पर गिरने वाला खून भारतीय था और इसे व्यर्थ बहाया गया। यही रक्त कही भारत की सीमाओं की रक्षा करते हुए बहता तो हमारी पवित्र पावन धरती लहलहा उठती, करोड़ों लोग उस धरती को चूम लेते, इस पवित्र रक्त के कण कण से उस्मान भी पैदा होते और कर्म सिंह भी। मैं भी अपना नत मस्तक करता, आप भी भाव पूर्ण श्रद्धाञ्जली देते। लेकिन भला यह बताइये कि अहमदाबाद की सड़कों पर साम्प्रदायिक दगो के दौरान गिरने वाले खून का क्या बना ? जिन लोगो का कारोबार कई दिनो तक ठप्प रहा, उन्हें दंगो से क्या मिला और जो बच्चा अनाथ हो गया वह किस की मां को मा कहेगा।

फासिस्ट प्रवृत्तियां

जब साम्प्रदायिकता के दात गढने लगते हैं, फासिस्ट विचार धारा उभरने लगती है। वैसे तो मूल रूप से फासिज्म को एक विचार धारा से संज्ञा दी गई है परन्तु वास्तव मे फासिज्म का अर्थ है मानवीय मूल्यों का घटाकर मनुष्य के नैतिक ढाचे का सर्वनाश करना। जाति व रंग-भेद नीति अपनाने वाले तथा फासिस्ट और तानाशाही शासक 'जीवन के लिए संघर्ष' करने के बहाने राजनैतिक विचार धारा पर आधारित जाति-भेद की नीति को ही बढावा देते हैं। इन लोगों की नजरों मे केवल उन्ही की जाति के लोग सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च हैं, तथा अन्य जातियों के लोग न तो श्रेष्ठ हैं न सर्वोच्च। इसी नीति को क्रियान्वित करके फासिस्ट संस्थाएं राज सत्ता को हथियाने का प्रयास करती हैं। सत्ता प्राप्त करना बुरी बात नहीं लेकिन यदि गल्त तरीको से सत्ता को हथियाया जाता है यह निश्चय ही निन्दनीय है। जहां फासिज्म होगा, वहां इन्सान मानवीय मूल्यो का दावा नही कर सकेगा। तानाशाह की आवाज कानून होगी, उसके एक आंख के इशारे से हजारों व्यक्ति मौत के घाट उतारे जा सकते हैं और लाखों घर बर्बाद किए जा सकते हैं। तानाशाह की शक्ति असीमित होती है और उस पर जनता का कोई अकुश नही होता। तानाशाही में विश्वास रखने वाली किसी भी सस्था ने आज तक खुले रूप से अपना कार्य नहीं किया। गोपनीयता ही उनका मुख्य आधार होता है और 'धर्म व संस्कृति की रक्षा' का नारा ही उनका शक्तिशाली हथियार। वास्तव में न तो इनकी धर्म के प्रति निष्ठा होती है और न ही संस्कृति के प्रति आस्था। केवल धर्म के नाम पर शोषण करना ही इनका परम ध्येय होता है। जहा कहीं भी समाजवाद की रचना का प्रश्न उठेगा, प्रतिक्रियावादी और फासिस्ट संस्थाएं जनता को जन आन्दोलन से अलग

करने का यत्न करेंगी और उन्हें रुढिवादी विचारधारा के जाल में फंसाने के लिए कोई कसर उठा न रखेंगी।

जर्मनी में फासिजम की इसलिए विजय हुई थी क्योंकि उस देश के पूंजी-पतियो को पहले विश्वयुद्ध में काफी हानि उठानी पड़ी थी। फासिस्टों ने उखड़ते हुए पूंजीवाद को पुनः स्थापित करने के लिए फासिस्ट विचारधारा को जन्म दिया फासिस्ट संस्था ने पूंजीवाद की डट कर सहायता की और उनके निजी हितो की रक्षा की थी। कारणवश जर्मनी रुढिवाद की शरण मे चला गया। हिटलर ने सत्ता अपने हाथ मे ली और जर्मनी को फिर दूसरे विश्व महायुद्ध में धकेल दिया। क्रान्ति का विरोध करने वाले लोगों को हिटलर ने आह्वान दिया और देखते ही देखते फासिजम अपने असली रूप में सामने आने लगा। यहूदियों का कत्ले आम किया गया, उन्हे गैस चैम्बरों मे मौत के घाट उतारा गया और बन्दी गृहों मे तिल-तिल कर जान देने पर विवश कर दिया गया। यह थी हिटलर की 'सांस्कृतिक विजय' जिसके लिए हजारों लाखों लोगों को यहूदी होने के अपराध मे मौत का निशाना बनाया गया। हिटलर की यह इच्छा थी कि यहूदी कौम हमेशा के लिए खत्म कर दी जाए। हमने देखा कि किस प्रकार एक के बाद दूसरा देश हिटलर के हाथों पिटता गया। इन देशों पर कोई न कोई बहाना करके चढाई की गई। यह सारी घटना दुःखदायी है और इसके लिए हिटलर और उसके फासिस्ट अनुयायी जिम्मेदार हैं।

पौलैण्ड स्थित आस्विज कैम्प मे और उन देशों में जहां हिटलर ने दूसरे विश्व महायुद्ध मे अधिकार कर लिया था, आदमी, औरतें और बच्चे मौत के घाट उतारे गए। सड़कों पर यहूदियों को कतारों में खड़ा करके जर्मन सिपाहियों द्वारा गोली से उड़ाया गया। यदि हम हिटलर के राज्य हथियाने के इतिहास पर दृष्टिपात करें तो हमें विदित होगा कि किस प्रकार हिटलर ने नवयुवकों के मन मे यहूदियों के प्रति घृणा पैदा की। उसका मन्तव्य था 'छोटी आयु मे ही युवकों के मन पर काबू किया जाए' क्योंकि युवको के अन्दर साहस भी होता है और खतरे से लडने की शक्ति भी। उनकी इस प्रवृत्ति पर काबू पाकर उसे राजनैतिक सत्ता हथियाने के लिए भी प्रयोग मे लाया जा सकता है। हिटलर ने इसी विचार धारा को लेकर नवयुवको की अदम्य शक्ति का सहारा लिया और उसी के आधार पर अपने राज्य की नीव रखी। हिटलर को विश्वास था कि जहा गडबड हो उसका लाभ उठाया जाए और जहा गड़बडी न हो वहां ऐसे साधन अपनाए जाए जिससे गडबडी मच सके। कारणवश लोगो मे अकेलेपन और असहाय होने की भावना भर दी गई। लोगो के विचारो में

उनकी इच्छा के प्रतिकूल विचारों को ठूंसा गया। फासिज्म मूलरूप से 'एकाधिकार' का समर्थक है और निराश लोगों को मानसिक तौर पर गुलाम बनाने का अभ्यस्त भी। फासिज्म लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना जानता है और विशेषतया उस समय जब कि पूंजीवाद पर आधारित एकाधिपत्य देश मे सामाजिक अशान्ति पैदा करने में सफल हो जाता है। जब इसे विश्वास हो जाता है कि अब अधिक देर तक साम्राज्यवाद की मुर्दा लाश को घसीटा नही जा सकता, तो यह लोगों में रुढिवादी विचारों का समर्थक बनकर अपना कार्य जारी रखता है।

ऐसी स्थिति बराबर उन देशों में पाई जाती है जहा पर तानाशाहों का राज्य है। सी० आई० ए० इन तानाशाहो की हर प्रकार से सहायता करता है। विश्व के सभी फासिस्ट इस बात मे विश्वास रखते हैं कि उनकी कौम अन्य कौमों से श्रेष्ठ है और इसी कारण वे दो कौमो के सिद्धान्त को मान कर उन कौमों के बीच लड़ाई झगडा कराते हैं। सी० आई० ए० का भी यही अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्त है कि लोगों में फूट डाली जाए और उन्हे संकीर्णता के दायरे मे बन्द कर दिया जाय। सी० आई० ए० फासिस्ट संस्थाओं से तालमेल बनाए रखती है और तानाशाहों की सहायता भी करती है जैसा कि पश्चिम जर्मनी, पुर्तगाल और ग्रीस में हो रहा है। जनता के नेताओं का विरोध करना ही उनका मुख्य काम है ताकि देश प्रगतिशील नीतियों को अपना न सके। अधिकतर फासिस्ट संस्थाए केवल इसलिए बनी है कि साम्राज्यवाद का विरोध न किया जा सके। अब जब कि एशिया और अफ्रीका में समाजवाद की लहर उठ खड़ी हुई है सी० आई० ए० और उनके दलाल विशेष तौर पर इन प्रगतिशील देशों मे सतर्क हो गए हैं और वे उन प्रतिक्रियावादी शक्तियो की खोज में हैं जो उनकी सहायता कर सकें। प्रतिक्रियावादी किसी भी संस्था में हों और किसी भी रूप मे हों उनकी मनोवृत्ति एक जैसी है। वे सदैव प्रगतिशील नीतियों का विरोध करेंगे जैसा कि भारत में बैंक राष्ट्रीय करण के समय हुआ। उनका वर्ग रूप एक जैसा है और उनके कार्य करने की शैली भी एक जैसी है। वे इस बात की ताक में रहते हैं कि कब ऐसा अवसर आए कि वे उन जैसे विचार रखने वाली शक्तियों के साथ समझौता कर सकें।

उनकी दृष्टि में अमरीका में जन अधिकारों की मांग करने वाले लोग प्रजातंत्र विरोधी हैं और जो लोग वियतनाम मे अमरीकी हस्तक्षेप का समर्थन करते वे 'प्रजातन्त्र के समर्थक'। वे आक्रांताओं की सहायता करना अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझते हैं और लोगों की गुलामी को मजबूत बनाना अपना 'राष्ट्रीय कर्त्तव्य'।

कुर्बान जाएं हम उनकी बुद्धिमत्ता पर ! जनता की भावनाओं की अवहेलना भी करते हैं और जनता की सेवा का दम भी भरते हैं। वे कभी-कभी भावनाओं के वेग में बह भी जाते है परन्तु दरयासिन काण्ड पर दो आंसू भी बहा नहीं सकते। यह तो कौम के गम में डूबे रहते है परन्तु भाड़ में जाए कौम परस्ती—इनको इस बात की परवाह नहीं। हीरोशीमा और नागा साकी में लाखों लोग अकारण ही बम का शिकार बना दिए जाएं तो इनके कान पर जूं भी नही रेंगती क्योंकि ऐसा करने से उनके मालिक नाराज हो जाएगे। भारत मे भी फासिस्ट टोले ने 'भारतीय करण' का नारा देकर यह सिद्ध कर दिया है कि हिटलर के मरने के बाद भी छोटे-छोटे हिटलर मौजूद हैं जो अपने देश की प्रगति मे बाधक हो सकते हैं। उनके नारों के पीछे वास्तविकता कुछ और है। मुंह में राम है तो बगल में छुरी। इन विश्वास घातक लोगों पर कौन अपने देश की बागडोर छोड़ सकता है। कहीं ये सत्ता पर अधिकार कर लें, जो असम्भव है, तो समूचा देश खाई में गिर जाएगा।

सी० आई० ए० के एजेन्ट नागालैंड, सिक्किम और काश्मीर इत्यादि सीमा प्रदेशों में बहुत सक्रिय हैं क्योंकि ये प्रदेश सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इस बात का प्रमाण मौजूद है कि नागालैण्ड में देश द्रोहियो की सहायता के लिए पाकिस्तान ने उन्हें हथियार इत्यादि भी दिए ताकि उस स्थान पर अशान्ति बनी रहे। सी० आई० ए० ने ऐसे जासूस भर्ती कर रखे हैं जो इन प्रदेशों से सम्बन्ध रखते हैं। काश्मीर में तो इन्होंने 'आजाद काश्मीर' योजना की भूमिका अदा करने में महत्वपूर्ण कार्य भी किया।

विश्वविद्यालयों में भी सी० आई० ए० वाले घुस पैठ करते रहते है। जहां कही उन्हें साम्प्रदायिक तत्व मिलजाए तो बस क्या है मानों कुत्ते को हड्डी मिल गई हो। बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय में पुलिस ने छापा मार कर बहुत से हथियार अपने कब्जे में लिए। बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय जांच समिति के अध्यक्ष श्री बी० पी० गजेन्द्र गड़कर ने अपनी रिपोर्ट में राष्ट्रीय स्वयं सेवक सघ की गतिविधियों पर भी प्रकाश डाला है। इस जाच समिति ने विश्वविद्यालय के प्रबन्धक वर्ग पर आरोप लगाया है कि वे भूतपूर्व प्रबन्धको में सन्तुलन बनाने के लिए प्रगतिशील और वाम पंथी अध्यापको के विरुद्ध राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के एक कार्यकर्ता को खड़ा करते रहे। यह कमरा जहां पर सघ का कार्यालय स्थित है, जांच समिति ने उसके सम्बन्ध में लिखा है कि विश्वविद्यालय के प्रांगण में राष्ट्रीय स्वयं सेवक सघ का कार्यालय साम्प्रदायिक गतिविधियों का केन्द्र रहा है और इससे शैक्षणिक वातावरण

दूषित होता रहा है। जांच समिति ने पूरे सोच-विचार के बाद यह सुझाव दिया है कि विश्वविद्यालय के प्रागण मे बने हुए इस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यालय की इमारत को गिरा दिया जाए। जब संघ वालों को इस बात का पता लगा तो उन्होंने 'खून खरावे' की धमकी दी और इमारत गिराए जाने का विरोध भी किया। यही साम्प्रदायिक तत्व इस बात की ताक में थे कि यदि विश्वविद्यालय के अधिकारियो ने संघ के कार्यालय को गिरा दिया तो वे 'विश्वविद्यालय की ईट से ईट बजा देंगे'।

यह प्राय: देखने में भी आया है कि जब कभी किसी विश्वविद्यालय मे कोई घटना हो तो अमरीकी समाचार पत्र व रेडियो उस समाचार को बुरी तरह उछालते हैं और उनकी यह कोशिश होती है कि अमरीकी रेडियो सुनने वालों को विश्वास हो जाए कि 'भारत सरकार लडखड़ा रही है' और "भारत के युवक और विद्यार्थी सरकार का तख्ता उल्टने के लिए उतारू हैं।" इस प्रकार मनोवैज्ञानिक लड़ाई लडी जाती है और सी० आई० ए० को विश्वास होने लगता है कि वह इस लड़ाई मे अकेले नही वल्कि ऐसे गुट और सस्थाएं भी शामिल हैं जिनका उद्देश्य सी० आई० ए० के उद्देश्यों से भिन्न नही है। दो वर्ष पूर्व जब भारत में कुछ स्थानों पर विद्यार्थियों द्वारा प्रदर्शन, हड़तालें इत्यादि हो रहे थे तो सी० आई० ए० के एजेंट इन्ही विश्व विद्यालयों मे सम्पर्क बढ़ाने का काम कर रहे थे। उस समय की स्थिति का इन्होंने पूरा लाभ उठाया। ऐसा लगता है कि सी० आई० ए० दोनों ओर से सुरक्षित है उग्र वाम पंथी भी सी० आई० ए० के साथ हैं और उग्र दक्षिण पंथी भी। भारत के एक विश्वविद्यालय मे जब गर्वीले विद्यार्थियों ने अपनी कक्षा में प्रतिदिन एक अमरीकन को जो कि विद्यार्थी न होकर केवल डिप्लोमेटिक सर्विस करता था, देखा तो उन्होने इस पर भारी रोष प्रकट किया। यद्यपि इस चेतावनी के बाद वह अमरीकन पुन: कक्षा में नही आया परन्तु पता लगा है कि अमरीका के एक संस्थान ने उस कालेज को वातानुकूलित बनाने का वायदा किया है इसलिए वह अमरीकी कूटनीतिज्ञ हर प्रकार का लाभ उठाने लगा था। वह कालेज को अपनी पैत्रिक सम्पत्ति समझने लग गया था और विद्यार्थियों से ताल-मेल बढाना अपना कानूनी अधिकार परन्तु वह भूल गया कि विश्वविद्यालय की दीवारों पर अमरीकी नारे अंकित करना शायद सम्भव हो ये नारे विद्यार्थियों के दिलों पर अंकित नहीं किए जा सकते।

विद्यार्थी तो स्वभाव से ही विद्रोही हैं वह न तो पैसे से समझौता कर सकता है न अपने विचारो से। उसको डालर की झलक खरीद नही सकती, वह स्वाभिमानी

है और उसकी नसों में बहने वाला रक्त भारतीय है। इसलिए कोई भी ऐसा कार्य जो भारतीय जनता के हितों के विरुद्ध है वह उसको सहन नहीं कर सकता। उसे इस बात का दुःख है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी सी० आई० ए० घुस पैठ कर रहा है लेकिन शिक्षा का ठेकेदार सो रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि हमारे शिक्षा क्षेत्र में किसी भी प्रकार का विदेशी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और न ही किसी विश्वविद्यालय को या कालेज को यह अधिकार प्राप्त होना चाहिये कि वे किसी विदेशी संस्थान से सम्पर्क बढ़ाकर विश्वविद्यालय को या कालेज को पट्टे पर लिख दे।

आज़ादी के शत्रु

अमरीका के भूतपूर्व राष्ट्रपति कैनेडी और जानसन के शासन काल में अन्तर-विभागीय समितियों का गठन इस ढंग से किया गया था कि वे सरकार की खुफ़िया एजसियों पर नज़र रख सकें। सरकार को कई समितियों का गठन इसलिए भी करना पड़ा क्योंकि इन सरकारी विभागों के पास वैसा ही काम था जैसा कि सी० आई० ए० के पास। प्रश्न केवल आपसी सम्पर्क का था। १९६१ में क्यूबा में बे आफ़ पिगज़ पर हुई अमरीकन पराजय पर सी० आई० ए० की प्रतिष्ठा को भारी धक्का लगा था। कारण यह कि सी० आई० ए० द्वारा दी गई सूचना गलत निकली। इसलिए बोबी कैनेडी के नेतृत्व में एक समिति का निर्माण किया गया जिसका काम सी० आई० ए० के काम की देखभाल करना था। इसी प्रकार जार्जिया के सेनेटर रिचर्ड रसल की नियुक्ति कांग्रेस की ओर से सी० आई० ए० के काम की देखभाल के लिए हुई। राष्ट्रपति के निजि मित्र क्लार्क क्लिफोर्ड के ज़िम्मे यह काम लगाया गया था कि वह सरकारी तौर पर इन समितियों की जांच करे।

लेकिन, परिणाम क्या निकला ? मैसाचुसेटस इन्स्टीट्यूट आफ़ टेक्नोलोजी इन कैम्बरिज, जहा पहले रोस्टोव काम करता था ने १९६६ में निश्चय किया कि वह अधिक देर तक सी० आई० ए० के अनुसन्धान केन्द्र में कार्य नहीं कर सकता। इसी प्रकार स्टान फोर्ड के विद्यार्थियों ने भी सी० आई० ए० के विश्वविद्यालय स्थित पिट्ठुओं के विरुद्ध प्रदर्शन किए। कोलम्बिया विश्वविद्यालय और ग्रिनेल कालेज आइओवा के विद्यार्थियों ने भी सी० आई० ए० की तीव्र निन्दा करते हुए प्रदर्शन आदि किए। अमरीका के समाचार पत्रों में भी वियतनाम सम्बन्धी अमरीकन नीति की भर्त्सना की गई। लन्दन के समाचार पत्रों और बाल्कन स्थित रेडियो स्टेशनों

ग्रौर मजदूरों की संस्थाओं को आर्थिक सहायता देने के प्रश्न पर भी सी० आई० ए० की कड़ी आलोचना की गई।

आश्चर्य की बात हैं कि सी० आई० ए० का एक रूप नहीं कई रूप हैं। यह एक ओर व्यापारिक सस्थाओं के रूप में सामने आती है तो दूसरी ओर हवाई कम्पनियों के माध्यम से। हर काम में इसकी रुचि है और हर स्थान पर इसके पिट्ठु बैठे हैं। अमरीका के कूटनीति-विभाग और सी० आई० ए० विभाग मे कोई अन्तर नहीं है। एक ही व्यक्ति दोनों विभागों में साथ काम करता है। फ्रास गणराज्य की स्थापना के लिए सी० आई० ए० ने तृतीय शक्ति "थर्ड फोर्स" की सहायता की। १६४८ के ग्राम चुनावो मे ईटली के क्रिश्चन डेमोक्रेटस की सहायता की। ईरान के भूतपूर्व प्रधान मन्त्री डाक्टर मुसद्दिक और गोटे माला के राष्ट्रपति आर बेन्ज के विरुद्ध षडयन्त्र रचा। इण्डोनेशिया के भूतपूर्व राष्ट्रपति सुकर्ण को सत्ता से अलग करने के लिए विद्रोही लोगो की सहायता की। बर्मा मे इसने साम्यवाद-विरोधी चीनी गुरिल्लों को भेजा। १६५० के मध्य मे सी० आई० ए० के दलालों ने कोस्टारीका मे घुसने का प्रयास किया क्योंकि कोस्टारीका लतीनी अमरीका मे सब से स्थायी और प्रजातान्त्रिक देश है। यह सी० आई० ए० के मस्तिष्क की ही उपज थी कि उसने गोटे माला की सरकार से माग की थी कि वह अपने देश मे क्यूबा के शरणार्थियो को सैनिक शिक्षण की सुविधा प्रदान करे ताकि ये शरणार्थी पुनः क्यूबा मे भेजे जा सकें और अपने देश के विरुद्ध काम कर सकें। सी० आई० ए० ने इन शरणार्थियों को सैनिक शिक्षा दी, धन भी दिया और उन्हें अपने खर्चे पर पिगज खाडी में भिजवाया जहां से उन्हे फिडल कैस्ट्रो की राज सत्ता को बदलना था। सी० आई० ए० प्रमुख ने और अमरीकी सेना के प्रमुख अधिकारी ने राष्ट्रपति केनेडी और राष्ट्रपति जान्सन को यह दृढ़ विश्वास दिलाया था कि सशस्त्र शरणार्थियों के जोरदार आक्रमण से घबराकर क्यूबा के क्रान्तिकारी शासक हथियार छोड देंगे। सी० आई० ए० को जब बुरी तरह असफलता का मुंह देखना पडा तो छटी का दूध याद आ गया। छोटे से देश क्यूबा ने अपनी बहादुरी की धाक दुनिया पर बिठा दी।

इन सब घटनाओं को देखकर यही लगता है कि सी० आई० ए० अमरीकी सरकार का ही अग है जिसे कई कामों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यह खुफिया विभाग से बढकर काम करने वाली संस्था है। इसी के माध्यम से अन्य देशो के आन्तरिक मामलो मे हस्तक्षेप किया जाता है। यही जिम्मेवार है 'बिना घोषित किए हुए युद्ध' की प्रस्तावना तैयार करने के लिए। यह आक्रान्ताओं का हथियार है।

यह ऐसा घिनौना अस्त्र है कि इसे अपने पास रखा नहीं जा सकता। यह न केवल राजनैतिक नियमों और सिद्धान्तों का ही विरोध करती है बल्कि यह नवोदित देशों की आजादी का हनन करने के लिए गुप्त रूप से काम भी करती है। सी० आई० ए० का बजट अमरीकी सैनिक विभाग तैयार करता है। जब 'वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सर्विस' ने ११ मार्च १९६७ को राष्ट्रपति जानसन से मांग की कि वह विद्यार्थियों को 'भेद गुप्त रखने' की सौगन्ध से मुक्त करें ताकि वे लोग सी० आई० ए० से अपना नाता तोड सकें, यह मांग कोई कम महत्वपूर्ण नही थी।

अमरीकी गृह विभाग और सी० आई० ए० निष्कासित व्यक्तियों के सगठनो की सहायता भी करते हैं ताकि इन निष्कासित लोगों की सहायता से उनसे उनके ही देश में शान्ति भग की जा सके। यह ढग अपना कर अमरीकन सरकार अन्य देशों मे अपने हितो की रक्षा करना चाहती है। तानाशाही के विरुद्ध संघर्ष करने के अपराध में यदि कोई व्यक्ति अपने देश से निष्कासित किया गया हो तो उसकी सहायता की बात तो समझ में आती है लेकिन वह व्यक्ति जो अपने देश की स्वतन्त्रता के विरुद्ध काम करने के अपराध मे निकाला गया हो उसे अमरीकी अपनी पलकों पर बिठा लें तो उसे कोई भी न्याय सगत नही कहेगा। सी० आई० ए० का काम यह भी है कि उपनिवेशवाद की जड़ें को मजबूत किया जाए और तानाशाहो की सहायता की जाए। अमरीका को शायद विश्वास है कि किसी न किसी दिन इन राज्यो मे उल्ट फेर होगा और निष्कासित लोगों की सहायता से वह इन देशों पर अपना प्रभुत्व जमा सकेगा। इसे इस बात की भी आशा है कि इन देशों में सैनिक अड्डे बनाना सरल होगा। वामपंथी किसी भी दल से सम्बन्ध रखता हो उस की छान बीन का काम भी सी० आई० ए० के जिम्मे है। साम्यवाद का विरोध करने वाले व्यक्तियों को नि.शुल्क सामग्री भेजी जाती है उनमें प्रमुख हैं 'प्राब्लेमज आफ़ कम्यूनिजम' अर्थात 'साम्यवाद की समस्याएं'। यह संस्था उग्रवादी लोगों से भी सम्पर्क रखती है चाहे वे उग्रवादी दाएं बाजू वाले हो या बाए बाजू वाले। यह जानते हुए कि विश्व मे सी० आई० ए० की गतिविधियों का भाण्डा चौराहे मे फूट चुका है, सेनेट की वाचडाग कमेटी के अध्यक्ष सेनेटर बी० रिचर्ड ने सुझाव दिया था कि उन सस्थाओं की आर्थिक सहायता बन्द कर दी जाए जिन पर सी० आई० ए० से धन लेने का आरोप लगा है। सेनेटर फुलब्राईट और अन्य सदस्यों ने भी राष्ट्रपति द्वारा सी० आई० ए० की गतिविधियों पर अंकुश न रखने के प्रति गहरी चिंता प्रकट की थी।

सी० आई० ए० दोधारी तलवार की तरह मार करने की कोशिश करती है। जहां प्रजातन्त्र को उखाड़ फेंकना असम्भव हो और सशस्त्र क्रान्ति आसान हो वहां सी० आई० ए० वाले अपनी पिट्ठु सरकार बनाने का भरसक प्रयत्न करते हैं। अब यह प्रकट हो चुका है कि विद्यार्थियों, वैज्ञानिकों, अनुसंधान केन्द्रों तथा सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं में सी० आई० ए० घुस पैंठ करती है, धन से भी और मन से भी ताकि विश्व में अमरीकी नीतियों का विरोध कम किया जा सके। सी० आई० ए० ने क्यूबा के क्रान्ति-विरोधी तत्वों जो फलोरीडा में इकत्र हुए थे, की सहायता की ताकि वे अमरीकी वायु सेना में बतौर पायलेट भर्ती होकर कांगो मे राष्ट्रवादियों को पराजित करने के लिए भेजे जा सकें। इस से अधिक रोमाचकारी घटनाएं भी हैं जैसा कि सी०आई०ए० की सहायता से गायना के भूतपूर्व प्रधानमंत्री डाक्टर छेदी जगन का तख्ता उल्टना। सी० आई० ए० ने १९६२-६३ मे साम्प्रदायिकता को बढ़ावा दे कर भारतीयों और नीग्रो के बीच दंगे फसाद कराये थे। जब छेदी जगन का दल जनता के हितों की बात कर रहा था केनेडी सरकार को इस बात का डर था कि कहीं मार्कसवादी छेदी जगन गायना को 'क्यूबा' न बना दे। इसलिए अमरीका ने यही उचित समझा कि प्रगतिशील विचारों का गला घोंट दिया जाए।

सी० आई० ए० विदेशों में अपनी कार्यवाहियों के लिए सरकारी सहायता भी प्राप्त करती है। व्हाईट हाउस के एक प्रतिनिधि का कहना है :—

> "कि राष्ट्रपति जानसन को अमरीका के अण्डर सेक्रेटरी आफ स्टेट, निकोलास कायजन बाच से रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि सी० आई० ए० ने लाखों डालर विभिन्न संस्थाओं को दिए है और यह सब कुछ अमरीका की सब से बड़ी राजनैतिक योजना समिति की नेशनल सक्यूरिटी कौंसिल के आदेशानुसार किया गया है।"

अंगोला, मुजाम्बिक, गिनी बिसाऊ और दक्षिणी रोडेशिया के स्वतन्त्रता सेनानी प्रतिक्रियावादी शक्तियों के साथ कोई समझौता नही करना चाहते। स्वतन्त्रता संग्राम को सफल बनाने के लिए वे लोग कटिबद्ध हैं। वे इस बात की दृढ़ प्रतिज्ञा किए हुए हैं कि गुलामी के कीड़ों को अपनी मातृभूमि पर कदाचित रेंगने नहीं देंगे। जेलखाने, गोली, लाठी या फांसी का फंदा उनके अदम्य उत्साह को कम नहीं कर सकता। वे यह भी निश्चय कर चुके हैं कि अन्याय के आगे उनका सिर झुक नहीं

सकता, भले ही कट जाए। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानियों को तरह-तरह की यातनाएं दी जाती हैं, उनको मौत के घाट उतारा जाता है, न कोई अदालती कार्यवाही होती है और न कोई सुनवाई। जगली कानून राज्य करता है। जिन मां बहिनों का सुहाग लुट गया उन्हें यह भी जानने की अनुमति नहीं है कि उनका एक मात्र सहारा बन्दी गृह में किन हालतों में मौत की गोद में सुला दिया गया? श्मशान भूमि की राख भी उनकी इस दुविधा का उत्तर नहीं दे सकती। आंसुओं की अविरल धारा उनके मन को शान्त नहीं कर सकती। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका कोई उचित उत्तर नहीं मिल सकता।

जिन देशों ने स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली है वहां सी० आई० ए० का यही प्रयास रहता है कि किस प्रकार इन देशों की आज़ादी पर कुठाराघात किया जा सके।

न्यूयार्क टाइम्ज़ में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार विश्व युवक केन्द्र, नेशनल स्टुडेण्ट प्रेस कौंसिल आफ़ इण्डिया और फ्रेण्डज़ आफ़ इण्डिया ट्रस्ट को फाऊंडेशन आफ़ यूथ एण्ड स्टुडेण्ट अफ़ेयरज़ और फैयर वुड फाऊंडेशन की ओर से आर्थिक सहायता मिलती रही है। नेशनल स्टुडेन्ट्स प्रेस कौंसिल आफ़ इण्डिया के भूतपूर्व अन्तिरंग सचिव ने अपने एक वक्तव्य में जो हिन्दुस्तान टाइम्ज दिनांक २१ फरवरी १६६७ में छपा था, कहा था :

> "एक योजना के लिए हमें अवश्य फाऊंडेशन फ़ार यूथ एण्ड स्टुडेण्ट अफ़ेयरज़ न्यूयार्क से आर्थिक सहायता मिली थी परन्तु हमें किंचित भी फाऊंडेशन के बारे में कोई सन्देह न था। हमें इस बात का पता न था कि फाऊंडेशन को सी० आई० ए० से सहायता मिलती रही है।"

अज्ञानता के पर्दे में इतनी बड़ी हिमालय जैसी भूल! गल्ती करने के पश्चात् यदि मनुष्य यह निश्चय कर ले कि वह इस गल्ती को दुहरायेगा नहीं, तो इस भूल को माफ़ किया जा सकता है। परन्तु आश्चर्य की बात है कि इस संस्था ने भूलकर भी फाऊंडेशन की घिनौनी गतिविधियों की निन्दा नहीं की है। इसके बावजूद यदि सहायता प्राप्त करने वाले 'अज्ञानता' का ढिंढोरा पीट कर अपने असली रूप को छिपाना चाहें तो यह असम्भव है। इण्टर नेशनल स्टुडेन्ट्स कान्फ्रेंस जो इसलिए भंग कर दी गई है कि इसका सम्बन्ध सी०आई०ए० से था के सचिव भी एक भारतीय रहे हैं।

केनेडा के विद्यार्थियों के प्रमुख नेता डेविड यंग ने खुले तौर पर सी० आई० ए० के विरुद्ध आरोप लगाया है कि अन्तर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठियों का केनेडा के

विद्यार्थियों द्वारा बुलाने के उद्देश्य के पीछे सी० आई० ए० का हाथ था। जब कभी केनेडा मे विचार गोष्ठियां बुलाई गईं तो फाऊंडेशन फ़ार यूथ एण्ड स्टुडेन्ट अफेयरज ने उनकी धन से डटकर सहायता की, कारण यह कि इन विचार गोष्ठियो में भाग लेने वाले लोगों के साथ सम्पर्क बढ़ाने के लिए इस कार्य-क्रम को प्रयोग मे लाया जाना सम्भव था। केनेडा जैसे देश पर न तो साम्राज्यवादी होने का सन्देह किया जा सकता है न साम्यवादी होने का। उसकी इस नीति का लाभ उठा कर अमरीकी साम्राज्यवादियों की यह कोशिश रही है कि सम्मेलन या विचार गोष्ठी ऐसे स्थान पर बुलाई जाए जहां किसी प्रकार की रोक टोक न हो।

अमरीका के 'समाजवादी' नेता नार्मन थामस के विरुद्ध भी यह आरोप लगाया गया था कि उसे सी०आई०ए० द्वारा आर्थिक सहायता मिलती रही है। सी० आई०ए० ने नार्मन थामस की इन्स्टीट्यूट फार इण्टरनेशनल लेबर रिसर्च को १९६१-१९६३ में जे० एम० केप्लन के माध्यम से १० लाख डालर की आर्थिक सहायता दी थी। वास्तव में इस इन्स्टीट्यूट की सभी गतिविधियों का संचालन सी० आई० ए० द्वारा किया जाता रहा है। इसी अनुसन्धान केन्द्र द्वारा कोस्टारीका में एक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया गया था और मेक्सिको में एक प्रकाशन हाऊस भी। स्पष्ट है कि इस अनुसन्धान केन्द्र द्वारा समाजवाद का प्रचार नहीं बल्कि समाजवाद का विरोध किया जाता था। भला अमरीका की समाजवाद में किस प्रकार रुचि हो सकती है?

२६ फरवरी १९७० को अमरीका के एक प्रमुख अधिकारी ने वाशिंगटन में चर्चा करते हुए कहा था कि भारतीय बुद्धिजीवियों को अमरीका का भ्रमण कराने के लिये सी० आई० ए० धन का प्रयोग किया जाना नितांत आवश्यक समझती है। इसी प्रमुख अधिकारी ने 'वाशिंगटन पोस्ट' के सम्वाददाता को बताया था कि यह असम्भव है कि भारतीय बुद्धिजीवी अमरीकी सरकार से सफ़र खर्च लेना मान लें, इसलिए यह आवश्यक है कि यह सहायता अन्य सूत्रों से दी जाए ताकि इन बुद्धिजीवियों को सहायता प्राप्त करने में कोई आपत्ति न हो। इस अधिकारी ने इस प्रकार दी जाने वाली सहायता का समर्थन करते हुए कहा था कि "भारतीय बुद्धि जीवी वर्ग विदेशी सरकार से सहायता इस लिए भी प्राप्त नहीं करना चाहते क्यों कि ऐसा करने से उनके स्वाभिमान को ठेस पहुँचती है और उनको अपने देश में कई प्रकार की प्रतिक्रिया हो सकती है। उससे बचने का एक सरल तरीका यह है कि उन लोगों को अमरीकी गैर-सरकारी संस्थाओं से सहायता दी जाए ताकि वे अपने आपको स्वतन्त्र व्यक्ति समझ सकें।"

इस जटिल समस्या को सुलझाने के लिए ही सी० आई० ए० ने गैर-सरकारी संस्थानों को आर्थिक सहायता देना मन्जूर किया है। एक अन्य संस्था जिसमें सी० आई० ए० की विशेष रुचि रही है वह है—कमेटी फ़ार सेल्फ़-डिटरमीनेशन अर्थात स्वशासन अधिकार समिति। इसके अतिरिक्त अन्य सस्थाओ में काग्रेस फ़ार कल्चरल फ्रीडम और रेडियो पीस यूरोप प्रमुख हैं। इन सस्थाओ के माध्यम से भारत और अन्य देशों के प्रतिक्रियावादी तत्वों की सहायता की जाती है। इसी संस्था के माध्यम से कई प्रतिनिधि मण्डल फार्मूसा और सैगोन भेजे जा चुके हैं।

अमरीकी सरकार अमरीकी केन्द्रीय श्रमिक सस्था की धन से इसलिए सहायता करती रही है कि इस संस्था के माध्यम से विश्व के अन्य देशों में श्रमिक संगठनों के साथ सम्पर्क बढाया जा सके। खास तौर पर उन देशों में श्रमिक संगठनों पर अधिक बल दिया जाता रहा है जो देश अर्ध-विकसित हैं। इस से पूर्व अमरीकी श्रमिक सस्था को सी० आई० ए० से सहायता मिलती थी और वह भी तथा कथित सस्थानों के माध्यम से। जब सी० आई० ए० का भेद खुल गया तो कुछ संस्थानों का आश्रय लिया गया। उनका नाम भले ही अलग हो लेकिन काम में कोई अन्तर नही। वही है चाल बेढंगी, जो पहले थी वह अब भी है। पैसे के लालच में किस किस का ईमान खरीदने का प्रयास नही किया जाता ? कोई इस कुकर्म के लिए इन्हें धिक्कारे भी तो क्या ? बेशर्मी की हद होती है लेकिन जब कोई इस दायरे में सीमित न रहना चाहे तो उसके सामने कोई तर्क काम नहीं करता। कौन समझाए इन लोगों को कि जो श्रमिक अपनी मुट्ठी में अपनी तकदीर समझते हों उन्हे डालर की माया से पथ भ्रष्ट नहीं किया जा सकता ?

किसी एक सस्था के बदनाम होने पर तुरन्त नई संस्था बनाने के काम मे अमरीका निपुण है। अब धन से सहायता देने का काम एक अन्य संस्था के जिम्मे है जिसका नाम है युनाईटिड स्टेट्स एजसी फार इण्टरनेशनल डिवेल्पमेंट। इस संस्था से जिन अन्य संस्थाओं को सम्बद्ध किया गया है उनमें प्रमुख हैं—अमेरीकन रिटेल क्लर्कस इण्टरनेशनल और इण्टरनेशनल फेडरेशन आफ़ पेट्रोलियम एण्ड केमिकल वर्कर्स। इसके अतिरिक्त इस अमरीकी एजंसी के माध्यम से विभागीय श्रमिक संस्थाओं को अफ्रीका, एशिया और लतीनी अमरीका में कार्यवाहियो का सचालन करने के लिए धन की सहायता दी जाती है। जब किसी संस्था को आर्थिक सहायता दी जाती है तो उस संस्था से यह आशा की जाती है कि वह गैर-साम्यवादी राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का सहयोग देगी। अब तो आर्थिक सहायता व्यापक रूप मे दी जाने लगी

है और छोटी-मोटी कई संस्थायें इसका पूर्णरूपेण लाभ उठा रही हैं। कारण यह है कि इस प्रकार की आर्थिक सहायता देने के लिए सरकारी अनुमति की आवश्यकता नहीं है और न ही अन्य देश की सरकार का इसमें कोई दखल है। सीधा सम्पर्क सहायता देने और लेने वाले के बीच रहता है। जहा-जहा भी सी० आई० ए० को बदनाम होने के कारण हटना पड़ा है, वहा तुरन्त किसी अन्य संस्थाओं के जिम्मे वही काम सौंपा जा चुका है।

बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्ज में सबसे ऊंची और शानदार इमारत उस देश की समाजवादी पार्टी की है परन्तु यही समाजवादी पार्टी अफ्रीका और एशिया में चल रहे आजादी के आन्दोलनों का समर्थन नही करती बल्कि प्रतिक्रियावादियों और आजादी के शत्रुओ की सहायता करती है। इस संस्था के अधिकाश सदस्यों को सी० आई० ए० से आर्थिक सहायता मिलती है। ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी के नाम पर यह पेशेवर क्रान्ति-विरोधी लोगों का टोला हो। ब्रसल्ज मे अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठन का प्रमुख कार्यालय है। इसी नगर में विद्यार्थियों के अन्तर्राष्ट्रीय सगठन का भी कार्यालय था जिसे इसलिए भग कर दिया गया क्योंकि इस सस्था के विरुद्ध सी० आई० ए० से आर्थिक सहायता प्राप्त करने का भीषण आरोप था। यह सस्था भग तो कर दी गई परन्तु इसके स्थान पर एक नई सस्था कायम कर दी गई है जिसका नाम है—इन्स्टीट्यूट दि-इण्टरनेशनल इतुदियां सुर ला-एजूकेशन। संस्था बनते देर नहीं लगती क्योंकि नाम ही तो बदलना है काम मे तो कोई अन्तर नहीं होता। ब्रसल्ज मे तो सी० आई० ए० की गतिविधियां बहुत बढ चुकी हैं क्योंकि इस स्थान पर प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र हैं, विद्यार्थियों, श्रमिकों और युवको के।

आज के अन्तरिक्ष-युग में सीटो, नाटो और सेंटो जैसे सैनिक संगठनो का महत्व कम हो गया है परन्तु इन सगठनो के पीछे सी० आई० ए० का हाथ रहने से इन संगठनों की गोपनीय गतिविधियों पर दृष्टिपात करना जरूरी है। सैनिक आक्रमण तो आज के युग में इतना सरल नही है जितना कि गोपनीय ढग से किसी अन्य देश की राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक अवस्था में घुस पैठ करना। यही काम सी० आई० ए० का है। सी० आई० ए० का काम है इन्टेलीजेन्स अलायन्स द्वारा सैनिक सगठनों मे एकता बनाए रखना, उनकी कार्यवाहियो को बढावा देना और समय पडने पर हर प्रकार की सुविधा प्रदान करना ताकि जो राष्ट्र एक बार इस चंगुल मे फंस जाए तो वह बचकर निकल न सके।

ऊंट रे ऊंट ! तेरी कौनसी कल सीधी ? सी० आई० ए० का कौनसा काम घिनौना नहीं ? इसके किस कार्य पर गर्व किया जाए ? सी० आई० ए० राजनीति में ही दखल नहीं देती बल्कि सट्टे बाज़ों का भी टोला है। इन्ही सट्टे बाजो के माध्यम से हथियारों का सौदा किया जाता है। सट्टे बाज़ों के कारण ही युद्ध का भीषण वातावरण पैदा किया जाता है और इसका लाभ उठा कर हथियारों का सौदा किया जाता है। ज़ाहिर है जिसका काम हथियार बेचना हो वह चाहेगा कि हथियारों की मांग बढ़ती रहे अर्थात युद्ध के बादल मंडराते रहें। हथियारो में तेज़ी और मन्दे की सूचना भी सी० आई० ए० के माध्यम से दी जाती है। यदि कोई देश किसी समाजवादी देश से हथियार खरीदना चाहे या विमान लेने का सौदा करना चाहे तो सी० आई० ए० वाले समाचार पत्रों के माध्यम से यह सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि अमुक समाजवादी देश के जहाज़ काम में नही लाए जा सकते। सैनिक समान खरीदने के बारे में, जिसे प्राय: गोपनीय रखा जाना चाहिये, देश के समाचार पत्र टीका टिप्पणी करना शुरु कर देते हैं।

हथियार बेचने की होड़ में विचारों की लड़ाई शुरु हो जाती है और इस लड़ाई में उन लोगों की सहायता ली जाती है जो रिटायर होने से पहले सरकारी क्षेत्र में अच्छे पद पर रहे हों। फोर्ड फाऊंडेशन मे काम करने वाले व्यक्तियों में अधिकाश लोग वे हैं जो सरकारी अफ़सर रह चुके हों। काम करने वालों में लायक अधिकारियों की लड़किया आसानी से नौकरी हासिल करती हैं। अधिकारी स्वयं न सही उसकी लडकी उतना ही योगदान दे सकती है। इस आधार पर फोर्ड फाऊं-डेशन का काम चलता है। इसके अतिरिक्त सी० आई० ए० ने टेपरिकार्ड और फोटो द्वारा ब्लैकमेल करने का तरीका भी अपनाना शुरु किया है। पश्चिम जर्मनी मे लोक सभा के एक बहुत बडे अधिकारी की वार्ता को टेप रिकार्ड करने के बाद उसे अपने राष्ट्र के विरुद्ध काम करने के लिए कहा गया। पाश्चात्य देशों के दूतावासों में सी०आई०ए० से सम्बन्ध रखने वाले लोगों का जाल बिछा रहता है। शायद ही कोई पाश्चात्य देश ऐसा होगा जिसके दूतावास में सी० आई० ए० के एजेन्ट न हों। यहां यह बात भी उल्लेखनीय है कि अमरीकी कम्पनियों ने अन्य देशों में बड़े २ समाचार पत्रों में हिस्से खरीद रखे हैं। टेलीवीज़न कम्पनियों पर भी इसी प्रकार नियंत्रण रखने का प्रयास किया जाता है। फ्रांस जैसे देश में जहां फ्रांसीसी भाषा का ज़ोर है दूर देहातों में अंग्रेजी भाषा में छपने वाले समाचार पत्रों की भरमार है। इन समाचार पत्रों में छपने वाले समाचारों में इतनी ताजगी होती है कि यह समाचार

पत्र लन्दन टाइम्ज़ और बी० बी० सी० से भी पहले समाचार प्रसारित करते हैं। फ्रांस में जनरल दी गाल के बाद सी० आई० ए० का इस प्रकार विस्तार फ्रांस के देशभक्तों के लिए एक चुनौती है।

ब्रिटेन में गिरजाओं के अन्दर जितनी सजीदगी पाई जाती है अमरीकी ढंग पर बने हुए गिरजाघरों मे नही। अमरीकी ढंग के बने गिरजाघरो मे ड्राई-रूम भी है, बाल-रूम भी और प्रार्थना कक्ष भी। यही कारण है कि धर्म के इन ठेकेदारों की कोई बात समझ मे नहीं आती। फलस्तीन मे यदि यहूदी, मस्जिदों और पवित्र स्थानों को क्रीड़ा स्थलों मे बदल कर प्रेमी और प्रेमिकाओं के केन्द्र मे परिणत कर दें तो यह दुःख की बात तो अवश्य है आश्चर्य का विषय नही। क्योंकि ईस्राईल सरकार भी अमरीकी साम्राज्यवादियों के इशारों पर इन्ही पूजा स्थलों को ग़लत कामो के लिए प्रयोग मे ला रही है। अमरीका में नए पीढी के लोगों को सिखाया जाता है कि किस प्रकार वे Humour with God and Fun in the Church अर्थात भगवान के साथ दिल्लगी और गिरजाघरों मे हसी मजाक को चरितार्थ कर सकें। नौजवान लडके और लडकियां इन केन्द्रो मे जाती हैं जहा धन का प्रयोग पानी की भांति किया जाता है। जरा सोचिए, इन गिरजाघरों के पास इतना धन कहा से आया ? यह भगवान की अनुकम्पा है या फोर्ड फांऊडेशन की, यह भगवान का नियम है या सी० आई० ए० का। किसका अधिकार है इन भगवान के घरो पर, भगवान का या पूँजी के दलाल का ? यीशू मसीह की आत्मा इनको आशीर्वाद देती होगी या धिक्कारती होगी। पाश्चात्य सभ्यता के रंग मे डूबे हुए कुछ धनवानो ने खुदा को भी अपनी तिजोरी मे बन्द कर रखा है और वे नही चाहते कि उनके आडम्बरो का भाण्डा फोडा जाए। लेकिन कब तक ? जब तक इन्सान सोता है, उसके जागते ही यह नकली पहरेदार या धर्म के ठेकेदार दुम दबाकर भाग जाएंगे। हमारी धारणा है कि अमरीकी ढंग के गिरजाघरो से या तो हिप्पी पैदा होगे या डकैत, धर्म मे निष्ठा रखने वाले इन्सान पैदा नहीं हो सकते। सी० आई० ए० की यही कोशिश रहती है कि पहले देश की संस्कृति को निपुंसक बना दिया जाए और फिर सास्कृतिक पुनरुत्थान के नाम पर उस देश मे घुसपैठ की जाए। जहां सी० आई० ए० का बोल बाला हो जाए तो समझ लीजिए कानून की छुट्टी मिल गई। आपको अधिकार है किसी का गला दबोचिए या किसी का गौरव छीनिए। अगर आप शान्ति चाहते हैं तो घर की चार दिवारी मे बन्द रहिए, रात को बाहर मत निकलें अन्यथा जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। कोई किसी की रक्षा नही कर सकेगा। अगर आप यह नही चाहते तो सी० आई० ए० और उस जैसी

अन्य संस्थाओं को चोर दरवाज़े से भी अपने देश में मत घुसने दीजिए। श्री लंका में सी० आई० ए० की बुरी तरह पिटाई की जा रही है। क्यूबा के बहादुर लोगों ने सी० आई० ए० की हालत खराब कर रखी है। जासूसी करने के लिए पकड़े गए अमरीकी सैनिकों ने स्पष्ट रूप में बताया है कि क्यूबा के खिलाफ अमरीका, प्रशिक्षण केन्द्रों से जासूसी की ट्रेनिंग देकर भेजता है। वे लोग जो गिरफ्तार किए जा चुके हैं उनमें से अधिकांश लोग सी० आई० ए० के एजंट के रूप में काम करते रहे हैं।

कांगो मे पेट्रिक लुमुम्बा की हत्या के पीछे भी सी० आई० ए० का हाथ था क्योंकि पेट्रिक लुमुम्बा के नेतृत्व मे साम्राज्यवाद कोमुह की खानी पड़ी थी। लेकिन शर्म की बात है कि लुमुम्बा के हत्यारे शोम्बे को सी० आई० ए० के संरक्षण में एक बार कटंगा से ब्रसल्ज ले जाया गया और वहां से ही कांगो के प्रगतिशील आंदोलन को कुचलने की योजना बनाई गई। उठते हुए राष्ट्रों की प्रगति को रोकने के लिए राष्ट्रीय नेताओं की हत्या करने या उन्हें अपमानित करने की योजना सर्वथा निंदनीय है। भारत में भी पाश्चात्य देश के दूतावास के एक लेबर अटेची ने पैसा देकर एक भारतीय मजदूर नेता से प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गाधी के खिलाफ़ घृणास्पद पोस्टर लगवाया था। जब इस बात की खोज हुई तो उस अटेची को भारत छोडना पड़ा।

कौन सा घिनौना काम ऐसा नही जिसे सी० आई० ए० न करता हो? इन कार्यवाहियों के केन्द्र हैं धर्म के नाम पर चलने वाले कही-कही वाई० एम० सी० ए० या वाई० डब्लू० सी० ए० के होस्टल। यह सही है कि होस्टल के प्रबन्धकों को इस बात का ज्ञान नही होता कि कौन इस होस्टल मे टिकता है और उसकी क्या दिनचर्या है लेकिन यह बात सत्य है कि इन होस्टलों का प्रयोग आसानी से किया जा सकता है क्योंकि संस्कृति या सभ्यता का विरोध कौन करेगा? इतनी बड़ी शानदार संस्था को इस्तेमाल करने मे भी सी० आई० ए० को कोई शर्म नही आती।

नाईजीरिया में 'बांटो और राज्य करो' की नीति के आधार पर नाईजीरिया के एक प्रान्त बायाफ्रा के लोगों को भड़का कर, फुसला कर, स्वतन्त्र रहने का चकमा देने के पीछे भी सी० आई० ए० का हाथ था। नाईजीरिया की आजादी को खतरे मे डालने की यह साम्राज्यवादी चाल थी। भोले भाले लोग फस गए। पृथक बायाफ्रा आन्दोलन मे नाईजीरिया और बायाफ्रा के कई लोग मारे गए। बायाफा को पृथक रखने की माग करने वालों का समर्थन सी० आई० ए० और लाल चीन के लोग

करते थे। दो साम्राज्यवादियों के बीच समझौता इस लिए हुआ कि दोनों आजादी के शत्रु हैं। सी० आई० ए० और लाल चीन के इरादों में कोई अन्तर नहीं। एक पश्चिम से उठा है पाश्चात्य सभ्यता का लिबास पहन कर, दूसरा पूर्व से उठा है शैतान का रूप धारण कर के। दोनों आजादी के सूर्य को उदीयमान होता नहीं देख सकते। एक माओ-वाद का गुलाम है तो दूसरा साम्राज्यवाद का। प्रकट रूप में दोनों एक दूसरे के प्रति विरोधाभास दिखाते हैं लेकिन है मिली भक्त। एक तेल फेंकता है तो दूसरा आग लगाता है। एक विस्तारवादी है तो दूसरा पूर्ण रूपेण साम्राज्यवादी। नाईजीरिया में झगड़े का कारण उस देश के खनिज पदार्थ थे। चीन, अमरीका और ब्रिटेन की नजर खनिज पदार्थों पर थी और यही कारण है कि वे बायाफ्रा के पृथक रहने की माग को लेकर खनिज पदार्थों की बांट के लिए समझौता कर रहे थे। नाईजीरिया की राष्ट्रवादी सरकार ने पूरी शक्ति के साथ बायाफ्रा को अलग करने की मांग का विरोध किया। विजय राष्ट्रवादियों की हुई, चीन हार गया, अमरीका को मुंह की खानी पड़ी, सी० आई० ए० की चाल बेकार हो गई।

स्वतन्त्र देश में अन्दर ही अन्दर पृथकतावादी आदोलन की आग को सुलगाने का काम करते हैं सी० आई० ए० के एजेंट, क्योंकि वे जानते हैं कि पृथकतावादी आदोलन से ही आजाद देश की शक्ति को क्षीण किया जा सकता है। जब साम्राज्यवादी शक्तियां परास्त हो जाती हैं तो वे 'बांट-बटवारे' की नीति के बीज बोकर तमाशा देखती हैं। इसी प्रकार जब भारत स्वतन्त्र हुआ तो नागालैंड में ऐसी पृथकतावादी शक्तियों की सहायता करने के लिए ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने कई हत्यकण्डे अपनाए। फिज़ो भारत से फरार हुआ तो ब्रिटेन में एक पादरी की शरण में पहुँचा। नागालैंड मे काफी समय तक विद्रोही नागाओं ने हुलडबाज़ी की। सी० आई० ए० के एक एजेंट जानस्मिथ के कथनानुसार १६५६ में सी० आई० ए० ने अपने एक एजेंट को टेक्नीकल कोओपरेशन मिशन के नाम पर अमरीकी मिलिट्री अटेची के साथ इम्फाल भेजा था और उन्होने वहां कई विद्रोही नागाओं से भेंट भी की थी। जानस्मिथ का कहना है कि अमरीकी अटेची ने नागाओं को दस लाख रुपये की कीमत के हथियार दिए और उन्हे कहा कि जब तक अमरीकी सहायता नहीं पहुँचती वे विद्रोह जारी रखें। इसके अतिरिक्त ढाका स्थित अमरीकी कौंसिल जनरल और सी० आई० ए० एजेंट की पूर्वी पाकिस्तान में विद्रोही नागाओं के साथ खुफिया बातचीत भी हुई और इसी मीटिंग में विद्रोही नागाओं को आर्थिक सहायता और

हिदायतें भी दी गई। नागा विद्रोहियों को हथियार देने का काम एक अन्य सी० आई० ए० एजेंट जोसफ़ म्कालर के जिम्मे था जो पूर्वी पाकिस्तान से हथियार भेजता था। इस काम मे ज़ोन ग्रोवर सहयोगी था और देहली में उनका सम्बन्ध बलारा पापास से था।

जिन लोगों ने नागा विद्रोहियों को प्रशिक्षण एवं हथियार दिए उनमें डविड हेनरीब्ली का नाम उल्लेखनीय है जो १६५० में पाकिस्तान मे अमरीकी दूतावास मे अटेची वन कर आया और भारत व पाकिस्तान में सी० आई० ए० की गतिविधियों मे ताल मेल बढ़ाने का काम करता रहा। यह व्यक्ति १६६२ मे दिल्ली भी आया था। स्मिथ ने यह भी बताया कि सी० आई० ए०, नागा विद्रोहियों की सहायता करने के अतिरिक्त पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पर भारत विरोधी कार्यवाहियों को भी प्रोत्साहन देती थी। इस काम की देख रेख डेविड बरगस करता था जो १६५६ को भारत आया और जिसने कई बार नागालैंड के उन इलाकों का दौर किया जहां पृथकतावादी आंदोलन चल रहा था इस कार्य में चैपमेन उसका सहयोगी था।

स्मिथ ने जैंक कूरान का भी ज़िक्र किया है जो सारे भारत में सी० आई० ए० की गतिविधियों का इंचार्ज था। १६ नवम्बर १६६७ की इण्डियन एक्सप्रेस में छपे समाचार के अनुसार जैंक कुरान वही व्यक्ति है जिसने इन्सटीट्यूट आफ़ पैसेफ़िक रिलेशनज न्यूयार्क की ओर से राष्ट्रीय स्वय सेवक संघ के बारे में पुस्तक छापी है। यहां यह बात उलेखनीय है कि यह पुस्तक १६५१ मे छपी जब जैंक कुरान भारत आया हुआ था। जेक का जन्म चीन में हुआ, बर्मा में उसकी परवरिश हुई और भारत में सामाजिक ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने के लिए सी० आई० ए० से ग्रांट लेकर आया।

आखिर सी० आई० ए० ने नागा विद्रोहियों की सहायता क्यों की ? इस पर विचार करना आवश्यक है।

भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का साया उठ जाने के बाद भारत को जो कुछ विरासत में मिला उसमे लाखों करोड़ों लोग ऐसे भी शामिल थे जो अनपढ़ थे और रूढिवादिता का शिकार थे और जो किसी भी समस्या को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से न देख सकते थे। अग्रेजों ने उन्हें जान बूझकर अज्ञानता के दायरे में बन्द रखा

और जब भारत स्वतन्त्र हुआ तो इन्ही अज्ञानता के पिंजरे में बन्द लोगों को साम्राज्यवादियों ने इस्तेमाल करना शुरु कर दिया। साम्राज्यवादी हत्कण्डो में प्रमुख स्थान मिलता है सीमाओं पर छेड़खानी करने को। सीमाओं पर गोला बारुद चलता रहे इस काम के लिए सीमा पर विद्रोह करने वाले लोगो की धन, प्रशिक्षण और हथियारो से सहायता की जाती है।

नागालैंड मे नागाओं को उकसाने के लिए भी सी० आई० ए० ने यही काम किया। साम्राज्यवादियो को ख्याल था कि धधकता हुआ नागालैंड भारत की आजादी को कमजोर कर देगा लेकिन हुआ बिल्कुल विपरीत। नागालैंड के देशभक्तो ने न केवल विद्रोहियो के दात खट्टे कर दिए बल्कि यह सिद्ध कर दिया कि साम्राज्यवादियों की कमीनी हरकतों का नागालैंड पर कोई प्रभाव नही पड़ सकता।

इसी प्रकार सी० आई० ए० की यह कोशिश रही है कि भारत की उत्तरी सीमा पर उथल पुथल होता रहे और अपने इस प्रयास से सफल बनाने के लिए सीमा पार क्षेत्रों में सी० आई० ए० के एजट तखरीबी कार्यवाहिया करने में संलग्न रहते हैं। 'आजाद काश्मीर' सरकार तो पिट्ठु सरकार है ही, इसका सब काम पिछलग्गुओं का है। काश्मीर के बारे में भारत की नीति बहुत स्पष्ट रही है और इस नीति की हर जगह सराहना हुई है। भारत कह चुका है कि चूकि पाकिस्तान ने भारतीय क्षेत्र पर अतिक्रमण किया है इसलिए पाकिस्तान के लिए जरूरी है कि वे भारतीय क्षेत्र से तुरन्त हट जाए।

कभी २ 'आजाद काश्मीर' का नारा भी सुनने मे आता है। यह नारा उन लोगों की ओर से लगाया जाता है जो आजादी के शत्रु हैं और चाहते हैं कि काश्मीर विदेशी शक्तियो के हाथ मे कटपुतली बन जाए और भारत की आजादी के लिए हमेशा खतरा बना रहे। चाहे रायशुमारी मोर्चा हो या कोई और सस्था, काश्मीर को भारत से अलग करने की मांग करने वाले विदेशी शक्तियों के हाथ खेल रहे हैं। इसलिए कोई भी सरकार अपने देश में इन तत्वों को सहन नहीं कर सकती। संयुक्त राष्ट्र में जब भूतपूर्व प्रतिरक्षा मन्त्री कृष्णा मेनन ने तर्क के साथ पाकिस्तान की थोथी दलीलों का मुंह तोड़ उत्तर दिया तो पाकिस्तान के अतिरिक्त साम्राज्यवादी अमरीका और बर्तानिया भी बौखला उठे थे। परिणाम स्वरूप जब कृष्णा मेनन ने १९६२ और १९६७ का चुनाव लड़ा तो सी० आई० ए० वालों ने कृष्णा मेनन का विरोध करने के लिए अपनी थैलियों के मुंह खोल दिए। अमरीकी

पता पानी की तरह बहाया गया ताकि कृष्णा मेनन चुनाव जीत न सकें। कृष्णा मेनन की जीत साम्राज्यवादियों की हार होती। चुनांचे सी० आई० ए० ने अपने भारतीय एजेंटों की सहायता से चुनाव को जिंदगी और मौत का प्रश्न बना लिया।

२३ नवम्बर १९६७ को लोक सभा में स्मिथ के ब्यान पर विस्तृत चर्चा हुई। लोक सभा के कई सदस्यों ने माग की कि 'काश्मीर प्रिंसेस' नामी भारतीय हवाई जहाज में विस्फोट के बारे मे जिन अमरीकी अधिकारियों का नाम स्मिथ ने अपने ब्यान में लिया है, उनके विरुद्ध सरकार क्या कदम उठा रही है ? सदस्यों ने यह भी जानना चाहा कि वह अमरीकी कौन है जिस पर विस्फोटक कार्यवाही का आरोप लगाया गया है। गृह मन्त्री यशवन्तराव चह्वाण ने संसद में बताया कि वह व्यक्ति अमरीकी दूतावास का अधिकारी है और अब भी वहीं काम करता है। 'काश्मीर प्रिंसेस' नामी भारतीय हवाई जहाज के साथ १९५५ में दक्षिण-चीनी समुद्र मे दुर्घटना हुई थी जिसकी जिम्मेदारी सी० आई० ए० पर है। स्मिथ ने इस घटना का जिक्र करते हुए कहा कि उसने स्वयं, बिना जाने हुए, दो टाईम बम, कोमिंटाग चीन के एक व्यक्ति को जो हांगकाग मे काम करता था को देने के लिए भेजे। यह सब क्यों किया गया ? इसके बारे में जानकारी देते हुए स्मिथ ने कहा कि १९५५ में घटना से कुछ दिन पूर्व दिल्ली स्थित अमरीकी अटेची ने कहा था : 'स्मिथ ! मुझे आपकी सेवाओं की आवश्यकता है क्योंकि मैं अपने एक मित्र को तुरन्त ही कुछ भेजना चाहता हूं।' उस अटेची ने दिल्ली के होटल का जिक्र करते हुए कहा कि उस होटल में कोई व्यक्ति उसकी प्रतीक्षा कर रहा होगा, उसे कहना कि 'मैंने यह थैला उसके पास भेजा है।' वह थैला भारी था और जब स्मिथ ने उस अटेची से पूछा कि इस थैले में क्या है तो उसने उत्तर दिया कि वह स्वयं भी नहीं जानता और यह थैला बन्द किया हुआ मिला है और उसे यह हिदायत दी गई है कि वह इस थैले को खोले बिना ही अमुक व्यक्ति के पास भेज दे। स्मिथ ने हिदायत अनुसार वह थैला निश्चित व्यक्ति को जाकर दिया। स्मिथ ने आगे चलकर यह भी बताया है कि उसके विवाह के उपरान्त उसकी धर्म पत्नी, जो सी० आई० ए० की एजेंट थी, ने उसे बताया कि उस थैले में दो टाईम बम भेजे गए थे। वे बम हांगकांग से 'काश्मीर प्रिंसेस' नामक हवाई जहाज में रखे गए। यह हवाई जहाज विस्फोट होने के कारण, उडान के आधा घंटे बाद ही समुद्र में गिर कर तबाह हो गया। यह जहाज हांगकाग से इण्डोनेशिया जा रहा था और रास्ते मे ही उसके साथ यह दुर्घटना हुई।

स्मिथ ने यह भी बताया कि भारत के भूतपूर्व रक्षा मन्त्री कृष्णा मेनन को

चुनाव में हराने के लिए सी० ग्राई० ए० ने लाखों डालर खर्च किए। सी० आई० ए० कृष्णा मेनन का इसलिए विरोध करती रही है क्योंकि कृष्णा मेनन ने काश्मीर की समस्या को लेकर संयुक्त राष्ट्र में साम्राज्यवादी चालों का भाण्डा फोड़ा था। परिणाम स्वरूप १९६२ के श्राम चुनाव में कृष्णा मेनन का डटकर विरोध किया गया परन्तु सी० ग्राई० ए० के हत्थकण्डे असफल रहे। १९६७ में बम्बई चुनाव क्षेत्र में वही बात दुहराई गई जिसके कारण दो बार बम्बई से कृष्णा मेनन की हार हुई।

सी० ग्राई० ए० की गतिविधियो को लेकर २३ नवम्बर १९६७ को भारतीय संसद में काफी चर्चा हुई थी। इस दौरान सदस्यो ने यह भी माग की थी कि जिस व्यक्ति के बारे मे स्मिथ ने चर्चा करते हुए उसे 'कश्मीर प्रिंसेस' की दुर्घटना के लिए दोषी ठहराया है क्या वह व्यक्ति अमरीकी दूतावास का अधिकारी है ? केन्द्रीय गृह मन्त्री ने उत्तर देते हुए बताया था कि वह व्यक्ति अमरीकी दूतावास में काम करता था। गृह मन्त्री ने यह भी बताया था कि तीन अमरीकी सस्थानों—फोर्ड फ़ाऊडेशन, राक फ़ीलर ाफऊडेशन ग्रौर एशिया फ़ाऊडेशन —को गैर-सरकारी सस्थानों ग्रौर ट्रस्टों से ग्राथिक सहायता मिलती रही है ग्रौर मजे की बात यह है कि इन सस्थानो को ग्राथिक सहायता सी०ग्राई०ए० करती है। यह तिकडमबाजी नही तो ग्रौर क्या है ? गृह मन्त्री ने जोरदार शब्दो मे कहा था कि इन सस्थानो को मनमानी करने की छूट नही दी जा सकती ग्रौर ग्राथिक सहायता के इस कुकर्मी जाल को फैलने से रोका जाएगा।

ग्रमरीकी खुफ़िया विभाग ने दक्षिण पूर्व एशिया के लिए दिल्ली में केन्द्र स्थापित करके अपनी योजनाग्रो को कार्यान्वित करना शुरु किया था। इस बात की चर्चा करते हुए स्मिथ ने यह भी कहा है कि भारतीय सरकार को विवश होकर एक ग्रमरीकी ग्रधिकारी को भारत छोडने का ग्रादेश देना पड़ा क्योंकि उस व्यक्ति की गतिविधिया भारत-विरोधी थी। इस ग्रमरीकी ग्रधिकारी का नाम रोजीकी बताया जाता है। इस बात से इन्कार नही किया जा सकता कि सी० ग्राई० ए० का काम ग्रन्य देशों मे ऐसी कार्यवाहियों को बढावा देना है जिससे वह राष्ट्र प्रगति के पथ पर अग्रसर न हो सके। यह उन लोगो को सहायता करता रहा है जो जवाहर लाल नेहरू की प्रगतिशील नीतियों के विरोधी थे ग्रौर जो ग्रब भी इन्दिरा सरकार का विरोध इसलिए करते हैं कि देश से गरीबी को हटाने की योजनाए सफल न हो सकें।

राजनैतिक दबाव की नीति

किसी भी देश की राजनैतिक परिस्थिति में कब और कैसा मोड़ आ जाए इसके बारे में भविष्य वाणी नही की जा सकती भले ही थोड़ा बहुत अन्दाजा लगाया जा सकता हो। भारत में जब दल बदलने वालों की हरकतों से ऐसा अन्दाजा लगाया जाने लगा कि शायद राजनीति में कोई विशेष परिवर्तन होने वाला है तो सी० आई० ए० ने अपनी गतिविधिया राजनैतिक क्षेत्र पर प्रभाव डालने के लिए अधिक तेज कर दी। सबसे पहले यह मान कर कि मन्त्री तो बदल सकते हैं, मत्रालय में काम करने वाले प्रमुख अधिकारी नहीं, सी० आई० ए० ने यह उचित समझा कि वह प्रमुख अधिकारियो के माध्यम से उपयुक्त सूचना भी हासिल करे और साथ-साथ उन्हें अपना पिछलग्गु भी बना ले।

सी० आई० ए० की नीति में यह तीसरा मोड़ था। पहले राजनैतिक दलों को गांठा गया, फिर राजनैतिक क्षेत्र मे काम करने वाले कुछ लोगों को और इसके पश्चात लाल फीताशाही के जन्मदाताओं को।

भारत में अधिकारी वर्ग प्रारम्भ से ही प्रभावशाली रहा है और उसकी जड़ें काफ़ी मजबूत हो चुकी हैं। अब भी अधिकारी वर्ग यही समझता है कि सरकार उनके ही बल बूते पर चल रही है। सरकार गल्त काम करे तो स्वाभाविक है कि लोग सरकार-विरोधी होगे, उनको क्या मालूम कि सरकार की मशीनरी के पुर्जों को जग लगा हुआ है और लाल फीताशाही अपनी मनमानी करती है। हम सब अधिकारियों को दोषी नही ठहराते परन्तु उन लोगों की आलोचना किए बिना नही रह सकते जो अन्न तो भारत का खाएं और गुणगान अमरीका का करें। पेंशन सरकार से हासिल करें और रिटायर होने के बाद नौकरी टाटा या बिरला की या किसी

विदेशी फर्म की करें। जब तक सरकारी नौकरी में रहें सेवा पूँजीपतियों की करें और नौकरी से मुक्त होने के बाद चाकरी उन लोगों की करें जो इनके पूर्व-सरकारी सम्बन्धों का लाभ उठा कर कोटा और परमिट हासिल कर सकें।

हाथी जिन्दा लाख का और मरा हुआ सवा लाख का ! यह अधिकारी रिटायर होने के बाद भी उतना ही वेतन पा लेते हैं जितना उन्हें पहले मिलता था। दुःख तो इस बात का है कि जब एक अधिकारी सरकारी नौकरी के दौरान विदेशी फर्मों से सम्बन्ध जोडता है और रिटायर होकर उस विदेशी फर्म में काम करने को राजी हो जाता है। कुछ समय से विदेशी एजंसियों ने यह धन्धा शुरु कर रखा है कि बड़े-बड़े सरकारी अधिकारियों, उनकी धर्म पत्नियो और बच्चों को किसी न किसी बहाने विदेश भिजवाते हैं तथा इस प्रकार सम्पर्क बढ़ा कर उनसे लाभ उठाया जा सके।

भारत मे लाल फीताशाही को दो सरकारों के आधीन कार्य करने का तजुरबा हासिल है, एक सरकार विदेशी थी और दूसरी देशी। इसलिए हम यह नही मानते कि इन लोगों को विदेशी कुचक्रों का ज्ञान नही है। विदेशी एजंसियां लोगो को राष्ट्र विरोधी जाल मे फसाकर इन लोगों से अपने ही देश के विरुद्ध जासूसी करने के लिए तैयार करती हैं।

आश्चर्य का विषय है कि लगभग ५०० से ६०० अधिकारी इस समय तक विदेश यात्रा के लिए विदेशी एजंसियों के कृपा पात्र बन चुके हैं। मजे की बात यह है कि वे अधिकारी जो अधिक तजुरबा हासिल करने के लिए विदेश जाते हैं, उनके इस तजुरबे का लाभ हमारे देश को नहीं होता। अधिकांश लोग तो सेवा से निवृत्त होने के कुछ मास पहले ही विदेश यात्रा की योजना बनानी आरम्भ कर देते हैं। वे लोग जो आधुनिक जानकारी प्राप्त करने के लिए गए हैं निश्चित ही भारत लौटने पर उनकी यह धारणा बन गई होगी कि उससे कम जानकारी देने वाले हमारे देश में नही हैं। प्रश्न उठता है कि विदेशों में शैक्षणिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए अधिकारी वर्ग को क्यों प्रेरणा दी जाती है ? कारण यह है कि इन अधिकारियो के माध्यम से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा सकता है। वरना कौनसा ऐसा काम है जिसकी विशेष शिक्षा विदेश में ही दी जा सकती हो, देश में नहीं ? क्या हमारे विश्वविद्यालय किसी देश के अन्य विश्वविद्यालयो से कम ख्याति प्राप्त हैं ? फिर भी अधिकारी वर्ग पर विदेशी शिक्षण का भूत सवार क्यों ? हम मानते हैं कि

उच्च शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण हुआ करती है लेकिन उस शिक्षा की प्राप्ति के लिए अपनी आत्मा को गिरवी रख देना अमानुषिक है। विदेशी शैक्षणिकों पर अधिक निर्भर रहने से राष्ट्रीय गौरव को ठेस लग सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में जब इण्डो-यू० एस० एजूकेशनल फ़ाऊंडेशन की योजना पेश की गई थी तो उस समम इस सुझाव का डटकर विरोध हुआ था क्योंकि यह योजना शिक्षा प्रणाली में सुधार या शिक्षा क्षेत्र में सर्वांगीण विकास के लिए नहीं बल्कि शिक्षा के माध्यम से लोगों के दिल और दिमाग पर काबू पाने के लिए बनाई गई थी।

खेद का विषय है कि जिन देशों की खुफ़िया कार्यवाहियों पर कड़ी नजर रखनी चाहिए उन्ही देशों में हमारे खुफ़िया विभाग के अधिकारी शिक्षण प्राप्त करने के लिए भेजे जाते हैं। जाहिर है कि भारत की कभी भी यह नीति नहीं रही है कि वह अन्य देशों मे खुफ़िया कार्यवाहियां करे परन्तु इस प्रकार की नीति पर अन्य देशों की नीति निर्धारित नहीं है इसलिए अन्य देश के खुफ़िया विभाग के कर्मचारी हमारे देश के खुफ़िया विभाग के 'गुरु' हों तो 'शिष्य' अपने 'गुरु' के विरुद्ध काम नहीं कर सकता। हमारे खुफ़िया विभाग के कर्मचारियो को सजग और जागरुक रहना चाहिए।

आश्चर्य की बात है कि जन-गणना का शिक्षण प्राप्त करने के लिए भी हमारे भारतीय कर्मचारियों को विदेश भेजा जा रहा है। भारत आबादी के आधार पर विश्व में दूसरे दर्जे पर है और इतनी बड़ी आबादी वाले देश के कर्मचारी उन देशों में शिक्षण के लिए भेजे जाए जहां की आबादी हमारे एक प्रदेश से भी कम हो, यह समझ में नहीं आता। भारत में गणित-शास्त्रियों की कमी नहीं है परन्तु फिर भी 'गणित विद्या' प्राप्त करने के लिए हम विदेशी शरण में जाएं यह विचित्र बात है।

हम सी० आई० ए० पर आरोप लगाते हैं :—

- कि सी० आई० ए० ने तहसील से लेकर लोक सभा स्तर तक पूरा रिकार्ड बना रखा है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जो राजनैतिक क्षेत्र मे भाग लेता हैं, के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर रखी है। इस प्रकार लगभग नौ लाख व्यक्तियों की सूची तैयार है। यह काम कई वर्षों से जारी है। आखिर किसलिए ?

इस योजना के अन्तर्गत कई लोग दिन रात काम करते हैं। सी० आई० ए० इन लोगों की सेवाओं से पूरा-पूरा लाभ उठाती है। 'अमेरिकन रिपोटर, जैसी पत्रिकाओं के नाम पर प्रति वर्ष 'पते की जानकारी' के बहाने जो फार्म भेजा जाता है उसके द्वारा यह प्रयत्न किया जाता है कि व्यक्ति विशेष के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। इस सूची के द्वारा यह पता लगाया जाता है कि अमुक व्यक्ति का सम्बन्ध किस राजनैतिक, सामाजिक या धार्मिक संस्था से है, उन्हे अमरीकी जीवन के किस भाग में दिलचस्पी है, वे कितनी बार अमरीकी रेडियो सुनते हैं और वे 'अमेरिकन रिपोर्टर' से क्या चाहते हैं। जाहिरा तौर पर यह प्रश्न मामूली ढंग के हैं परन्तु इन प्रश्नों के पीछे सी० आई० ए० का दिमाग काम करता है और वह इस सूचना के आधार पर अपना जाल फैलाते हैं।

- सी० आई० ए० भावी नेताओं के बारे में भी पूरी जानकारी प्राप्त करती है। अधिक ध्यान उन लोगों की ओर दिया जाता है जो विद्यार्थी या युवक आन्दोलन में काम करते हैं। वे सोचते हैं कि विद्यार्थी समुदाय को सुगमता से खरीदा जा सकता है। पिछले दिनों उन लोगों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने व उनके विचारों के बारे में जानने की कोशिश की गई जो १९९० में देश की बागडोर हाथ में ले सकते हैं। आखिर न तो यह ज्योतिष विद्या का कमाल है न किसी दैवी शक्ति का कि एक संस्था यह जान सके कि २० वर्ष बाद कौन स्थानीय स्तर पर और कौन राष्ट्रीय स्तर पर नेता होगा? लेकिन रिसर्च विभाग में यह काम जारी है। सी० आई० ए० वर्तमान के प्रति ही चिन्तित नहीं बल्कि भविष्य के बारे में भी चिन्तित है। उसको डर है कि साम्राज्यवाद का भविष्य खतरे से खाली नहीं। साम्राज्यवाद जिस नींव पर खड़ा है वह अधिक देर तक टिकने वाली नहीं। लड़खड़ाते हुए साम्राज्यवाद को सी० आई० ए० कितनी देर तक खड़ा रख सकता है?

सूचना इकत्रित करने के बहाने किसी भी व्यक्ति को या उसकी संस्था को यह अनुमति नहीं दी जा सकती कि वह षडयन्त्रकारी गतिविधियों को जारी रख सके। षडयन्त्र षडयन्त्र है उसे देशी करें या विदेशी, किसी भी षडयन्त्र-कारी को माफ नहीं किया जा सकता। षडयन्त्रकारियों के दाव-पेच से सावधान रहने की आवश्यकता है, उनके चेहरे का नकाब उतारना ही चाहिए।

● सी० आई० ए० पर यह भी गम्भीर आरोप है कि इसने विद्यार्थियों और युवकों को और उनकी संस्थाओं को पिछलग्गू बनाने का भी प्रयास शुरु कर रखा है। इसकी गतिविधियां यहां तक ही सीमित नही बल्कि मजदूरों, साहित्यकारों और सामाजिक कार्यकर्त्ताओ की संस्थाओं में भी बढ़ रही हैं। यह ठीक है कि 'काठ की हांडी दोबारा नही चढ सकती' परन्तु फिर भी सावधान रहना आवश्यक है ताकि इस कुकर्मी और कुमार्गी सी० आई० ए० को पनपने न दिया जाए।

गत कुछ वर्षों से एक नई योजना के अन्तर्गत युवको को फसाने के लिए 'युवक शिक्षण योजना' तैयार की गई है जिसके माध्यम से युवकों को फुसलाकर विदेश भेजा जाता है ताकि वे पश्चिमी सभ्यता के प्रशसक बनकर पश्चिमी राग-रंग में उलझ कर क्रान्तिकारी भावनाओं से विमुख हो जाएं। यह भी कोशिश की जाती है कि इन युवको के दिमाग में यह बिठा दिया जाए कि 'पश्चिमी ढंग का प्रजातन्त्रवाद' ही उचित है।

इस योजना के बारे में भारतीय संसद मे भी यदाकदा चर्चा की जा चुकी है। दिल्ली में भी इस योजना के प्रसार के लिए विचार गोष्ठियों का आयोजन किया जा चुका है।

● सी० आई० ए० ने सदैव फासिस्ट और साम्प्रदायिक मनोवृत्ति वाली सस्थाओ को आर्थिक सहायता की है, उनको प्रोत्साहन दिया है। इसके अतिरिक्त सरकार विरोधी कार्यवाहियों को भी बढावा दिया जाता है। धर्म के नाम पर होने वाले दंगो के पीछे भी इन्ही का हाथ है। यह संस्था विशेष तौर पर उन क्षेत्रों में क्रियाशील है जो औद्योगिक क्षेत्र हों। औद्योगिक क्षेत्रों में हड़तालें कराना या दंगे कराना ही इनका काम है। कारण यह है कि यदि भारत आर्थिक तौर पर शक्तिशाली हो जाए तो पूंजीवादियों की दाल नही गल सकती। मजदूर वर्ग के लोगो में फूट डालने की तह में साम्राज्यवादी भावना काम करती है।

● सी० आई० ए० समाचार पत्रों और स्थानीय पत्रिकाओं को भी आर्थिक सहायता देती है ताकि इस प्रकार के प्रचार को बढावा दिया जा सके जिससे समाजवाद के बढ़ते हुए चरण रुक जाएं। सी० आई० ए० जनता की शत्रु है और इसी कारण समाजवाद का भी विरोध करती है। सी० आई० ए०

की यह कोशिश रही है कि समाचार पत्रों की नीति पर डालर का प्रभाव कायम रहे। लोग समाचार पत्र पढ़ें और अपने विचारों पर इसका प्रभुत्व कायम होने दें भले ही सम्पादक की लेखनी न बिक सकती हो परन्तु समाचार पत्र का मालिक, जो नीति निर्धारित करता है वह तो खरीदा जा सकता है।

हमारे देश के समाचार पत्रों ने काफी महत्वपूर्ण कार्य किया है। नई चेतना लाने में योगदान भी दिया है लेकिन कुछ वर्षों से कुछ समाचार पत्रों की नीति में परिवर्तन हुआ है। दुःख की बात है कि हमारे देश मे कुछ ऐसे व्यक्ति विद्यमान हैं जिनकी लेखनी राष्ट्र हित के बारे में तो कम लिखती है, अमरीकी विचारो का अधिक प्रतिपादन करती है। यह हर्ष का विषय है कि काफ़ी हद तक लेखको और सम्पादकों ने राष्ट्रीय मान मर्यादा को ठेस नही लगने दी है।

यह भी देखा गया है कि व्यापार सम्बन्धी बड़े-बड़े कारखानो और मिलो मे लोगों के विचारों को नया मोड देने के लिए पत्र-पत्रिकाओ द्वारा कोशिश जारी है। यह पत्र-पत्रिकाएं कार्यकर्त्ताओं में निःशुल्क बांटी जाती हैं।

सवाल रबात का हो या प्रिवीपर्स का, चुनाव केरल का हो या उत्तर प्रदेश का—इन लोगों का एक ही काम है कि लोगों में यह भावना भर दी जाए कि देश उत्पात की ओर बढ़ रहा है, निराशा चर्म सीमा पर पहुँच चुकी है, प्रजातन्त्र प्रणाली खत्म होने वाली है।

● सी० आई० ए० ने कई ऐसी संस्थाओं को भी जन्म दिया है जिनका उद्देश्य साम्राज्यवादी शक्तियों का पिछलग्गू बनकर यह ज़ाहिर करना है कि जन-साधारण की तथा कथित सहानुभूति साम्राज्यवादियो के साथ है ऐसी ही एक सस्था भारत में काम कर रही है जिसका नाम 'फ्रेंडज आफ़ ईस्राईल' है इसके अतिरिक्त एक अन्य संस्था 'सोसायटी फार कलचरल फ्रीडम' है जिसका सम्बन्ध न तो आज़ादी से है और न ही कलचर से। इनका मुख्य उद्देश्य है कि इने-गिने व्यक्तियों को या तो फार्मूसा भेजना या इस्राईल भेजना ताकि ये व्यक्ति वापिस भारत आकर फार्मूसा और इस्राईल सरकारों की नीतियों के प्रति उचित वातावरण पैदा कर सकें। अभी कुछ दिनों से तो दिल्ली नगर की दीवारों पर दो बड़े-बड़े चित्रों वाला इश्तहार भी देखने

को मिलेगा। जिसमें महात्मा गांधी के साथ-साथ च्यांग-काई शेक के चित्र हैं। महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्ति को च्यांग-काई-शेक के स्तर पर लाना देश द्रोह है। दक्षिण कोरिया दिवस के उपलक्ष मे भी इस प्रकार की प्रचार सामग्री जारी की गई थी। इस्राईल के पक्ष में भी इस प्रकार के इश्तहार लगाए गए थे। इस प्रचार द्वारा विदेश में यह प्रकट करने का प्रयास किया जाता है कि दक्षिण कोरिया, दक्षिण वियतनाम और फार्मूसा की सरकार को भारतीय जनता का 'समर्थन प्राप्त है परन्तु वास्तविकता कुछ और है। लोग जानते हैं कि विदेशी धन के आधार पर भारत की क्रान्तिकारी परम्पराओं को तिरस्कृत नही किया जा सकता। भारत के लोग लाल चीन की विस्तारवादी नीति के उतने ही विरोधी हैं जितने वे साम्राज्यवादी कैम्प में पलने वाले च्याग-काई-शेक सरकार के।

- सी० आई० ए० ने अपने कंधो पर कुछ तथा कथित संस्थाओं के कार्यालयों को चलाने का भार भी सम्भाल रखा है। शानदार भवनो में इन संस्थाओ के कार्यालय स्थित हैं, उनको देखकर कोई भी यह अन्दाजा नहीं लगा सकता कि यह किसी भारतीय संस्था का कार्यालय होगा। उनकी प्रचार सामग्री को देखकर यह अनुमान लगाना कठिन है कि ये सामग्री और उस पर किए जाने वाला व्यय किसी गैर-सरकारी संस्था का हो सकता है।

- सी० आई० ए० ने भारत में तथा अन्य स्थानो पर भी प्रेस कौंसिल बना रखी हैं या फिर उनकी सहायता की जिम्मेदारी ले रखी है जो निरन्तर प्रचार सामग्री भेज कर यह कोशिश करती है कि भारतीय जनता को साम्राज्यवादी शक्तियों के वास्तविक रूप से अनभिज्ञ रखा जा सके। इनकी प्रचार सामग्री से जनता-विरोधी भावनाओं की झलक आती है।

- सी० आई० ए० भारत सरकार की प्रगतिशील नीतियों का विरोध करने के लिए इने-गिने व्यक्तियों को इस्तेमाल करती है। चाहे बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न हो या प्रिवीपर्स को समाप्त करने का, सी० आई० ए० के इशारे पर इनका विरोध किया जाता है।

- सी० आई० ए० ने रबात के प्रश्न पर जो हुडदंग मचाया वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। बी० बी० सी० ने जिस ढंग से भारत को बदनाम करने की कोशिश की वह सोची समझी साजिश का छोटा सा रूप था। लेकिन

आश्चर्य की बात है कि रबात के प्रश्न को लेकर बी० बी० सी० ने जी भर कर टीका टिप्पणी की—पक्षपाती के रूप में। यहां तक ही बस नहीं, भारत की प्रतिक्रियावादी संस्थाओं ने भी उसी राग में गाना शुरु कर दिया। इन सब का उद्देश्य एक था कि भारत सरकार को बदनाम किया जाए और हिन्दुओं को उत्तेजित किया जाए। यह अलग बात है कि उन्हें सफलता न मिली और लोग जान गए कि साम्राज्यवादी एक ओर तो पान-इस्लामिज़म को बढावा देते हैं तो दूसरी ओर हिन्दुओं को भी भड़काते है ताकि दोनों लड़ पड़ें और साम्राज्यवाद सुरक्षित रह सके।

सी० आई० ए० का आर्थिक दृष्टिकोण :

सी० आई० ए० एक विशेष आर्थिक दृष्टिकोण को बढावा देती है ताकि स्वतन्त्र देशों को पुनः आर्थिक बन्धनों मे जकड़ उनकी आजादी को छीना जा सके। साम्राज्यशाही पिटने के बाद एक बार फिर वापिस लौटने का प्रयत्न करती है, सीधे दरवाज़े से नहीं बल्कि चोर दरवाज़े से। यह ढंग सम्भवतः अब पुराना हो गया है और अब यही साम्राज्यशाही आर्थिक दरवाज़े से घुसने का प्रयास करती है और आर्थिक सहायता के बहाने घुस पैंठ करके इस बात की आशा करती है कि इस सहायता के उपलक्ष में उसे कुछ सुविधाएं प्राप्त हो जाएं। आर्थिक घुसपैठ अधिक भयंकर और विकराल रूप धारण कर सकती है विशेषतया उस समय जब किसी देश में आर्थिक समस्या भीषण रूप धारण कर चुकी हो क्योंकि आर्थिक सहायता के साथ-साथ ऐसी जंजीरें बन्धी रहती हैं कि इन बन्धनो से छुटकारा पाना ठिन हो जाता है।

'पैसा सब कुछ कर सकता है' इस सिद्धान्त के आधार पर व्यक्तियों की तथा उनकी संस्थाओं की भी सहायता की जाती है। पर्याप्त मात्रा मे धन उपलब्ध रहता है और चूंकि खुफ़िया काम करने के लिए स्थानीय मुद्रा का ही प्रयोग हो सकता है इसलिए यह जानना कठिन होता है कि कितना धन, किसको, कब दिया गया। किन्तु कुछ संस्थाओं की ओर से इस नीति का समर्थन नि.सन्देह अवांछनीय है। जो संस्था इस बात की चर्चा नहीं करती कि इस संस्था को मिलने वाला धन कहां से आया, निश्चय ही इस गोलमाल में हिस्सेदार है। जिस प्रकार अमरीका की नेशनल स्टुडेन्ट्स एसोसियेशन के पदाधिकारियो ने यह राज खोल दिया कि उनकी संस्था को सी० आई० ए० से आर्थिक सहायता मिलती रही, इन संस्थाओं के बारे में, जिनके धन

के स्रोत का पता नहीं, जब भेद खुलेगा तो इन संस्थाओं को आटे-दाल का भाव विदित हो जाएगा।

१९५१ में वर्ल्ड असेम्बली आफ़ यूथ की इथाका में हुई बैठक में इस संस्था से सम्बन्ध रखने वाली राष्ट्रीय समितियों से चन्दा लेने की दृष्टि से छः भागों में विभक्त किया गया। निम्नलिखित सूची से पता लग सकेगा कि किस उद्देश्य से यह योजना बनाई गई थी :

ए	१,००० फ्रांक	
बी	५,००० फ्रांक	भारत, पाकिस्तान और आस्ट्रिया
सी	१०,००० फ्रांक	वियतनाम, डेन्मार्क और टोगो
डी	२०,००० फ्रांक	केनेडा, नीदरलैण्ड
इ	५०,००० फ्रांक	ईटली, स्वीडन, टर्की
एफ	१००,००० फ्रांक	ब्रिटेन, अमरीका, फ्रांस, बेल्जियम

यह सूची उन देशों की है जिन्हें ऊपरलिखित राशि वर्ल्ड असेम्बली आफ यूथ को नियमित रूप से देनी पड़ती है। परन्तु इस सूचि को ऊपर से नहीं नीचे से पढ़िए। आपको कुछ आश्चर्यजनक बातें दिखाई देंगी। जहां ब्रिटेन, अमरीका और फ्रांस धनराशि प्रदान करने वालों में चोटी पर हैं, छोटा सा देश बेल्जियम भी इन देशों के साथ भारी धनराशि देने वालों की सूची में आता है। क्या इस छोटे से देश का युवक आन्दोलन इतना शक्तिशाली है कि इस धनराशि को देने की क्षमता रखता है? इसके अतिरिक्त टर्की का दर्जा दूसरे नम्बर पर आता है जिसे ५०,००० फ्रांक देने पड़ते हैं जबकि केनेडा और नीदर लैण्ड जो गरीब देश नहीं हैं छोटे दर्जे में शामिल किए गए हैं। लंगड़ा वियतनाम, अज्ञात टोगो डेन्मार्क के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर खड़े हैं और गौरवशाली आस्ट्रिया को भारत और पाकिस्तान के साथ जोड़ा गया है।

इस सूची में जिन देशों का नाम लिखा गया है वास्तव में उनसे कोई चन्दा वसूल नहीं किया जाता। धनराशि तो अन्य स्रोतों से मिलती है। सूची तो केवल दिखावा मात्र है वरना कहां टोगो और कहां अमरीका? कागजों में नाम दक्षिण वियतनाम का लिखा जाता है, पैसा अमरीका देता है और बड़ी शान के साथ कोषाध्यक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहता है कि इन राष्ट्रों से पर्याप्त सहायता मिलती रही है और दूसरे ही क्षण में इस बात को स्वीकार कर लेता है कि राष्ट्रीय

समितियां अपना चन्दा अदा नहीं करतीं। एक ही जुबान से दो प्रतिकूल बात। वाह रे अन्तर्राष्ट्रीय संस्था तेरा, कमाल !

यह तो स्पष्ट है कि उच्चकोटि के दान वीरों में चार ही देशों का नाम लिखा गया है और उन्ही से पैसा वसूल किया जाता है, वही संस्था के व्यय को पूरा करते हैं और इन्ही चार देशों को अर्थात अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस और बेल्जियम को यह अधिकार प्राप्त है कि वे अधिक धन देने के उपलक्ष में वर्ल्ड असेम्बली आफ यूथ की नीति भी निर्धारित करें। इस बात से इन्कार नही किया जा सकता कि ऊपरलिखित सूची राजनैतिक दृष्टिकोण से तैयार की गई है क्योंकि 'जैसा होगा धन, वैसा होगा मन।"

वर्ल्ड असेम्बली आफ़ यूथ के यात्रा कोष की ६० प्रतिशत धनराशि फाऊंडेशन फार यूथ एण्ड स्टुडेन्ट अफेयरज अदा करती है जिसको मिलने वाली धनराशि के स्रोतों के बारे मे पीछे चर्चा की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त सामाजिक, साहित्यिक और शैक्षणिक सस्थाओ को अधिकाश धनराशि एशिया फ़ाऊंडेशन से प्राप्त होती है। यही सस्था विशालकाय भवनो का निर्माण करने के लिए पर्याप्त धनराशि भी देती है। इस प्रकार मिली हुई धन राशि से बने हुए विशालकाय भवन षडयन्त्रकारी गतिविधियो का केन्द्र बन जाते हैं।

अधिकांश सस्थान बेनामी हैं और सी० आई० ए० इन संस्थानों को अपनी कार्यवाहियो को बढ़ावा देने के लिए प्रयोग मे लाती है। इन सस्थानों के माध्यम से अन्य संस्थाओ के साथ सम्पर्क बढाने का कार्य किया जाता है सी० आई० ए० के कार्यालय का काम विभिन्न विभागों मे विभक्त है प्रत्येक विभाग का मुखिया अपने विभाग की देख रेख करता है। एशियाई विभाग और अफ्रीकी विभाग विशेष ध्यान के पात्र हैं क्योंकि अफ्रीकी एशियाई देशों मे साम्राज्यवाद की जड़ें खोखली हो चुकी है और इन देशों के लोग अपने राष्ट्रीय गौरव और स्वाभिमान की रक्षा के लिए तत्पर हैं।

१९५९ तक दक्षिण-पूर्व-एशियाई कार्यालय नई दिल्ली मे स्थित था और एक बंगाली सज्जन इस कार्यालय के प्रमुख थे। इन्होने यह जाहिर करने की कोशिश की कि वह तो केवल एक व्यापारी है परन्तु वास्तव मे यही व्यक्ति 'साम्यवाद का विरोध' करने के लिए 'बड़े व्यापार' को कई वर्षों तक चलाता रहा। उसकी देख रेख मे खुफ़िया काम करने वालों का जाल बिछाया गया। उनके रहन-सहन, खान-

पान ग्रौर शान व शौकत को देखकर कोई भी व्यक्ति भूले से भी यह शक नहीं कर सकता था कि यही महोदय व्यापारी नहीं बल्कि 'बड़े व्यापारी' के दलाल के रूप में लोगो के स्वाभिमान का सौदा किया करते थे। यह ग्रलग बात है कि उन्हें सफलता न मिली परन्तु उसकी कार्यवाहिया निन्दनीय थीं।

ग्राज सी० ग्राई० ए० की गतिविधियों में कोई ग्रामूल परिवर्तन नही है। वही है चाल बेढगी, जो पहले थी वह ग्रब भी है। ग्रन्तर केवल यह है कि ग्रब लोग सी० ग्राई० ए० की गतिविधियो से परिचित हो चुके हैं। सी० ग्राई० ए० पहले की भांति ग्रब भी उन देशो की खोज में रहती है जहां गड़बड़ मचाई जा सके ग्रौर जहां सी० ग्राई० ए० को थोडी सी भी सहायता प्राप्त हो सकती हो। जहां-जहां पिछलग्गू सरकारें कायम हैं वहां सी० ग्राई० ए० को ग्रपनी कमीनी चालो में थोडी सी सफलता ग्रवश्य प्राप्त होती है परन्तु ग्रधिकाश देशो में लोगों के बढ़ते साहसिक कदमों के ग्रागे सी० ग्राई० ए० की चालें नाकाम रही हैं। गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के विरुद्ध रेडियो एव समाचार पत्रों द्वारा भूठा प्रचार किया जाता है, विभिन्न राजनैतिक दलों के माध्यम से गुट निरपेक्ष राष्ट्रों की सरकारों पर दबाव डाला जाता है कि वे एंग्लो-ग्रमरीकन गुट में शामिल हो जाएं। वह यह भी भूठा प्रचार करते है कि यदि भारत एग्लो-ग्रमरीकन गुट में शामिल हो गया होता तो चीन भारत पर ग्राक्रमण नही कर सकता था। सदा इस बात का प्रयास किया जाता है कि प्रजातंत्र प्रणाली में विश्वास रखने वाले देशो की शक्ति को क्षीण किया जा सके। हर प्रकार की हरकतें की जाती हैं ताकि षडयन्त्रकारी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके। सी० ग्राई० ए० सरकार के ग्रन्तर्गत एक ग्रन्य सरकार है जो ग्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के बारे मे निर्णय करती है कि किस देश के ग्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध किसके साथ कैसे हों? इस प्रकार ग्रान्तरिक मामलों मे भी हस्तक्षेप किया जाता है ग्रौर उल्ट फेर की भूमिका ग्रदा की जाती है।

१३ मई १९६९ को केन्द्रीय गृह मन्त्री ने भारतीय लोक सभा में कहा था कि भारत सरकार कानून द्वारा इस बात पर रोक लगाना चाहती है कि भारत में किसी भी संस्था को विदेशी संस्थाग्रों से ग्रार्थिक सहायता न मिल सके। गृह मन्त्री विदेशी संस्थाग्रों द्वारा भारतीय संस्थाग्रों को मिल रही ग्रार्थिक सहायता के बारे में चर्चा कर रहे थे। सभा में इस बात की माग की गई थी कि खुफिया विभाग की १९६७ ग्रौर १९६८ की रिपोर्ट में क्या लिखा गया है। गृह मन्त्री ने बताया कि किन कारणों से खुफिया विभाग द्वारा की गई जांच पड़ताल को ग्राम जनता के

सन्मुख नही रखा जा रहा। आपने बताया कि खुफिया विभाग किन्ही कारणों से खुनी जांच न कर सका है और न ही गवाहियां इत्यादि ली गई हैं परन्तु इस विभाग की जांच का आधार वे सूचनाएं हैं जो उन्हें प्राप्त हुईं थी।

केन्द्रीय गृह मन्त्री ने कहा कि व्यक्तियों या उनकी संस्थाओं को विदेशों से मिलने वाली आर्थिक सहायता का विषय चिन्ताजनक है। ये संस्थाए चाहे राजनैतिक क्षेत्र में *कार्य करती हों या साहित्यक क्षेत्र मे। यद्यपि निश्चित रूप में यह जानकारी* प्राप्त न हो सकी है कि इस प्रकार किस संस्था को कितनी आर्थिक सहायता प्राप्त हुई परन्तु ऐसा लगता है कि इस प्रकार दी जाने वाली सहायता न तो अधिक मात्रा मे थी और न ही इतनी कम कि इसकी ओर ध्यान न दिया जाए। इसके अतिरिक्त इस सम्बन्ध में भी जानकारी प्राप्त हुई है कि गत आम चुनाव में विदेशी धन का प्रयोग किया गया था। चुनाव के समय विदेशी धन पानी की तरह बहाया जाता रहा है और इस बात की कोशिश की जाती रही है कि प्रगतिशील विचार रखने वाले लोगों को हराने के लिए विपक्षी दलों की पूरे तौर पर सहायता की जाए। पिछले आम चुनाव मे तो सी० आई० ए० ने ही निर्णय लिया था कि किस प्रगतिशील व्यक्ति का विरोध कौन करेगा और इस प्रकार उसने एड़ी चोटी का ज़ोर लगाया कि इने-गिने नेताओं के विरुद्ध प्रतिक्रियावादी शक्तियों का मोर्चा लगाया जाए। अमरीकी साम्राज्यवादियो ने हमेशा कृष्णा मेनन का विरोध किया है। हारे हुए जुआरी की भांति साम्राज्यवादी हमेशा इस ताक में रहे हैं कि कोई न कोई मौका हाथ में ज़रूर लगे जिससे प्रगतिशील नीतियो को उखाड़ फेंका जा सके।

केन्द्रीय गृह मन्त्री ने यह भी बताया कि विदेशी समाचार पत्रों से प्राप्त सूचना के आधार पर तथा भारतीय खुफ़िया विभाग की सूचना के अनुसार ऐसा विदित होता है कि सी० आई० ए० की हिदायत पर कुछ संस्थाओं को 'शोध' के लिए तथा 'शिक्षा के विस्तार' के लिए आर्थिक सहायता मिलती रही है। हो सकता है कि इन संस्थाओं को इस बात का ज्ञान न हो कि इस प्रकार मिलने वाली आर्थिक सहायता या छात्र वृत्ति या यात्रा व्यय के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता न तो शोध कार्य के लिए है और न ही शिक्षा के विस्तार के लिए अपितु इस देश में इन कार्यवाहियों के माध्यम से अमरीकी गुप्तचर संस्था की गतिविधियों को बढ़ावा देना है।

इसी कारण भारत सरकार ने एशिया फ़ाऊंडेशन को आदेश दिया है कि वह भारत से अपना ताम-तोबड़ा उठा कर ले जाए। सरकार ने यह आश्वासन भी

संसद में दिया है कि यदि इस प्रकार की गतिविधियों में संलग्न कोई अन्य संस्था भारत में दिखाई दी तो उसे भी अपना काम-धाम बन्द करना पड़ेगा। गृह मन्त्री ने संसद में चर्चा करते हुए कहा कि संसद सदस्यों को इस समस्या पर विचार करना चाहिए ताकि भारत की धरती पर षडयन्त्रकारी गतिविधियां पनप न सकें। आपने कहा कि अपरोक्ष रूप में मिलने वाली राशि, पुस्तकों पर कमीशन के रूप में, या व्यापारिक सौदों से आर्थिक दलाली के रूप में, या विज्ञापन दरों को बढ़ाकर या अनुवाद कार्य के लिए भारी रकम द्वारा दी जाती है। इस प्रकार मिलने वाले धन पर न तो किसी को शक हो सकता है और न ही एतराज परन्तु इस प्रकार इन संस्थाओं को या व्यक्तियों को काफ़ी धनराशि सहज में ही प्रदान की जाती है।

यह भी देखने में आया है कि इन व्यक्तियों के नाम पर विदेशों में अवैध तरीकों से धन भी भेजा जाता है और इस काम में विदेशी बैंकों, विदेशी कम्पनियों और विदेशी लोगों की सहायता ली जाती है। कुछ व्यक्ति तो ऐसे भी हैं कि जिनका काम सिवाए सौदे बाज़ी के और कुछ नहीं है। उनका काम तो दलाली करना है, कभी वे राजाओं के दलाल बन जाएंगे तो कभी राजवाड़ा शाही के। कभी बैंको के राष्ट्रीयकरण का विरोध करके बैंकरों की चापलूसी करेंगे तो कभी काला धन कमाने वालों के एजेंट बन जाएगे। इन लोगों का दीन-ईमान पैसा है। वह तो ऐसे लोग हैं जिन्हें 'चाम भी प्यारा है और दाम भी'। अगर किसी मनुष्य का चाम बेच सकते हों तो सहर्ष बेच देंगे। देश की मान मर्यादा का सौदा करना हो तो वह भी करने को तैयार रहेंगे। ऐसे लोग समाज के लिए हानिकर होते हैं, वे कभी भी देश-द्रोह कर सकते हैं। मानवता उन्हे छू भी नही सकती, उनके लिए सब मर्यादाएं कुण्ठित हो चुकी हैं।

इस प्रकार की स्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि ऐसे समाज-विरोधी तत्वों से सावधान रहा जाए ताकि ये लोग हमारे देश को घुन की तरह खा न जाए। कुछ लोग भले ही गोरी चमड़ी देखकर उन लोगों के विरुद्ध आवाज न उठाएं परन्तु जिस व्यक्ति में थोडा सा भी स्वाभिमान है वह अवश्य ही इन देश द्रोहियों का विरोध करेगा। खेद का विषय है कि जब हमारे देश में हमारे भाई ही विदेशी सत्ता या धन्ना सेठों के हाथ में बिक जाएं, तो शायद कुछ लोग निराशा अनुभव करने लगते हैं। परन्तु उन्हें विदित होना चाहिए कि कुछ इने-गिने लोग अपनी गल्त कार्यवाहियों से थोड़े समय के लिए हानि तो पहुँचा सकते हैं। परन्तु ऐसे लोग अधिक देर टिक नही सकते। यही कारण है कि जिन-जिन स्थानों पर सी० आई०

ए० ने लोगों को या उनकी संस्थाओं को खरीदना चाहा वहां प्रारम्भ-में तो उन्हे अवश्य सफलता मिली परन्तु जनता ने जब करवट ली तो इन सस्थाओं का अस्तित्व मिट गया। लोगों ने जन-भावनाओं का विरोध करने वाले व्यक्तियों को इस प्रकार अलग कर दिया मानो दूध और पानी अलग-अलग कर दिया गया है। जनता से अलग-अलग रहने वाले चेहरे भी ज़रा देखें कि वे किस रंग में और कहा रहते हैं ?

नया रूप, पुरानी चालें

दुनिया के लोग बड़ी तेजी के साथ छलांगे मारते हुए प्रगति के पथ पर बढ रहे हैं। उनकी भावनाओं और आकांक्षाओं को नई दिशा प्रदान की जा चुकी है। संसार का मानचित्र जो दस वर्ष पहले था वह अब वैसा नहीं है। नए राष्ट्रों का जन्म हुआ है, उन्होने आज़ादी की सांस ली है। सदियों तक गुलामी की बेड़ियों में जकड़े रहने के बाद कई राष्ट्रों ने फिर अंगड़ाई ली है। साम्राज्यवादियों ने दमन की नीति अपनाई, राष्ट्रवादियों ने उसे भी सहन किया। अपने जीवन की आहुति देने वालों ने फांसी के फन्दे को चूमा परन्तु उफ न की, गोलियों से शरीर छलनी हो गया लेकिन आह न निकली, और जेल की काल कोठरियों में तिल-तिल कर बलिदान देने वालों ने अदम्य उत्साह का परिचय दिया। बार-बार उनके मुख से यह आवाज़ निकली 'तुम तीर आजमाओ हम जिगर आजमाएं'। परिणाम यह निकला कि जनता की अपार शक्ति के आगे साम्राज्यवादी टिक न सके। एक-एक करके राष्ट्र आज़ाद होते गए। विश्व के इतिहास की रूप रेखा बदल दी गई। नया इतिहास लिखा जाने लगा। प्रजातान्त्रिक देशों में एक नए युग का प्रादुर्भाव हुआ।

साम्राज्यवादी तिलमिलाने लगे। उनकी नींवें शिथिल हो गईं। परिवर्तन अवश्य भावी है, उसे कोई नहीं रोक सकता, न धन में इतनी शक्ति है न हथियारों में कि बढ़ते हुए कदमों को रोक सकें। इस समय दुनिया में ४४ देश ऐसे हैं जो अभी तक साम्राज्यवादी चंगुल से मुक्ति प्राप्त न कर सकें हैं। कुल मिला कर लगभग २८ करोड़ लोग दुनिया में गुलामी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इनमें से काफी देश ऐसे हैं जो गोराशाही के शिकार हैं जहां पर काली चमड़ी वाले लोगों के साथ बर्बरता पूर्ण व्यवहार किया जाता है। इन देशों में न जनता के साथ समान व्यव-

हार किया जाता है न उन्हें किसी प्रकार की नागरिक सुविधाएं प्राप्त हैं। इन देशों मे प्रमुख हैं दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी रोडेशिया, जाम्बिया (दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका) पुर्तगाली तानाशाही के आधीन अंगोला, मुजाम्बिक, गिनी इत्यादि। इन देशो में काली नस्ल वालों के साथ अमानुषिक व्यवहार किया जाता है। इन देशों के अतिरिक्त ३६ देश ऐसे भी हैं जहां उन लोगो को अभी तक गुलामी का दौर देखना पड़ रहा है। यद्यपि सयुक्त राष्ट्र सघ ने उपनिवेशवाद को समाप्त करने की बराबर मांग की है परन्तु उन वर्तमान शासकों के कान पर जूं तक नही रेंगी है। साम्राज्यवादी शासकों में न केवल पुर्तगाल बल्कि आस्ट्रेलिया, फ्रास, ब्रिटेन, स्पेन और अमरीका भी शामिल हैं।

इस प्रकार अन्य देशों को गुलाम रखने की नीति के पीछे साम्राज्यवादियो की एक गहरी चाल है। वे चाहते है कि इन देशो के खनिज पदार्थों का शोषण किया जाए और वह धरती जो सोना उगलती है उसे वीरान कर दिया जाए या फिर इस प्रकार उत्पन्न होने वाली कीमती धातुओ को कोडी के मूल्य खरीद कर उस देश को भिखारी बना दिया जाए। आर्थिक गुलामी के बन्धनो में इन देशो को जकडने के पश्चात उन्हे राजनैतिक व सामाजिक तौर पर अपाहिज बनाने का निरन्तर प्रयास किया जाता है।

कागो में भी इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न को गई थी। कागो पश्चिमी तट से पूर्व तक और भूमध्य रेखा से रोडेशिया तक फैला हुआ एक ऐसा देश है जिसकी अपनी विशिष्ट स्थिति के कारण इसे अफ्रीका मे एक महत्व पूर्ण स्थान प्राप्त है। इस देश से अफ्रीका की राजनैतिक स्थिति पर भी प्रभाव डालना सम्भव है। इस देश के प्राकृतिक साधन किसी देश से कम नही हैं। तेल-खजूर और रबड़ के वृक्ष पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इस देश मे हीरे भी मिलते हैं और सोना भी। १९५९ में दुनिया में हीरो की पैदावार का ६९% भाग कांगो में हुआ था। केवल खनिज पदार्थों के निर्यात से १०० लाख पौंड की आमदन हुई थी। १९५८ तक कागो के लोगों को बेल्जियम सरकार ने अपने अंकुश के नीचे दबाए रखा। कारणवश जनता राजनैतिक विचार-प्रवाह से अलग रही परन्तु जब राष्ट्रवादी नेता पेट्रिक लुमुम्बा ने आल-अफ्रीकन पीपुल्ज कान्फ्रेंस जो आकरा में हुई के अन्दर अपने उद्‌गारों को व्यक्त करते हुए जब साम्राज्यवादियों को चेतावनी दी कि कांगो को अधिक देर गुलाम नहीं रखा जा सकता तो साम्राज्यवादी कैम्प मे खलबली मच गई। परन्तु विजय राष्ट्रवादियो की हुई। ३० जून '६० को राष्ट्रीय सरकार बनी पेट्रिक लुमुम्बा

उसके प्रधान मन्त्री बने और कासावूबू राष्ट्रपति। ११ जुलाई १९६० को काटंगा ने कांगो से अलग होने का एलान कर दिया। इस एलान के पीछे बेल्जियम सरकार का हाथ था क्योंकि वह लुमुम्बा से नाराज थी और उसे कांगो की आज़ादी एक आंख भी न भाती थी। जब देश में अलगाव पसन्दी शक्तियां उठ खड़ी हुईं तो उस समय लुमुम्बा ने सोवियत रूस से सहायता ली। बस क्या था साम्राज्यवादियों ने बौखला कर कासावूबू को इस बात पर राजी कर लिया कि वह लुमुम्बा को प्रधान मन्त्री पद से हटा दे। लुमुम्बा ने इसका विरोध किया और जब वह लियोपोल्डविला से स्टानलेविला जा रहे थे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आजादी का अमर सेनानी जेल की थान कोठड़ी में बन्द रखा गया और कुछ दिनो पश्चात लुमुम्बा की निर्मम हत्या कर दी गई। यह हत्या मानवता के माथे पर सदा के लिए कलुषित दाग बन गई। लुमुम्बा की हत्या के पीछे सी० आई० ए० का षडयन्त्र था। इसकी तह में डलेस की नीति काम कर रही थी। लुमुम्बा चले गए, उनकी आत्मा अब भी कांगो में निवास करती है। वह आज भी राष्ट्रवादियों को प्रेरणा देती है कि साम्राज्यवादी हथकण्डों से सावधान रहो। साम्राज्यवादी पिशाच हैं, मानवता के शत्रु हैं और उपनिवेशवाद के समर्थक।

सी० आई० ए० की गतिविधियों पर प्रकाश डालते समय हमारे सामने यह प्रश्न था कि 'अन्धे को अन्धा कहना' चाहिये या नहीं। क्योंकि निश्चय ही उन लोगों की आंखों में 'सी० आई० ए० का पर्दाफ़ाश करना' अखरेगा जिनको डर है कि सजग और जागरुक जनता कहीं उनके षडयंत्रकारी धन्धे पर लात न मार दे। यह भी ठीक है कि सैंकड़ों साम्राज्यवादी दलालों का काम ठप्प हो जाएगा, साम्राज्यवादी की जड़ें खोखली हो जाएंगी परन्तु यह भी सही है कि लाखों इन्सानों को शोषण से मुक्ति मिलेगी क्योंकि सी० आई० ए० शोषक टोले का साथ देता है।

अभी कुछ दिन हुए जार्डन में फलस्तीनी कमाण्डो और शाह हुसैन की सेनाओं के बीच भयंकर मुठभेड़ हुई। एक ओर साम्राज्यवाद-विरोधी शक्तियां खड़ी थी तो दूसरी ओर लड़खड़ाते हुए साम्राज्यवाद को सहारा देने वाली शक्तियां। एक को जनता का समर्थन प्राप्त था तो दूसरे को शाही दरबार का, लेकिन यह भी प्रमाणित हो गया कि अरब देशों में जन-जन की भावनाओं की अवहेलना करके साम्राज्यशाही संगीन की नोको से अपना राज्य कायम नही रख सकती। अरब देशों मे देशभक्ति की भावनाओं के सामने एक या दो राष्ट्र दीवार बनकर खड़े नही हो सकते। यदि जार्डन के शाह हुसैन यह समझते हों कि विदेशी गोला-बारूद और

हवाई जहाजों से अरब देशों में अरब-राष्ट्रीयता-विरोधी नीति अपना कर वह अपना दमन-चक्र जारी रख सकते हैं तो यह उनकी भूल है। अमरीकी साम्राज्यवाद का ताना-बाना अफ्रीका के कुछ देशों में भी मिलेगा और एशिया के कुछ भागों मे भी। जहां जहां शोषण की गुंजायश हो सकती है—साम्राज्यवाद के लिए पाव जमाना सरल हो जाता है। अरब देशों पर साम्राज्यवादियों की कोप दृष्टि इसलिए भी रही है कि नए आर्थिक दृष्टिकोण के अन्तर्गत मरुस्थल उर्वरा धरती में बदला जा चुका है। जिस रेगिस्तान में लोग पानी को तरसते थे वहां नई-नई योजनाओं से पानी की कमी को दूर किया जा चुका है। रेतीली धरती का कण-कण सुनहला रूप धारण कर चुका है। अरब देश मिलकर यदि अमरीका जैसे साम्राज्यवादी देशों को तेल देना बन्द करदें तो वाशिंगटन की मिलें बन्द हो सकती हैं, कारखानों मे चिमनियो की रौनक खत्म हो सकती है, विमान उड नही सकते, लगभग आधा कारोबार ठप्प हो सकता है। यही कारण है कि अरब देशों में साम्राज्यवादी हथकण्डे अपनाए जाते हैं ताकि तेल का शोषण होता रहे और अरब देशों की आर्थिक व्यवस्था आत्म-निर्भर न हो सके।

साम्राज्यवादियों को न यहूदियों से सहानुभूति है न ईसाइयो से, न इसे हिन्दू से प्यार है न मुसलमान से। मुसलमान की मस्जिद वीरान हो जाए या हिन्दू का मन्दिर गिर जाए तो साम्राज्यवादियो की आंख से आसू नही टपकेंगे परन्तु उनकी बाहे खुल जाएगी कि अब हिन्दू को मुसलमान से लड़ाना आसान हो जाएगा। यदि अमरीका, ब्रिटेन या फ्रास को हिटलर के जुल्म से तग आने वाले यहूदियो के साथ हमदर्दी थी तो उन्होंने अमरीका, ब्रिटेन या फ्रांस में ही यहूदियों के लिए अलग 'होमलैण्ड' क्यो न बना दिया। किसी भी शरणार्थी को दूसरे के घर मे बसाने का उपदेश तो हर कोई दे सकता है परन्तु मजा तो तब है जब उसे अपने घर मे स्थान दे। यदि यहूदियों का पुनर्निवास अमरीका में हो गया होता और फिर इन्हीं यहूदियों ने अमरीकियों को निकालकर स्वयं उस भाग पर अधिकार कर लिया होता तो अमरीका को आटे-दाल का भाव मालूम हो जाता। अगर निक्सन के परिवार के किसी भी व्यक्ति को उसके घर से उखाडा गया होता तो उन्हे विदित होता कि निष्कासित व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मतलब क्या है ? परन्तु खेद तो इस बात का है कि चतुराई के साथ 'बल्फोर डेक्लेरेशन' के आधीन साम्राज्यवादी राष्ट्रों ने अरब की धरती पर यहूदियों को इसलिए आबाद कर दिया कि ये लोग साम्राज्यवादियों के पिछलग्गू बने रहेंगे। यहूदी विश्व के किस कोने मे नही रहते

ग्रौर यदि हर देश में यहूदी यह माग करनी शुरु करदें कि उन्हें अलग 'होमलैंड' दिया जाए तो देशभक्तों की क्या प्रतिक्रिया होगी। खेद का विषय है कि फलस्तीन के स्वाल पर साम्राज्यवादी इसे विकृत रुप देते रहे हैं। भारत में यह प्रचार किया जाता रहा है कि 'ग्ररब' देश तो 'मुस्लिम देश' हैं हमें इनका समर्थन नहीं करना चाहिये'। इस ढग का प्रचार भ्रमात्मक है क्योकि हमारी नजरों में साम्राज्यवादी तो साम्राज्यवादी है—न वह हिन्दु है न मुसलमान, न वह यहूदी है न ईसाई—उसका काम तो केवल लोगों को ग्रापस मे लडना है। दो पडोसी राष्ट्र भिडने लगें तो साम्राज्यवादियों के चेहरे खिल उठते हैं क्योकि जग का सामान बिकेगा, मानवता का सौदा होगा, सभ्यता का दिवाला निकलेगा, बच्चे यतीम होगे, बहिनों का सिन्दूर गैन्दा जाएगा, माताग्रों की गोद खाली होगी, शोषण बढेगा, गरीबी का दौर-दौरा होगा, लोग भूख से विह्वल होंगे, बेरोजगारी बढेगी, ग्रार्थिक ढांचा ग्रस्त-व्यस्त होगा ग्रौर फिर चालाक दुकानदार की भाति ग्रमरीका दल-बल के साथ, डालर के ज़ोर पर उस देश में घुस जाएगा ग्रौर उसे कंगाल बना कर भिख मगों की कतार में हमेशा के लिए बिठा देगा।

प्रत्येक देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिनका काम प्रगतिशील नीतियों का विरोध करना है। भारत में भी ऐसे लोगों की यही मनोवृत्ति है कि सरकार की प्रगतिशील नीतियों का विरोध किया जाए। जब भारत में बैंकों का राष्ट्रीय-करणहुग्रा तो प्रतिक्रियावादी शक्तियो ने सरकार की खिल्ली उडाई ग्रौर जब राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तो इन लोगों ने ग्रदालत का दरवाज़ा भी खटखटाया। यह वही लोग हैं जो इन्दिरा गाधी को कम्युनिस्ट ग्रौर कृष्णा मेनन को साम्यवादियों का समर्थक कहते हैं ग्रौर जितने भी प्रगतिशील निदर्लीय व्यक्ति हैं उन्हे साम्यवाद का प्रशंसक ग्रौर युवा तुर्कों को साम्यवादी घुसपैठिया कहते हैं। जब जनता जायदाद पर सीमा लगाने की माग करती है तो ये लोग इस प्रकार झूठा प्रचार करते हैं कि जन साधारण के मन मे यह बात बिठा दी जाए कि जायदाद पर सीमा निर्धारित होने का मतलब होगा कि प्रत्येक साधारण व्यक्ति को भी अपनी मामूली जायदाद से हाथ धोना पड़ेगा।

इस प्रचार शैली के पीछे एकाधिपतियों, पूंजीपतियों ग्रौर निजि कारोबार के लिए विदेशी पूजी का सहयोग प्राप्त करने वालों का हाथ है ग्रौर इन सब के पीछे विद्यमान है—सी० ग्राई० ए०। सी० ग्राई० ए० एक फासिस्ट सस्था है ग्रौर यह शैक्षणिक संस्थाग्रों के माध्यम से लोगों मे मानसिक गुलामी के बीज ग्रारोपन करने

का काम भी करती है। सी० आई० ए० की किसी भी धर्म के प्रति निष्ठा नहीं है। अरब देशों में यह यहूदी का रूप धारण करती है और भारत-पाक महाद्वीप में मुसलमान का, दक्षिण अफ्रीका में यह गोरे का साथ देती है तो परतन्त्र अफ्रीकी देशों में काले का। यह मस्जिद भी गिरा सकती है और मन्दिर भी। इसका काम है लोगों में फूट डालना, लोगों के घर जलवाना, निरीह बच्चों को कत्ल करना, मानवता की हत्या करना।

सी० आई० ए० सर्व प्रथम किसी देश में फूट डालने का काम करती है और फिर 'एकता' लाने का और जब एकता के लिए वार्ता शुरु हो जाए तो उस वार्ता को विफल बनाने का काम भी करती है। जब इण्डियन नेशनल कांग्रेस गम्भीर स्थिति से गुजर रही थी तो सी० आई० ए० के दलाल संसदीय कार्यालय के बाहर चक्कर काट रहे थे। उनके लिए 'राजनैतिक कमाई' का सब से सुन्दर मौका था। सी० आई० ए० ने एक नया धन्धा भी शुरु कर रखा है। यह विदेशी सरकारों की दलाली का काम भी करती है चाहे 'कोयले की दलाली में मुंह काला क्यों न हो जाए'। यह बहाना बनाने में निपुण भी है और क्रियात्मक कार्यों की आड़ में धोके बाज़ी में चतुर भी।

जब जनता वर्तमान के प्रति चिन्तित होगी तो सी० आई० ए० वाले भूतकाल की बात करेंगे। लोग रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हों तो ये उनका मन बहलाने के लिए 'तोता और मैना की' कहानी सुनाएंगे। जनता की विद्रोही भावनाओं को कुण्ठित करने के लिए उन्हें नाच गाने के लिए आमन्त्रित करेंगे। इनकी यही इच्छा होगी कि लोग समाजवादी विचार धारा के समर्थक न बन कर 'उग्र राष्ट्रवादिता' के पुजारी बन जाएं ताकि धार्मिक भावनाओं को उद्वेलित करके उन्हें साम्प्रदायिकता की भट्टी में झोंका जा सके।

इनकी मित्रता किनसे है? जनता से—नहीं! परन्तु इनकी मित्रता है:—

क) भारतीय और विदेशी एकाधिपत्य वालों से।

ख) शोषकों से।

ग) फासिस्टों और उनकी संस्थाओं से।

ताकि लोग गरीबी से छुटकारा न पा सकें। उन्हें डर है कि जब देश आत्म-निर्भर हो जाएगा तो एकाधिकार की रक्षा नहीं की जा सकेगी। जनता अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सजग और जागरुक हो जाएगी।

यही कारण है कि एक ही थैली के चट्टे-बट्टे साम्राज्यवाद के साये में पलते रहते है। सी० आई० ए० के पास हर बिमारी का इलाज मौजूद है या यूँ कह लीजिए कि टोटके हैं, सब के सब एक दम पेटेंट :

क) यदि कोई व्यक्ति प्रगतिशील हो तो उसे साम्यवादी कहो या साम्यवाद का समर्थक या वाम पंथी।

ख) यदि लोग समाजवाद की बात करें तो उन्हें उग्र राष्ट्रवादिता के चक्र मे डाल दो।

ग) यदि मेहनतकश जनता अपने अधिकारों के लिए लड़े तो पूँजीपतियों की मदद करो।

घ) यदि बेरोजगार रोजगार की माग करें तो अपने कारखानों को ताले लगा दो।

ङ) यदि बोनस का प्रश्न उठे तो कारखाने मे ताला बन्दी करके स्वयं वहाँ से चले जाओ।

सी० आई० ए० को विश्वास है कि उसे निम्नलिखित लोगों से सहायता मिल सकती है :

क) लाल फीताशाही से।
ख) नौजवानों से।
ग) राजनैतिक गुटों से।
घ) विद्यार्थियों से।
ङ) वैज्ञानिकों से।

सरकारी भेद को प्राप्त करने के लिए, उत्तेजना फैलाने के लिए, प्रजातांत्रिक सरकारों का तख्ता उलटने के लिए, षड्यन्त्र की भूमिका तैयार करने के लिए सी० आई० ए० उपयोगी सूचना प्राप्त करने का भी काम करती है ताकि उसे प्रयोग में लाया जा सके :—

क) व्यवसायिक राज़ बेचने के लिए।

ख) सैनिक क्षेत्रों से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त करने के लिए।

ग) तस्करी के लिए।

श्रौर श्रपने इस कारोबार को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित ढग श्रपनाए जाते हैं :—

क) श्रार्थिक हस्तक्षेप द्वारा।

ख) राजनैतिक घुस पैठ द्वारा।

ग) धार्मिक भावनाश्रों को उद्वेलित करके।

जिस प्रकार मृत्यु का निवास-स्थान युद्ध, विष श्रौर बिमारी है उसी प्रकार सी० श्राई० ए० विध्वसक कार्यवाहियो की गोद में पलता है इसलिए इस घुस पैठ को रोकने के लिए सब राजनैतिक श्रौर सामाजिक दरवाजे वन्द होने चाहिएं।

श्रमरीकी लोग, श्राम तौर पर, सी० श्राई० ए० की गतिविधियो के कट्टर विरोधी हैं। सी० श्राई० ए० तो श्रपने देश श्रमरीका की भी वफादार नही है इसे श्रपने देश में श्रछूत समझा जाता है। भला कौन सजग व्यक्ति चोरो श्रौर लुटेरो का साथ देगा। ये लोग साम्राज्यवाद-विरोधी देशों को बदनाम करने पर तुले हुए है।

श्रधिकांश श्रमरीकी लोग सयुक्त राज्य श्रमरीका की विदेश नीति के कट्टर विरोधी हैं। इन लोगों को विश्वास है कि सी० श्राई० ए० ने ही दुनियां मे श्रमरीका का हुलिया बिगाड़ रखा है श्रौर श्राजका श्रमरीका जनता का हितैषी नही बल्कि उनका शत्रु है। साम्राज्यवादी श्रमरीका श्रब्राहीम लिंकन श्रौर जेफरसन को भूल चुका है। जो कुछ इन महान विभूतियों ने श्रमरीका के लिए किया, उन्ही की सन्तान ने उस पर कालिख पोत दी। जेफ़रसन श्राजादी के लिए लड़े, लिंकन रंग-भेद के खिलाफ लड़े परन्तु श्रमरीका रंग-भेद नीति का समर्थन करने वाले दक्षिण रोडेशिया का भी मित्र है श्रौर दक्षिण श्रफीका का भी, इसकी मित्रता पुर्तगाल श्रौर ग्रीस की तानाशाही सरकारो से भी है जिन्होने श्रंगोला, मोजाम्बिक श्रौर गिनी बिसाऊ में श्राजादी का दमन कर रखा है। यह गरीबी से सताए हुए छोटे-छोटे राष्ट्रों पर श्राक्रमण भी कराता है श्रौर श्रर्घ-विकसित देशों में श्रार्थिक शोषण के बीज भी बोता है ताकि साम्राज्यवादी हृत्थकण्डों को सफल बनाया जा सके।

यह असम्भव है कि कोई भी व्यक्ति जो खुफिया विभाग में काम करता हो वह अपना सम्पर्क इस विभाग के साथ दिखाने का एलान करता रहे। खुफिया काम तो खुफिया ढंग से किए जाते हैं और वे लोग जो यह कार्य करते हैं उनका रंग-ढंग बदल नही जाता, केवल वे लोग पैसे के लालच में अपना ईमान बेच देते हैं क्योंकि उन लोगों को पता है कि जो काम वह कर रहे हैं वह उनके अपने देश के लिए अहितकर है। खुफिया विभाग तो देश की रक्षा के लिए बनाया जाता है और जो खुफ़िया विभाग विदेशी सत्ता के इशारे पर काम करता हो वह निश्चय ही निन्दनीय है। अतः यह जनता का कर्त्तव्य है कि ऐसे लोगो से और उनकी संस्थाओं से सतर्क रहें तथा उनकी षडयन्त्रकारी गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखें। यह प्रजातन्त्र के साथ बहुत बड़ा मजाक होगा यदि हम विध्वसकारी, आतंकवादी और हिंसात्मक कार्यवाहियों को बढ़ावा देने वाली राष्ट्र-विरोधी संस्थाओं को पनपने दें। किसी भी देश को अपनी आज़ादी की सुरक्षा का पूर्ण अधिकार है इसलिए कोई भी देश अपने आस्तीन मे साप नही पाल सकता। साम्राज्यवाद का पिछलग्गू सी० आई० ए० भी एक विषैला साप है जो नृशंसात्मक कार्यवाहियों के लिए बदनाम है।

आज़ादी का यह मतलब नही कि कुछ लोगों को अधिकार है कि वे इसका गलत इस्तेमाल करते हुए आज़ादी का हनन करना शुरु करदें। इस प्रकार की आज़ादी पर सरकार को भी रोक लगानी चाहिए और यदि सरकार इतना कड़ा कदम उठाने में असमर्थ हो तो जनता को चाहिए कि राष्ट्र-विरोधी तत्वों के मुंह में लगाम दे। इससे पहले कि षडयन्त्रकारी गतिविधियां विकराल रूप धारण कर लें, प्रत्येक देश वासी को इस बात का निश्चय करना चाहिए कि वे लोग जो आज़ादी का दमन करने का प्रयास करते हैं उनके साथ लोहा लिया जाएगा।

यदि प्रजातन्त्र को धक्का लगता है तो आज़ादी को ठेस लगती है। इसलिए हम प्रजातन्त्र प्रणाली के प्रशंसक ही नही उसको क्रियान्वित भी कर रहे है और हम नही चाहते कि स्वावलम्बी राष्ट्र आर्थिक गुलामी की जजीरों में जकड़ दिए जाएं नही तो हमारी अवस्था उस चिकित्सक के समान होगी जो कहेगा "आपरेशन तो कामयाब रहा परन्तु रोगी की मृत्यु हो गई।"

अन्त में हम उन लोगों से अनुरोध करते हैं, उनकी कार्य करने की शक्ति को आह्वान देते हैं, उनकी आज़ादी, प्रजातन्त्र और शान्ति के प्रति भावनाओं को चुनौती

देते हैं, कि वे सजग और जागरुक रहें क्योंकि सी० आई० ए० का अस्तित्व ि में आजादी के लिए खतरा है।

सी० आई० ए० की कुख्यात गतिविधियों की चर्चा करते हुए पाकिस्तान के भूतपूर्व राष्ट्रपति अय्यूब खा ने आरोप लगाया है कि उसकी सरकार का तख्ता उल्टने में सी० आई० ए० का हाथ था। 'सुबह का भूला शाम को घर लौट आए' तो उसे भूला हुआ नहीं कहना चाहिए। अच्छा है कि अय्यूब खां जल्दी समझ गए। पाकिस्तान में प्रजातन्त्र की हत्या के पीछे भी षडयन्त्रकारी भावना काम कर रही थी परन्तु उस समय शासक वर्ग 'मिट्टी के माधो' बनकर सारा तमाशा अपनी आखो से देखते रहे। पाकिस्तान मे अब भी फौजी शासन है और इसमें कोई सन्देह नही कि पाकिस्तान को अमरीकी साम्राज्यवादी भी इस्तेमाल करेंगे और चीनी विस्तार-वादी भी। सी० आई० ए० के पर्दे के पीछे कौन किसके साथ गठ बन्धन करता है इसके प्रति सजग रहना आवश्यक है। एशिया और अफ्रीका की धरती उपद्रवो और उत्पातों से मुक्त रहे इसके लिए आवश्यक है कि सी० आई० ए० के चेहरे पर पड़ा हुआ नकली नकाब उतरता रहे। उसमे आप सब का सहयोग अनिवार्य है।

सी० आई० ए० आजादी की शत्रु है। इसका जनाजा उस स्थान पर जाकर दफ़ना दो जहां इसकी मौत पर आसू बहाने वाला कोई न हो।